खण्ड-06 सत्र -05 (भाग-03) / अंक-50

बुधवार 31 मई, 2017 / 10 ज्येष्ठ, 1939 (शक)

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्यमेव जयते

छठी विधान सभा

पांचवां सत्र

अधिकृत विवरण

(सत्र-05 (भाग-02) में अंक 50 सम्मिलित है)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

सम्पादक वर्ग

EDITORIAL BOARD

प्रसन्ना कुमार सूर्यदेवरा

सचिव

PRASANNA KUMAR SURYADEVARA

Secretary

एम.एस. रावत

उप-सचिव (सम्पादन)

M.S. RAWAT

Deputy Secretary (Editing)

विषय सूची

सत्र - 5 भाग (3) बुधवार, 31 मई, 2017/10 ज्येष्ठ, 1938 (शक) अंक - 50

क्र.सं.		विषय
1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	1-2
2.	अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था	4-12
3.	नवनियुक्त मंत्रियों का परिचय	12-15
4.	प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण	15-52
5.	प्रस्ताव (नियम-114)	53-86
6.	विधेयक का पुर:स्थापन, विचार एवं पारण	87-90
7.	प्रतिवेदन पर सहमति	90-166

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र - 5 भाग (3) बुधवार, 31 मई, 2017/10 ज्येष्ठ, 1939 (शक) अंक - 50

दिल्ली विधान सभा

सदन अपराह्न 2:00 बजे समवेत हुआ।

सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची:

1 श्री शरद कुमार
2 श्री संजीव झा
3 श्री पंकज पुष्कर
4 श्री पवन कुमार शर्मा
5 श्री अजेश यादव
6 श्री महेंद्र गोयल
7 श्री वेद प्रकाश
8 श्री सुखवीर सिंह दलाल
9 श्री ऋतुराज गोविंद
10 श्री रघुविन्द्र शौकीन
11 श्रीमती बंदना कुमारी
12 श्री जितेंद्र सिंह तोमर
13 श्री राजेश गुप्ता
14 श्री अखिलेश पति त्रिपाठी
15 श्री सोमदत्त
16 सुश्री अलका लाम्बा
17 श्री आसिम अहमद खान
18 श्री विशेष रवि
19 श्री हजारी लाल चौहान
20 श्री गिरीश सोनी

21 श्री जरनैल सिंह (तिलक नगर)
22 श्री राजेश ऋषि
23 श्री महेंद्र यादव
24 कर्नल देवेंद्र सहरावत
25 श्री सुरेंद्र सिंह
26 श्री विजेंद्र गर्ग
27 श्री प्रवीण कुमार
28 श्री सोमनाथ भारती
29 श्रीमती प्रमिला टोकस
30 श्री नरेश यादव
31 श्री करतार सिंह तंवर
32 श्री अजय दत्त
33 श्री दिनेश मोहनिया
34 सरदार अवतार सिंह कालकाजी
35 श्री सही राम
36 श्री नारायण दत्त शर्मा
37 श्री अमानतुल्लाह खान
38 श्री राजू धिांगान
39 श्री मनोज कुमार
40 श्री नितिन त्यागी
41 श्री एस. के. बग्गा
42 श्री अनिल कुमार बाजपेयी
43 श्री राजेंद्र पाल गौतम
44 श्रीमीत सरिता सिंह
45 मो. इशराक
46 श्री श्रीदत्त शर्मा
47 चौ. फतेह सिंह
48 श्री जगदीश प्रधान

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र - 5 भाग (3) बुधवार, 31 मई, 2017/10 ज्येष्ठ, 1939 (शक) अंक - 50

सदन अपराह्न 2.05 बजे समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय **(श्री रामनिवास गोयल)** *पीठासीन हुए।*

(राष्ट्रीय गीत-वन्दे मातरम्)

अध्यक्ष महोदय : दिल्ली विधान सभा के पांचवें सत्र के तीसरे भाग में मैं आप सब का हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप शालीनतापूर्वक सदन की कार्यवाही में भाग लेंगे तथा कार्यवाही के सुचारू रूप से संचालन में मुझे पूरा सहयोग देंगे।

निधन संबंधी उल्लेख

माननीय सदस्यगण, आपको यह जानकर अत्यंत दु:ख होगा कि दिनांक 22 अप्रैल, 2017 को दिल्ली विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री रामपाल कराहना का देहांत हो गया। वे वर्ष 1993 से 1998 तक प्रथम दिल्ली विधान सभा के सदस्य रहे और करावल नगर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। राजनीति में आने से पहले वे भारतीय सेना में कार्यरत थे। वर्ष 1989 में उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया तथा अनेक राजनैतिक तथा सामाजिक संगठनों के सदस्य रहे और करावल

नगर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। उन्होंने विधान सभा सदस्य के रूप में सजगतापूर्वक अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन किया तथा अपने क्षेत्र की जन–समस्याओं को सदन में सक्रियता से उठाया।

मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से श्री रामपाल करहाना जी के निधन पर हार्दिक शोक संवेदना करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार वालों को इस दु:ख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

अब दिवंगत आत्मा के सम्मान में सदन द्वारा दो मिनट का मौन धारण किया जायेगा।

(सदन द्वारा दो मिनट का मौन धारण।)

अध्यक्ष महोदया : ऊँ शांति, शांति, शांति।

अध्यक्ष महोदय :आज माननीय सदस्य श्री जगदीप सिंह जी, चीफ व्हिप, का जन्म दिन है। मैं इस अवसर पर उनको अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से हार्दिक बधाई देता हूं तथा कामना करता हूं कि वे अपने व्यक्तिगत तथा राजनीतिक जीवन में नई ऊंचाइयां प्राप्त करें। 4.00 बजे इनकी ओर से जलपान की भी व्यवस्था रहेगी।

माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था

अध्यक्ष महोदय : समिति के प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं माफी चाहूँगा, पहले क्वेशचन ऑवर खत्म, फिर 280 खत्म अब ध्यानाकर्षण पर भी कोई ध्यान नहीं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, बिल्कुल ध्यान है।

मुझे श्री विजेन्द्र गुप्ता जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष तथा श्री मनजिन्दर सिंह सिरसा जी माननीय सदस्य से नियम-54 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तथा नियम-55 के अंतर्गत अल्पकालिक चर्चा की सूचनाएं प्राप्त हुई। सदन की ये बैठक 'दिल्ली माल और सेवा कर विधेयक' पर विचार करने के लिए बुलाई गई है। अत: आज कार्यसूची में दर्शाये गये विषयों के अतिरिक्त... देखिये, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, इसके अतिरिक्त किसी भी विषय पर विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए उक्त सूचनाओं को मैं अस्वीकार करता हूं, कोई बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जो दिल्ली की जनता से सीधे जुड़ा है, आज की समस्या को लेकर, जो आपके नोटिस आए हैं, ऐसा कुछ उसमें नहीं मुझे दिखाई दिया तो इसलिए मैं इन दोनों को अस्वीकार कर रहा हूं।

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ता : नहीं, तो आपके लिए ये महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है?

...(मुद्दा)

अध्यक्ष महोदय : रहीं, उतना, मैंने ये कहा कि कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं है। विजेन्द्र जी,देखिये।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : हर मुद्दा एक एजेण्डा होता है। जीएसटी का अपना एक एजेण्डा है, आप एक दिन कराइये, दो दिन कराइये लेकिन आप जब क्वेशचन ऑवर करेंगे और इतने महत्वपूर्ण मुद्दे, दिल्ली में लोगों को दवाई नहीं मिल रही अस्पताल में, खुद मुख्यमंत्री जी ने इस बात को माना है तो सदन

के अंदर आप कोई बयान नहीं देंगे, सदन में आप कोई बात नहीं, करेंगे, तो फिर कब चर्चा होगी और कहां होगी ये चर्चा?

अध्यक्ष महोदय : नहीं, विजेन्द्र जी, मैंने इस पर व्यवस्था दी है। अपना ये विशेष सत्र बुलाया गया है जो नियमित सत्र होते हैं उनमें...

श्री विजेन्द्र गुप्ता : रूल बुक में कोई विशेष सत्र का, कोई आप मुझे उसकी डेफिनेशन दिखा दीजिए विशेष सत्र क्या होता है? सत्र को आप विशेष सत्र कहकर बार-बार, आप मुझे डिफाइन कर दीजिए, मैं बैठ जाऊंगा कि क्या कोई विशेष सत्र ऐसा होता है जिसमें कोई चर्चा नहीं होगी?

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, आप मेरी बात को समझ लीजिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, मैं विद डयू ऑल रिगार्ड्स, मैं इतना कहना चाहता हूं....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने दोनों बातें की, अब नियम में दिखा दीजिए। मैं दोनों बातों का उत्तर दे रहा हूं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : आप मुझे विशेष सत्र दिखा दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : पहली बात तो नियम में विशेष सत्र बुलाने के लिए सरकार जब चाहे सत्र बुला सकती है। एक दिन का बुलाए...

श्री विजेन्द्र गुप्ता : सवाल ये नहीं है, सत्र बुलाना। सत्र शब्द कोई विशेष शब्द नहीं होता।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, ये नियमित सत्र हैं, चलिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : सत्र, सत्र होता है और सत्र की वही परिभाषा होती है जो होनी चाहिए लेकिन आज आप दवाइयों पर बात नहीं करने देंगे, आप पानी पर बात नहीं करने देंगे।...

अध्यक्ष महोदय : अब श्री अरविंद केजरीवाल जी, माननीय मुख्यमंत्री, नवनियुक्त मंत्रियों का सदन को परिचय देंगे।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : सरकार ने घोषणा की थी 4 जनवरी, 2016 को कि मुफ्त दवाइयां मिलेंगी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसमें मैंने अपनी व्यवस्था दे दी है। फिर आप अपनी वही बात कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : ये तो पक्का ही पता होता है कि इस दिल्ली के लिए कोई न कोई जरूरी चीज तो है, हम तो ये कह ही नहीं रहे।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैंने तो ये कहा ही नहीं, जो कोई इस नियम के अंतर्गत।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : अध्यक्ष जी, जब भी सत्र बुलाया जाएगा, चर्चा तो कराई जाएगी और जो बाकी नियम बनाए गए हैं चाहे 55, 54 के

तहत बनाया गया है, चाहे क्वेश्चन...

अध्यक्ष महोदय : दो मिनट, अभी बैठिये मैंने व्यवस्था दे दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिये, माननीय मुख्यमंत्री जी....सिरसा जी, विजेन्द्र जी, बैठिये प्लीज, विजेन्द्र जी, बैठिये प्लीज।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : ...(व्यवधान)... तो दिल्ली का मुद्दा डिस्कस करोगे?

अध्यक्ष महोदय : नहीं, दिल्ली का मुद्दा ही डिस्कस होगा। भई, ये दिल्ली का मुद्दा ही डिस्कस कर रहे हैं।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : तो हम ये ही कह रहे हैं इसके साथ पीने का पानी...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जीएसटी का मुद्दा ही डिस्कस कर रहे हैं।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : ....किसी को ऐतराज नहीं है, चाहे एक घंटा फालतू बैठना पड़े, हम रात तक बैठने को तैयार हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय मुख्यमंत्री जी, नवनियुक्त...देखिये, दो मिनट बैठिये। सिरसा जी दो मिनट बैठिये। माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों...भई विजेन्द्र जी,

मैं जो कह रहा हूं एक बार उसको आप सुनने का प्रयास नहीं कर रहे हैं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : आपने खुद कहा है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा, हां, मैंने कहा, कोई अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : आपने खुद कहा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हां, तो उतना नहीं है ये, वैसा नहीं है ये। अभी आ रहा है। हां, हो रहा है वो।

...(व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : दवाई के बिना जब लोग मरेंगे...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री अरविंद केजरीवाल जी। भई एक बार देखिये सिरसा जी, दो मिनट सुन लीजिए। मैं बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहा हूं। दो मिनट रूक जाइये, दो मिनट रूक जाइये जरा। देखिये, सिरसा जी, सिरसा जी, जिस दिन आप सदस्य बने थे, सारा काम रोक कर के मैंने पहले आपका इंट्रोडक्शन दिया। अब मैं बोल रहा हूं, उसको आप सुन नहीं रहे। नहीं, आपका

परिचय सदन में आपके लिए उस दिन किया। आज दो मंत्री नियुक्त हुए हैं। नहीं, आपका परिचय सदन में आपके लिए उस दिन किया। आज दो मंत्री नियुक्त हुए हैं। आप चुनके आए थे, आपका अभिनंदन करवाया। दो मंत्री नियुक्त हुए हैं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : हां, तो उनका परिचय करवाइये।

अध्यक्ष महोदय : मैं बोल रहा हूं उनका परिचय मैं करवा रहा हूं, उसको आप रोक रहे हैं, उसको आप करने नहीं देर हे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नितिन जी, बैठिये। देखिये आप तीनों बोल रहे हैं, तो कोई बात समझ में नहीं आती। या तो वन बाई वन बोलें। मैं इनको भी रोक रहा हूं।

सुश्री भावना गौड : अध्यक्ष महोदय, ये हाउस मैं ही आकर के बोलते हैं। हाउस से बाहर इनको पता ही नहीं होता कि दिल्ली की समस्याएं क्या हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उसे मिनट रूकिए जरा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे एक बार ये विषय पूरा करने दें जिसे मैं बोल चुका

हूं। दो मिनट रूकिए। जरा। आश्वासन देना है, नहीं देना है, इसको मैं देखूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सिरसा जी, दो मिनट बैठिए प्लीज।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं मैं फैसला दे चुका हूं। अगर आप फैसले की बात करते हैं, मैं फैसला दे चुका हूं। मैं एक बार, मैं जो ये कह चुका हूं एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं मैं निणर्वय दे चुका हूं। मैंने कहा अस्वीकार किया।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक सेकेण्ड, जो मैं कह चुका हूं एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिये विजेन्द्र जी, ऐसा नहीं। मंत्रियों का एक बार परिचय एक बार मैं कह चुका हूं, पहले एक बार उसको पूरा करने दीजिए। फिर उसके बाद मैं विचार करता हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, देखिए ऐसा एडामैन्ट होकर काम नहीं चलता।. ..नहीं, आप तो सारी बातों को चैलेंज करते हैं। सिरसा जी, मैं सुन रहा हूं। आप भी तो थोड़ा संयम रखिए प्लीज। एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी को दोनों का परिचय करवाने दो प्लीज।

माननीय मुख्यमंत्री जी, श्री अरविंद केजरीवाल जी।

...(व्यवधान)

नये मंत्रियों का परिचय

मुख्यमंत्री (श्री अरविंद केजरीवाल) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज मुझे ये बड़ी खुशी है पूरे सदन के सामने दो नये मंत्रियों को प्रस्तुत करने में।

श्री कैलाश गहलोत जी जो कि नजफगढ़ से विधायक हैं, उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है और वो Law & Justice, Transport, Administrative Reforms और Information Technology का प्रभार संभालेंगे। हम उनको शुभकामनाए देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो खूब सफल हों

राजेन्द्रपाल गौतम जी, जो कि सीमापुरी विधानसभा से विधायक है, वो Tourism, Art Culture & Lnguages, Gurudwara elections, Water, SCS & ST और Social Welfare का प्रभार संभालेंगे। उनको भी ढ़ेर सारी शुभकामनायें और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि वो जनता की खूब सेवा करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैं अपनी और से तथा पूरे सदन की ओर से दोनों माननीय

सदस्यों को मंत्री बनने पर हार्दिक शुभकामनायें देता हूं तथा आशा करता हूं कि मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का बहुत अच्छी तरह से पालन करेंगे।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : अध्यक्ष जी, हमें बधाई देने का मौका तो दो।

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिये सिरसा जी, बैठिये दो मिनट अगर बधाई तक सीमित रहना है, तो दीजिये। बधाई की आड़ में कुछ और करेंगे, विजेन्द्र जी की आदत है, विजेन्द्र जी की आदत है, मैं बहुत क्लीयरली बोल रहा हूं। बधाई दीजिये, मुझे दिक्कत नहीं है। एक सदस्य दीजिये।

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ता : सिरसा जी करेंगे कि जगदीश जी करेंगे कि मैं करूंगा?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, ऐसा नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसी बात आप पर कंट्रोवर्सी हो रही है सिरसा जी खड़े हुए हैं, उन्होंने कहा है कि बधाई हमको देने दीजिये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : लेकिन परिपाटी आप तोड़ रहे हैं विजेन्द्र जी। परिपार्टी

आप तोड़ रहे हैं। सिरसा जी खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष जी, हमें बधाई तो देने दीजिये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं बड़ा लाइट वातावरण कर रहा हूं, बहुत प्यार से शांति से। बधाई की जो लाईन पढ़ी जाती है, वो पढ़ दीजिये।

सुश्री राखी बिड़ला : अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, अरे! गुप्ता जी, हमारी भी सुन लीजिये।

अध्यक्ष महोदय : चलिये दीजिये, दीजिये। बधाई देने दीजिये।

सुश्री राखी बिड़ला : अध्यक्ष जी, हमारी भी सुन लिया कीजिये। मेरी सुनिये, मेरा प्रस्ताव है कि गुप्ता जी को हटाकर सिरसा जी को नेता विपक्ष बनाया जाये। सब सर्वसम्मति से मतदान करो।

...(व्यवधान)

सुश्री राखी बिड़ला : हां पक्ष जीत गया, गुप्ता जी हटे हैं, सिरसा जी को हम नेता विपक्ष बनाने का प्रस्ताव रख रहे हें। ठीक है तो अध्यक्ष जी, ये हमारा प्रस्ताव है।

...(व्यवधान)

सुश्री राखी बिड़ला : पूरे सदन का प्रस्ताव है और इस प्रस्ताव को गंभीरता से लिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : हां, विजेन्द्र जी, चलिये।

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, सदन में मुख्यमंत्री जी द्वारा दो माननीय सदस्यों को मंत्री पद ग्रहण करने पर यहां पर उनका परिचय कराया गया है, मैं अपनी और से और अपने दल की ओर से दोनों माननीय सदस्यों को, जो मंत्री के रूप में इस सदन में उपस्थित हैं; राजेन्द्र गौतम जी और गहलोत जी, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं।

अध्यक्ष महोदय : बहुत बहुत धन्यवाद।

प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण

समिति के प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण सुश्री राखी बिड़ला जी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हां, मनीष जी क्या कहना चाहते हैं? माननीय उप मुख्य मंत्री जी। हां, बोलिये।

उप मुख्य मंत्री (श्री मनीष सिसोदिया) : मैं ये कह रहा था अध्यक्ष जी कि माननीय नेता प्रतिपक्ष जिस मुद्दे को ले के यहां सदन में चिंता दिखा रहे हैं, मैं सदन को और सदन के माध्यम से पूरी दिल्ली को आश्वस्त करना चाहता हूं कि शिक्षा और स्वास्थ्य दिल्ली सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकताएं हैं और इसको हम बार-बार यहां कहते भी रहे हैं। जहां तक दवाइयों की वर्तमान स्थिति का सवाल है, निश्चित रूप से....

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, बात तो दवाइयों की कमी की है।

उप मुख्य मंत्री : आपकी बात से पहले मैं रख देता हूं। आपके सवाल तो हमें पता है, कहां से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं और क्या हैं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : कहां से आ रहे हैं?

उप मुख्य मंत्री : हां, अस्पतालों से आ रहे हैं...

...(व्यवधान)

उप मुख्य मंत्री : अच्छा, आपके सवाल अस्पतालों से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे?

...(व्यवधान)

उप मुख्य मंत्री : आपके सवाल अस्पतालों में दवाइयों से जुड़े हुए हैं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : लोग बता रहे हैं, वो हम आपको बता रहे हैं।

...(व्यवधान)

उप मुख्यमंत्री : हम भी तो कह रहे हैं।

...(व्यवधान)

उप मुख्य मंत्री : मैंने कब कहा, कहीं और से आ रहे हैं। मैं भी तो यही कह रहा हूं, कहां से आ रहे हैं।

...(व्यवधान)

उप मुख्य मंत्री : माननीय मुख्यमंत्री जी सारी स्थिति का ले के पहले ही काफी चिंतित हैं और जिस तरह की सूचनायें दवाइयों को...

...(व्यवधान)

(श्री कपिल मिश्रा बैनर लेकर सदन के वेल में आए)

अध्यक्ष महोदय : भई, ऐसा नहीं चलेगा। अब आप बैठ जाइए कपिल जी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप नीचे बैठ जाइये। आपको समझ में आना चाहिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप नीचे बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय उप मुख्य मंत्री बोल रहे है, बैठ जाइये नीचे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ये कपिल जी, इस तरह स्लोगन लाना...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं वार्निंग दे रहा हूं। आपको इस तरह के स्लोगन सदन में लाना...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ये सदन का बहुत बडा अपमान है। बैठ जाइये। आप नीचे बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बंद करिये इसको। मैं वार्निंग दे रहा हूं। आप बंद करिये इसको। कपिल जी, मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं, इसको बंद करिये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मार्शलस कपिल मिश्रा को बाहर करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बाहर करें इनको सदन से। बाहर करें सदन से इसको। नहीं, ये कोई सदन की मर्यादा है!

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ये कोई तरीका है! ये कोई तरीका है! नहीं, ये तरीका नहीं है। न, बिल्कुल नहीं, ये कोई तरीका नहीं है। ले जाइये बाहर उठाकर। बाहर ले जायें।

...(व्यवधान)

(श्री कपिल मिश्रा को मार्शल्स द्वारा सदन से बाहर किया गया)

अध्यक्ष महोदय : कोई मारपीट नहीं हो रही।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कोई मारपीट नहीं हो रही, किसी तरह की मारपीट नहीं हो रही है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सिरसा जी, आप बैठिये। सब माननीय सदस्य बैठें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : भई विजेन्द्र जी, ऐसा नहीं चल पायेगा। ऐसे नहीं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसे नहीं चल पाएगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सिरसा जी, बैठिये। जगदीश जी, बैठिये। देखिये, मैं सिरसा जी को विजेन्द्र गुप्ता जी को विशेष रूप से ध्यान दिलाना चाहता हूं। पिछले दिनों लोकसभा में इस ढंग से कुछ सदस्य स्लोगन लेकर आये थे। सुन लीजिये बात को पूरा और लोकसभा अध्यक्षा ने क्या डायरेक्शनस दी थी, उसको संज्ञान में ले लीजिये। नहीं, मानते नहीं हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक सैकिण्ड, सिरसा जी, ये बहुत दिक्कत है। ये बहुत बड़ी दिक्कत है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप अध्यक्ष को हाईजैक करना चाह रहे हैं। आप बात करने नहीं दे रहे मुझे। आप मुझको अलाउ नहीं कर रहे। पूरी बात करने से पहले, नहीं, ऐसा नहीं। मुझे पहले पूरी बात करने दीजिये। मुझे पहले पूरी बात करने दीजिये। मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, मुझे पहले पूरी बात करने दीजिये। नहीं, विजेन्द्र जी, बैठिये। नहीं, पहले बैठिये। दो मिनट बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, बैठ जाइये। ऐसे नहीं चल पायेगा। नहीं, मुझे पूरी बात करने दीजिये।

उप मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो दवाइयों वाला मुद्दा है, मैं उस पर अपनी बात रख रहा था और दवाइयां...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, अब क्या बात पूरी करेंगे आप? बोलने नहीं दे रहे। नहीं, सिरसा जी, ठीक नहीं है।

...(व्यवधान)

उप मुख्य मंत्री : अरे! आपके लिये दवाइयों की व्यवस्था करवा रहे हैं। दवाइयों की बात कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, कोई हाथापाई नहीं हुई।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, कोई हाथापाई नहीं हुई।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

उप मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, दवाइयों के विषय में मुझे ये कहना है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने खुद इस पर संज्ञान लिया था। गड़बड़ी की सूचना मिल रही थी। माननीय मुख्य मंत्री जी ने खुद इस पर संज्ञान लिया था और उन्होंने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को आदेश दिये हैं कि वो जाकर पर्सनली हॉस्पिटलस को विजिट करेंगे और वहां पर मैडिसिन्स हैं या नहीं हैं, ये सुनिश्चित करेंगे और अगर वहां दइवायों की कमी पाई जाती है तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने आदेश दिये हैं कि चीफ सैक्रेट्री रिस्पोन्सिबिल ठहराये जायेंगे इस चीज के लिये। दूसरा, मैन्युपुलेट सप्लाई ऑफ मेडिसिन्स और जितनी भी उसके लिये जो भी अधिकारी नीचे स्वास्थ्य विभाग में या कहीं में कोई जिम्मेदार है, रिस्पोन्सीबिल्टी फिक्स की जायेगी कि अगर सभी अस्पतालों में दवाइयां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं तो वहां अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जायेगी, उनके ऊपर कार्रवाई की जायेगी। ये पहले ही निर्देश मुखमंत्री जी दे चुके हैं और उस पर कार्रवाई हो रही है।

तीसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने दौरा किया था कुछ अस्पतालों का। वहां पर सूचनाएं भी मिली हैं। अलग-अलग अस्पतालों में दवाइयों में कुछ कमी थी, इसकी एक वजह जो सामने आई है अभी तक जो मेडिसिन्स स्पलायर्स हैं, उनको पेमेंटस में करप्शन हो रहा था। कुछ गड़बड़ियां थीं, उसकी जांच के माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिये हैं और ये निर्देश दिये हैं कि एक

तय समय सीमा, क्योंकि दवाइयां बहुत एसंशियल हैं, दवाइयां अस्पताल में होनी चाहिए। अगर दवाइयां अस्पताल में नहीं मिलती हैं, इसलिये नहीं मिलती हैं क्योंकि किसी स्पलायर को पैमेंट नहीं हुआ, तो जिन लोगों की वजह से... स्वास्थ्य विभाग को कहा गया है कि एक पूरा खाका बनाया जाये कि मैक्सिमम कितने समय में पेमेंट हो जायेगा और अगर पेमेंट नहीं हुआ, तय समय सीमा में पेमेंट नहीं हुआ तो वो पेमेंट या उस पर जो ब्याज सहित दिया जाएगा कंपनियों को और वो ब्याज और उसके ऊपर जुर्माना अधिकारियों की तनख्वाह में से काटा जायेगा, जो अधिकारी रिस्पोंन्सिबिल हैं इस चीज के लिये। ये व्यवस्था पहले ही की गई है और इसको जैसे जैसे अमल में लाते रहेंगे, हमें उम्मीद है कि अस्पतालों की स्थिति, दवाइयों की स्थिति और ठीक होगी।

सुश्री अलका लाम्बा : अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान एक गंभीर मामले की तरफ ले जाना चाहती हूं। ये कानून व्यवस्था...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक सैकेंड अलका जी, अलका जी, एक सैकेंड बैठिये। अब क्या रह गया, विषय हो गया न पूरा?

श्री विजेन्द्र गुप्ता : कहां से हो गया? मैंने बोला नहीं और हो गया विषय पूरा! सवाल हम खड़ा कर रहे हैं। जवाब आ रहा है, बिना सवाल के।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आपका प्रश्न तो यही था।

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ता : देखिए, मुझे अपनी बात कहने दीजए। इतना ये सदन क्यों घबराता है, हमारे बोलने से?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब विजेन्द्र जी, ऐसे नहीं, आपकी पूरी बात हो गई। पूरा विषय हो गया, पूरा विषय आपने बिना परमिशन के रख दिया।

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ता : आप हमें इजाजत ही नहीं दे रहे बोलने की। सवाल हमारे हैं और जवाब आप...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने पूरा विषय रख लिया, बिना बोले रख लिया।

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ता : कहां रखा मैंने, अभी तो शुरू ही नहीं किया।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या बात कर रहे हैं? अब बैठिए प्लीज।

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ता : मैंने इतना कहा अस्पतालों के मामले में, दवाइयों के मामले में हमने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया अध्यक्ष जी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिए, विजेन्द्र जी, आपका लिखित में मेरे पास है। लिखित में मेरे पास है आपका।

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ता : लिखित में दिया है न मैंने।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हां, लिखित में, इसमें जो चार लाइनें हुई हें, वो बोल चुके हैं आप उसको।

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, वो विषय दिया जाता है ध्यानाकर्षण में। ध्यानाकर्षण में ये कोई, वो थोड़ी न है विषय। ये तो बताना पड़ेगा मेरे को।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ये हो चुका है, अब हो चुका है, इसको बैठिये प्लीज।

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ता : ये 280 नहीं है....

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जीएसटी आप लोगों का विषय है या नहीं है? आप जीएसटी को पास नहीं करवाना चाहते?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने भाषण देना है पूरा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सिरसा जी, वो पहले ही बोल चुके हैं। बिना इजाजत के वो बोल चुके हैं सारा विषय।

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ता : मैं बोला कब हूं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, सिरसा जी, उनको रखना है, वो रखें। आप मत बीच में करिए प्लीज। आप बैठ जाइय।

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी,

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : चलिए, रखिए, आप जल्दी रखिए, जल्दी रखिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हां, दो मिनट में रखिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सिरसा जी, दो मिनट बैठिए अब।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अभी दो मिनट बैठिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : विषय हो गया ना, विषय रखिए आप। अब दो मिनट बोल दीजिए आप।

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ता : तो विषय हो कब गया?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हां, बोलिए न आप।

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ता : आपने 54 एक्सेप्ट किया है न?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब बोलिए ना, बोलिए दो मिनट का समय दिया है मैंने, बोलिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : दो मिनट रूको जरा। दो मिनट रूक जाइए, बोल लेने दीजिए उनको।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : दो मिनट रूको जरा। दो मिनट रूक जाइये, बोल लेने दीजिए उनको।

...(व्यवधान)

अधक्ष महोदय : दो मिनट त्यागी जी, मैंने परमिशन दे दी है। दो मिनट रूक जाइये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : दो मिनट रूक जाइये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : त्यागजी जी, इतनी देर में पूरा हो जाता। बैठिए दो मिनट प्लीज।

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, जो ये नियम 54 में हमारा धयानाकर्षण प्रस्ताव है, वो आपने स्वीकार...

अध्यक्ष महोदय : वो हो गया।

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ता : उसी पर चर्चा हो रही है न?

अध्यक्ष महोदय : आप रखिए ना अपना विषय। मैं बोल रहा हूं। अब रख दीजिए, बात खत्म करिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : जी, पहले तो अध्यक्ष जी, मैं जिस समस्या की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता था, मेरे प्रस्ताव रखने से पहले, अपनी बात रखने से पहले सामने से जवाब आ गया और वो भी गलत कॉर्नर से। यहां पर स्वास्थ्य मंत्री भी बैठे हैं। मुख्यमंत्री जी की बात उप-मुख्य मंत्री बता रहे हैं, वित्त मंत्री...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप अगर इन विषयों पर जाएंगे...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिए विजेन्द्र जी, यही दिक्कत है। आपके साथ दिक्कत यही है। आप अपनी बात रखिए, वो तो सरकार ने निर्णय करना है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिए विजेन्द्र जी, सरकार ने निर्णय करना है कि स्वास्थ्य मंत्री उत्तर देंगे या वित्त मंत्री देंगे या डिप्टी सीएम देंगे, ये उनका निर्णय है।

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात...

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात रखिए। बात रखेंगे नहीं। इसीलिए दिक्कत होती है आपके साथ।

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ता : बात मेरी शुरू हो चुकी है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हां, करिए आप बात। आप विषय पर आएंगे नहीं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, वित्त मंत्री स्वास्थ्य मंत्रालय का जवाब दे रहे हैं और...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : फिर यही दिककत आ रही है आपके साथ।

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ता : मैं वही, अरे! मेरी बात है...

अध्यक्ष महोदय : आप जो कहते हैं, इनके साथ दिक्कत यही है। ये सीधा विषय रखेंगे नहीं। विषय रखते नहीं है ये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बोल लो। आप कंट्रोवर्सियल बात करते हैं हमेशा।

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ता : ये मैंने अपनी बात शुरू करी है। मैं क्या बोलूंगा, क्या नहीं बोलूंगा, ये तो आप तय नहीं करेंगे न। आपने मुझे समय दिया मैं बोल रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, समय अब आप खराब कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिए, मेरी बात सुनिए सिरसा जी, एक बार मेरी बात, मैं रूल के अनुसार बता रहा हूं आपको।

...(व्यवधान)

उप मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, लगता है ये...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब इतनी देर में आप अपनी बात रख सकते थे। इनके साथ दिक्कत यही है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बात ही नहीं रख रहे। आपको समय मिला। मैंने सदन को साइलेंट किया, मैंने सदन को साइलेंट किया, आप फिर ट्विस्ट कर रहे हैं विषय को। आप बात रखना नहीं चाहते। आप बात ही पॉलिटिसाइज करते हैं हमेशा।

...(व्यवधान)

उप मुख्य मंत्री : अध्यक्ष जी, अरूण जेटली जी के साथ इनके रिश्ते आजकल ठीक नहीं चल रहे हैं। इसलिए ये नहीं चाहते हैं कि जीएसटी इस विधान सभा में प्रस्तुत हो और पास हो।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब विजेन्द्र जी, पॉलिटिकली जवाब मांगेंगे तो यही होगा। आप पॉलिटिकल बात करेंगे, यही चीजें होंगी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिए, आपने पांच मिनट और...आप दो मिनट में अपनी बात रख सकते थे, आपने रखी नहीं। विजेन्द्र जी, मेरी बात समझ लीजिए। मैं, हालांकि आपका प्रस्ताव नियमानुसार अस्वीकार कर चुका था। फिर भी मंत्री जी ने जवाब दिया। फिर मैंने आपको कहा कि बोल लीजिए। फिर भी आप बात पूरी नहीं कर रहे हैं। आप उसको ट्विस्ट कर रहे हैं। आपको इसको फिर ट्विस्ट करेंगे, मैं बैन कर दूंगा।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, आपने मुझे जो समय दिया है, मैं उसमें अपना वक्तव्य दे रहा हूं। वक्तव्य में मैं क्या कहूंगा, ये न सैंसर होना चाहिए न एडिट होना चाहिए और न इस पर कोई...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, ऐसा है। ऐसा कुछ नहीं है। सदन नियमों से चलता है आपके अपने बताए हुए नियमों से नहीं चलेगा। नियमों से चलेगा! अब ये चीज दिक्कत आती है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी को पांच मिनट हो गए। अलका लाम्बा, जी आप क्या विषय रख रही है, बताइये?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, अब मैं छोड़ रहा हूं। आप रख ही नहीं रहे विषय को। आप मुझे ही चैलेंज कर रहे हैं बार-बार। आप मुझे ही चैलेंज कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं वक्तव्य क्या दूंगा, क्या नहीं दूंगा वक्तव्य मुझे रखना है।

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मुझे अपनी बात...

अध्यक्ष महोदय : नहीं, बात रख ही नहीं रहे आप। आप उसको पॉलिटिकली मोटिवेट कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, अब बैठिए प्लीज।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अलका जी, बताइये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, कोई बात नहीं। ठीक नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने बार-बार आपको समय दिया। सारी चीजों के बाद समय दिया।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप अस्पतालों के बारे में बात ही नहीं करना चाह रहे। आप अस्पतालों के बारे में बात ही नहीं करना चाह रहे हैं। मैंने समय दिया।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखो सिरसा जी, ऐसे नहीं चलेगा। आपने कहा, मैंने समय दिया लेकिन वो उसको टिवस्ट कर रहे हैं। वो उसको पॉलिटिकली लेकर जा रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं अब समय नहीं दे रहा हूं। अलका जी, जल्दी करिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अलका लाम्बा जी, हां।

अध्यक्ष महोदय : सिरसा जी, नहीं-नहीं प्लीज ऐसे सदन, नहीं देखिए, ये तो वो हाल हो गया।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, एक सैकेंड, एक सैकेंड, ये तो वो हाल हो गया कि सास गुस्से में आए और बहू फिर ठंडा करे ससुर को। आप तो वो ही रोल अदा कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वो खेल बिगाड़ रहे हैं। आप बहू बनकर उसको प्रयास कर रहे हैं ठंडा करने का, बैठिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब बैठिए, प्लीज। मैंने समय दिया, वो समय का दुरूपयोग कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिए, सिरसा जी, ऐसे नहीं चलेगा। बिना इजाजत के एक तो आप बोल रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, अब मैंने अलका जी को समय दे दिया। एक बार बैठ जाइए प्लीज। नहीं अब बैठ जाइए प्लीज।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : दोनों विषयों में मैंने देख लिया। अभी एक बार मुझे अलका जी को सुनने दीजिए, क्या कहना चाह रही हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब शांति, प्रवीण जी, बैठिए प्लीज। बैठ जाइए जरा। एक बार सुन तो लीजिए, अलका जी को क्या कहना है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : राजेश जी, ये बात समझ में नहीं आ रही मुझे। प्लीज बैठ जाइए। कमांडो जी बैठिए, प्लीज बैठिए। प्लीज बैठ जाइए। अलका जी, बोलिए क्या बोल रही है आप, जल्दी बोलिए।

सुश्री अलका लाम्बा : अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान आज की जो है सदन का ध्यान....

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं कृपया शांत हो जाएं। कमांडो जी, बैठिए जरा, प्लीज।

...(व्यवधान)

सुश्री अलका लाम्बा : अध्यक्ष जी, हिन्दुस्तान न्यूज की खबर, हैडलाइन है–तीन दिन बाद भी हत्यारे भारत की राजधानी दिल्ली में दिन दहाड़े...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब मैं बिल्कुल चर्चा, मैंने समय दिया आपको, पूरा समय दिया।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अभी मैंने समय दिया आपको। ये तो सदन गवाह है सारा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आप बोल ही नहीं रहे।

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ता : हां, मैं बोल रहूं ना।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप ट्विस्ट कर रहे हैं सारी चीजें। आप बोलिए अलका जी। मैं फिर समय दूंगा आपको।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं फिर समय दे दूंगा आपको।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए। आप बैठिए जरा, आपको समय दिया, आप बोल नहीं रहे हैं। आप बैठिए प्लीज। फिर मैं दे दूंगा आपको समय।

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ता : आप समय दीजिए ना।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं समय दे दूंगा लेकिन विषय को ट्विस्ट नहीं करने दूंगा। मैं फिर विषय को ट्विस्ट नहीं करने दूंगा।

सुश्री अलका लाम्बा : अध्यक्ष जी, मैं इस मुद्दे को उठाकर सदन का ध्यान दो मुद्दों की ओर ले जाना चाहती हूं। एक तो दिल्ली में जो 'कानून व्यवस्था का मुद्दा' है और दूसरा 'स्वच्छ भारत' की हकीकत को देश के सामने इस हत्याकांड ने लाकर रख दिया है कि आज एक युवा जो ई-रिक्शा चलाकर अपने घर-परिवार और छः महीने की गर्भवती उसकी पत्नी का पालन पोषण कर रहा था, कुछ लोगों ने, जो अखबारों से पता लगता है कि वो खुले में शौच कर रहे थे। कारण ये था कि कोई शौचालय नहीं है। इस 'स्वच्छ भारत' की धज्जियां उड़ाता हुआ, ये एक हत्याकांड हमारे सामने आता है कि शौचालय न होने की वजह से वो खुले में शौच कर रहे थे और ई-रिक्शा चालक जो रविन्द्र है, उसने उन्हें समझाने और रोकने की कोशिश की और उसे मौत के मुंह में धकेल दिया गया।

दूसरी बात, अखबार ये कहता है कि Prime Minister wants culprits brougth to book. प्रधानमंत्री के चाहने के बावजूद आज तीन दिन के बाद हत्यारों का कोई पता नहीं लगा है। दूसरा ये जरूर पता लगता है कि किस तरह करोड़ीमल कॉलेज के स्टूडैंटस को ह्रास किया जा रहा है, पूछताछ के लिये बार-बार बुलाया जा रहा है। पुलिस को समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करे और मैं कहती हूं कि ये मामला इतना अपने आप में गम्भीर है कि तीन साल बाद भी, स्वच्छ भारत अभियान 15 साल नगर निगम, ने आज तक उस झुग्गी-बस्ती, जहां पर रवीन्द्र खुद रहता है, उसके घर में खुद का शौचालय नहीं है, कम्युनिटी के शौचालय में वो जाते हैं ओर उन शौचालयों की हालत जो है, वो इस अखबार में बयां, उनके परिवार ने खुद की है। मैं सिर्फ यही मांग करती हूं। मैं दिल्ली सरकार का, दिल्ली के मुख्यमंत्री का

भी धन्यवाद करती हूं कि आपने उनके परिवार को बिना समय गंवाए और सिर्फ खोखली घोषणा नहीं की, आपने 5 लाख रूपया उसकी गर्भवती पत्नी को, उसके परिवार को देकर एक सराहनीय काम भी किया है। पर मैं ये कहूंगी कि साथ में वैंकया नायडू जी ने, मुझे खुशी है इस बात की, कि इस घड़ी में उनके घर में गए उनके परिवार को मिले और 50 हजार रूपये की मदद के साथ उन्होंने दिल्ली नगर निगम में उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी की बात भी कही है। मैं नेता विपक्ष से जरूर कहूंगी कि तीनों दिल्ली नगर निगम में आपकी सरकार है, आप ही के नेता और देश के मंत्री ने ये वायदा किया उस परिवार से कि नगर निगम में एक नौकरी उन्हें दी जाएगी। तो मैं पूछना चाहती हूं कि नगर निगम उसको लेकर क्या प्रयास कर रहा है और इस तरह की घटनाएं जो दिल्ली में, भारत की राजधानी में बढ़ते आपराधिक मामले और स्वच्छ भारत अभियान के इनके खोखले नारे की तरफ इशारा करती है, मुझे लगता है दोनों मुद्दों को बड़ी गम्भीरता से लेकर जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ा जाए और आगे इस तरह की वारदात ना हों, इस पर सदन को गम्भीरता से सोचना होगा, धन्यवाद।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सिरसा जी, दो मिनट।

श्री राजेश गुप्ता : अध्यक्ष जी, मैं दो मिनट इस पर अपनी बात रखना चाहता हूं। ये खबर आई कि शौचालय न होने की वजह से किसी को मारा गया, वो मर गया। अभी 5 दिन पहले मेरी विधान सभा के अंदर डूसिब जो शौचालय बना रही थी, उन शौचालयों को तोड़ा गया। इससे पहले भी आज

से कुछ साल पहले वहां पर गोली चल चुकी है। इसी शौचालय की वजह से एक आदमी मारा गया था, वहां पर उस शौचालय को तोड़ा गया है।

अध्यक्ष महोदय : राजेश जी, ये विषय जो अलका जी ने रखा है, उससे अलग हो गया।

श्री राजेश गुप्ता : सर, चीज तो वही है। हम शौचालय बना रहे हैं, ये तोड़ रहे हैं, जो डूसिब बना रही है, नये शौचालय बनाए जा रहे हैं कि लोग उसमें जाकर शौच कर सकें, खुले में न जाएं, उसको तोड़ रहे हैं और डीडीए तुड़वा रही है उसको। डीडीए से मैं हाथ जोड़कर ये निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष डीडीए के मैंबर भी है, मेरा हाथ जोडकर निवेदन है सर आप उसमें हमारी कुछ मदद करें, माननीय एलजी साहब से करवाएं। आपके यहां भी वो शौचालय बन रहे हैं, वही हमारे यहां पर भी बन रहे हैं, शौचालय बनाने में प्लीज मदद करें।

अध्यक्ष महोदय : एक सैकेंड बैठिए प्लीज। हां, किस विषय पर?

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : अलका जी ने जो कहा, मेरा तो लगा था उसी पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

अध्यक्ष महोदय : उस मैटर पर मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : आपने विजेन्द्र गुप्ता जी को इजाजत दी है।

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र गुप्ता जी को मैंने हैल्थ वाले पर बोलने के लिए कहा, नहीं अलका लाम्बा जी के विषय पर। हां उस पर अगर बोलना है तो बताइये।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : हां, उसी पर बोलूंगा।

अध्यक्ष महोदय : हां, बताइये।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : अध्यक्ष जी,

अध्यक्ष महोदय : एक सेकेण्ड, मैं इस पर टिप्पणी कर रहा हूं। जो अलका जी ने रखा है, ये विषय अति महत्वपूर्ण है। एक सैकंड, मैं सदन से प्रार्थना कर रहा हूं कि तीन दिन हो गए हैं, उन अपराधियों को अब तक पकड़ा नहीं गया है। मैं विजेन्द्र गुप्ता जी से स्वयं प्रार्थना कर रहा हूं कि कमिश्नर के पास जाकर इस विषय को लेकर, मैं स्वयं चलूंगा, आप समय लीजिए, मैं स्वयं चलने के लिए तैयार हूं। एक सैकंड रूक जाइये।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : दिल्ली सरकार क्या कर रही है?

अध्यक्ष महोदय : एक सैकेण्ड, उन्होंने तो 5 लाख रूपये दे दिये सरकार ने। सरकार ने 5 लाख रूपये की घोषणा कर दी। जो विषय है अति महत्वपूर्ण विषय है, इसको नहीं लेते हम।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : अध्यक्ष जी, मुझे अफसोस इस बात का है, हमारी साथी अभी बता रही थी कि कारण क्या है, आप देखिये। दिल्ली में शौचालय नहीं हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा इन्होंने उठाया और मैं समझता हूं कि इनकी सरकार का इतना बड़ा फेल्योर, दो लाख, अगर आपने मैनीफैस्टो पढ़ा हो, 70 प्वाइंट मैनीफैस्टो, दो लाख शौचालय बनाएंगे।

अध्यक्ष महोदय : सिरसा जी, एक सैकेंड मेरी बात सुन लीजिए पहले।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : किसी ने आरटीआई लगाई दिल्ली में 70 शौचालय नहीं बना पाये, दो लाख शौचालय बनाएंगे। इससे बड़ा फेल्योर, लोग मर रहे हैं। इसके कारण, शौच जा नहीं पा रहे इसके कारण। ये दो लाख शौचालय बनाने की बात करके सत्ता में आए, आज वो लोग खुद मान रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सिरसा जी। अब बात हो गई न? माईक खुला हुआ है आपका।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : अध्यक्ष जी, दो लाख शौचालय बनाने थे, बनाए नहीं। आज लोग त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। लोग शौच जाने को बाहर मजबूर हो रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : सिरसा जी, दो मिनट मेरी बात सुनेंगे। सिरसा जी, आप बोल रहे हो, आप सुन नहीं रहे हो। आपने बोल लिया। उतनी देर अलका जी नहीं बोली, जितनी देर आपको समय दिया।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : मैं दो मिनट भी नहीं बोल पा रहा, आप बोलने तो दीजिए मेरे को।

अध्यक्ष महोदय : बोल तो लिया। सिरसा जी, हम ज्यादा समय उसमें लेते हैं, टू दी प्वाइंट बात नहीं करते।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : मैं दवाइयों की बात कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, दवाइयों की बात या तो वो करेंगे या आप करेंगे। नहीं, आप बैठ जाइये। नहीं, दवाइयों की बात या तो वो करेंगे या आप करेंगे। नहीं, मैंने कहा, मैं समय दूंगा, नहीं आप बैठिए, आप बैठिए बात पूरी हो गई आपकी।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : मैं पूछता हूं दो लाख शौचालय कब बनेंगे? लोग शौचालय के कारण मरना कब बंद होंगे, सरकार इसका जवाब देगी? सरकार के नुमाइंदे ने सवाल उठाया है।

अध्यक्ष महोदय : अब बैठिए, दो मिनट बैठिए। दो मिनट बैठिये आप, दो मिनट बैठिए तो सही आप।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिये, सिरसा जी ने जो बात रखी है, दो मिनट रूकिये, सिरसा जी, आप नये सदस्य हैं सदन के, ये दिल्ली की जनता के हित में हमको विचार करना चाहिए। शौचालय बनाने का काम बेसिकली नगर-निगम का है, पेशाबघर, नहीं, फिर आप बोल रहे हैं, आप दो मिनट बैठिये। पूरा मैं बोल रहा हूं। आप बैठिए दो मिनट। सिरसा जी, ये तरीका ठीक नहीं है। मैं आप ही की तरफ मुखातिब हो रहा हूं, दो मिनट बैठिए आप।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : दूसरा एक सैकण्ड, राजेश जी, प्लीज दो मिनट। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, अगर एक व्यक्ति खुले में पेशाब कर रहा है, अगर वहां पेशाब घर नहीं है, चर्चा का विषय ये है। विजेन्द्र जी, नहीं, आप बैठ

जाइए। आप विषय को ही डायवर्ट कर रहे हैं। विजेन्द्र जी, आप बैठ जाइये। दो मिनट रूक जाइये आप। मैं खड़ा होकर बोल रहा हूं। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं, बैठ जाइये। सिरसा जी, बैठ जाइये आप। माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं बोले ना, प्लीज। अमानतुल्लाह जी, प्लीज। मैं खड़ा हुआ हूं आप बोल रहे हैं। मैं ये बात कह रहा हूं। मैं एक बात पूछना चाह रहा हूं कि जो भावना अलका लाम्बा की थी, उसको हम डायवर्ट कर रहे हैं। सदन बैठा है यहां पर। दिल्ली की जनता के हित में, पेशाब घर नहीं हो सकता, शौचालय नहीं हो सकता! कोई व्यक्ति उसको प्वाइंट आउट करता है कि आप यहां पर पेशाब ना करिये, क्या उसकी हत्या कर दी जाएगी, विषय ये है और आप उसको डायवर्ट कर रहे हैं, नहीं, उन्होंने यही कहा है। उन्होंने वो भी कहा लेकिन मैं सदन की भावना व उसकी भावना जो मैं समझा हूं और जिस चीज, फिर आप खड़े हो गये, फिर आपको परेशानी हो गई। सदन की भावना को समझें। एक सैकंड जी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं यह कहना चाह रहा हूं कि एक व्यक्ति की हत्या हो गई, उसका छोटा बच्चा है, उसकी पत्नी विधवा हो गई। हमें कमिश्नर के पास जाकर इस सदन की सामूहिक भावनाएं भेजनी चाहिए। नहीं, आप उसको....अरे! सम्मन करेंगे, वो बाद की बात है। राखी जी, चुप हो जाइए प्लीज। सदन को अपनी सामूहिक भावनाएं कमिश्नर के पास भेजनी चाहिए। तीन दिन हो गए, उनमें से किसी को पकड़ा नहीं गया। उन भावनाओं को आप डेमेज कर रहे हैं। आप ने साथ ही नहीं दिखाया। आपको चाहिए था। बैठिए आप बैठिए।

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सम्मन कराइए, पुलिए कमिश्नर को सम्मन कराइए। कैसे इस तरह से मर्डर हो जाता है दिल्ली में? कमिश्नर को सम्मन कराइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सिरसा जी, आप विषय को...मुझे उम्मीद नहीं थी आपसे। मुझे उम्मीद थी कि...

...(व्यवधान)

श्री राजेश गुप्ता : सर, पुलिस कमिश्नर को सम्मन करो। सिरसा जी कर क्या रहे हैं? सिरसा जी, मैं आपके साथ हूं। पुलिस कमिश्नर को सम्मन करो। सारा सदन इस बात को चाहता है, विपक्ष भी और हम भी। विपक्ष भी यही चाहता है और हम भी यही चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : राजेश जी, आप बैठ जाइए। आप बैठिए। आपको बोलने का मौका दिया, तब आप बोल नहीं पाए। बैठिए आप। आपने विषय ही डायवर्ट किया। बैठिए। नितिन जी, बैठिए प्लीज। राखी जी बैठिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सिरसा जी, सिरसा जी, ये तरीका ठीक नहीं है। राखी जी, बैठिए। राखी जी, बैठिए। प्लीज।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सदन 15 मिनट के लिए स्थगित किया जाता है।

(सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित की गयी।)

सदन अपराह्न 3.15 बजे पुनः समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय **(श्री रामनिवास गोयल)** *पीठासीन हुए।*

श्री सुरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सिरसा जी ने जो प्वाइन्ट रखा कि कमिश्नर को यहां बुलाया जाये, सम्मन कया जाये। हम उनकी इस बात से सहमत हैं। जो इस प्रकार दिल्ली के अन्दर गुंडागर्दी हो रही है। सरेआम एक निहत्थे नौजवान को मारा गया है। तो मैं उसका सहयोग करता हूं। उस बात को आगे बढ़ाते हुए कि कमिश्नर साहब को सम्मन किया जाये, बुलाया जाये, तलब किया जाये। ताकि पुलिस अपनी जिम्मेदारी समझस के। लॉ एण्ड आर्डर बना रहे। आज दिल्ली के अंदर, पूरी दिल्ली में एक डर का माहौल है। आये दिन रोडरेज, रोडरेज की आये दिन घटनाएं हो रही हैं।....

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं कि वो बैठें। मैं सदन की भावना से सहमत हूं और पुलिस कमिश्नर को अगली बार जैसे ही सेशन होगा, उनको यहां बुलाया जायेगा।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : जो विक्टिम हैं, उन्हें जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाये क्योंकि विषय, शौचालय के मामले में जिस युवक की हत्या हुई है, शौचालय के विषय पर उसको ध्यान में रखते हुए यहां...

अध्यक्ष महोदय : एक तो विजेन्द्र जी हम कन्फ्यूज हो रहे हैं। शौचालय पर नहीं, पेशाब पर हुआ है। पेशाब के ऊपर हुआ है। इसको थोड़ा सा...

श्री विजेन्द्र गुप्ता : मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता अध्यक्ष जी। मैं कहना चाहता हूं कि यहां पर सदस्यों ने कहा कि दो दिन में गिरफ्तारी नहीं हुई तो जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, ये भी हमको यहां जोड़ना चाहिए। ये नहीं कि आयुक्त जब आयेंगे, आयेंगे। लेकिन उस मामले में जिस मामले पर आयुक्त बुलाने की बात हुई है, वो गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

सुश्री भावना गौड़ : अध्यक्ष महोदय, ये दैनिक जागरण न्यूज पेपर है। ये बीजेपी के प्रो अखबार का ये कहना है। इसके अन्दर आज ये खबर छपी है और खबर में लिखा है कि जनता ने जताया विश्वास, अपनों का नहीं मिला साथ। ये सीधा-सीधा अखबार के अन्दर बताया गया है कि बीजेपी के हमारे साथी जो बहुत सारी समस्याओं को लेकर चिन्ताग्रस्त हैं लेकिन दिल्ली नगर निगम के अन्दर चाहे हैट्रिक बनाकर के इनके कैन्डीडेट्स जीत करके आये हैं, उस निगम को कैसे चलाना है, वो निगम कैसे काम करेगा, उसके पदाधिकारी चुन करके कैसे आयेंगे, इस तरफ इन लोगों का किसी भी तरह का कोई भी ध्यान नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, राजनैतिक महत्वाकांक्षा होना अपने आप में बहुत बुरी बात नहीं है किन्तु व्यक्तिगत आकांक्षा होना और उनको लेकर के लगातार लड़ते रहना, ये अपने आप में, मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता के साथ में कोई न्याय नहीं कर रहे हैं ये लोग। अध्यक्ष महोदय, इस अखबार के अन्दर बिल्कुल क्लीयरकट लिखा है और जिस भी पत्रकार बधु ने इसके अन्दर इस

भाषा का इस्तेमाल किया है, मैं चाहूंगी कि सदन के बीच में उसको पढ़कर के बताऊं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, पढ़िये नहीं। आप भावना प्रकट करिये फटाफट। मुझे बहुत समय का अभाव है। समय बहुत खराब हो चुका है।

सुश्री भावना गौड़ : अध्यक्ष महोदय, बीजेपी की सरकार, दिल्ली के अन्दर एक महीना हो गया निगम के चुनाव हुए और लगभग 15 दिन का समय हो गया इन लोगों को शपथ लिये हुए, दिल्ली नगर निगम के अन्दर आज तक स्थाई, हमारे स्टैंडिंग कमेटी के न तो चेयरमैन की इन्होंने नियुक्ति की है और न हमारे सदन के नेता इन लोगों के द्वारा बनाये गये हैं और इनके भाजपा के नेता चाहे वो प्रदेश के अधिकारी हों, चाहे लोक सभा के चुने हुए इनके सांसद महोदय हों, चाहे राज्य सभा में भेजे हुए इनके केन्द्रीय राज्य अधिकारी हों, सभी मिल कर के केवल मोदी जी के तीन साल के कामों के दिल्ली से बाहर जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, केवल उन कार्यक्रमों के अंदर व्यस्त हैं। लेकिन दिल्ली के अंदर बारिश का समय है, नालों की सफाई अभी तक शुरू नहीं हुई है। आने वाले समय के अंदर मलेरिया फैलेगा, आने वाले समय में चिगनगुनिया और डेंगू जैसी बीमारियां फैलेंगी लेकिन निगम को कैसे चलाया जायेगा, इस तरफ महोदय, इन लोगों का किसी भी तरह का कोई भी ध्यान नहीं है। मैं सदन को इस बात से अवगत कराना चाहूंगी कि दिल्ली के अंदर चुनाव हुए और बहुत भारी मतों से जीत के इनके सभी उम्मीदवार सदन में पहुंचे हैं। सदन जब तक चलेगा नहीं, तब तक उसके कामों की प्रगति कैसे होगी, उन कार्यों का क्रियान्वयन कैसे क्षेत्र के अंदर किया

जाएगा, इसका अपने आप में कोई इनका रोड-मैप भी अभी तक तैयार नहीं हुआ।

अध्यक्ष महोदय, क्योंकि यहां पर विपक्ष के नेता बैठे हैं। सत्र और विशेष सत्र, इसकी परिभाषा तो अभी आपको समझा रहे थे। पूरे सदन को समझा रहे थे।

अध्यक्ष महोदय : कन्क्लूड कीजिए।

सुश्री भावना गौड़ : अध्यक्ष महोदय, मेरा तो यही कहना है कि इस अखबार में जो पत्रकार लिख रहा है, वो मेरी भाषा नहीं है। इन्हीं का पत्रकार है। इन्हीं का अखबार है। इन्हीं की छपने वाली खबर है तो दिल्ली के अंदर नगर निगम को कैसे काम करना है, किस तरह से इन सारे कामों को छोड़ कर के नगर निगम अपनी तैयारी करे। उसके बारे में मैंने अपना विचार आपके सामने रखा।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, मैं भावना जी की बात पर, क्योंकि इन्होंने मुझे सम्बोधित करके कहा है...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, हो गया। देखिये, मुझे जीएसटी पास करवाना है प्लीज।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : कहा है कि स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनी, मेरे को....

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हो गया, बात खत्म हो गई। आप कारपोरेशन के मैम्बर हैं क्या? प्रवीण जी, बताइये।

श्री प्रवीण कुमार : अध्यक्ष जी, मैं भावना जी बात....

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वो अखबार के हवाले से बोल रही हैं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, जोन का गठन नहीं हुआ, यह छोटा विषय है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वो अखबार के माध्यम से बोल रही है। अखबार उन्होंने रखा है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, मुझे जीएसटी पास करवाना है। आप दो मिनट बैठ जायें। प्रवीण जी, बोलिये। त्यागी जी, हो गया। त्यागी जी, बहुत समय हो गया है। प्रवीण जी, बोलिये।

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी,यह कौन सा तरीका है?

अध्यक्ष महोदय : क्या?

श्री विजेन्द्र गुप्ता : आप उनको बोलने दे रहे हैं अखबार लेकर और वो आरोप लगा रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कोई आरोप नहीं लगाया। उन्होंने कहा नेता सदन नहीं बने।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : उन्होंने कहा जोन गठित नहीं हुए, जोन गठित किसको करना है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जोन कब लिया, आप फिर ट्विस्ट कर रहे हैं विजेन्द्र जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : उन्होंने कहा है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने नहीं बोला, मैं फिर दोहरा देता हूं। जो मैंने सुना है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक सेकेंड रूक जाइये कि नेता सदन का निर्णय नहीं हुआ और स्टेंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी नियुक्त नहीं हुए, बस। जोन कहां हैं?

श्री विजेन्द्र गुप्ता : वही तो कह रहा हूं। स्टेंडिंग कमेटी...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बैठिये। प्रवीण जी, बोलिये।

श्री प्रवीण कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि एक बधाई प्रस्ताव इस सदन में लाना चाहता हूं। आपकी अनुमति हो तो एक बधाई प्रस्ताव मैं इस सदन में लाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : संक्षेप में रखिये फटाफट।

श्री प्रवीण कुमार : इस सरकार ने कई सारे ऐसे बड़े-बड़े काम किए हैं, पिछले दो सालों में लेकिन एक बहुत बड़ा काम जिसके कारण हम सारे सदन का और पूरे दिल्ली वासियों का और सदन में बैठे हरेक एमएलए का, हरेक मंत्री का, हरेक व्यक्ति का सीना फख्र से चौड़ा हो जाता है क्योंकि जब यह सुनते हैं, जब अखबार की बड़ी हैडलाइन आती है कि हमारे दिल्ली सरकार के स्कूलों ने प्राइवेट स्कूलों से नौ प्रतिशत बेहतर परफॉर्म किया। अपने आप में बहुत बड़ी काबिलेतारीफ है। मैं चाहता हूं सारा सदन खड़े होकर मुख्य मंत्री, उप मुख्य मंत्री को एक बार इसकी बहुत बधाइयां दें।

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, सीट पर तो खड़े हो जाओ, क्या दिक्कत है? आपका ध्यान ही नहीं है। उन्होंने दिल्ली में पब्लिक स्कूलों से, एक सेकेंड, माननीय सदस्य...

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : बधाई हो, बधाई हो।

अध्यक्ष महोदय : सिरसा जी, आपसे यह उम्मीद नहीं है मुझे। विजेन्द्र गुप्ता

जी से उम्मीद हो सकती है। आप बैठ जाइये। प्लीज बैठ जाइये। मैं आग्रह कर रहा हूं, बैठ जाइये। सिरसा जी, बैठ जाइये प्लीज।

...(व्यवधान)

श्री ऋतुराज गोविंद झा : XXXX[1]

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : हद है, इस तरह की बात कहने की भावना है उसके अंदर...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : त्यागी जी, प्रवीण जी, आप अपनी सीट पर रहिये।

श्री प्रवीण कुमार : एमसीडी स्कूल आपसे चलते हैं, दिल्ली सरकार के स्कूल....

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठेंगे दो मिनट सिरसा जी? मैं बोलूंगा, परेशानी हो जाएगी। आप प्लीज बैठ जाइये।

श्री प्रवीण कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद प्रस्ताव आपके सामने पढ़ना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये। त्यागी जी, बैठिये।

श्री प्रवीण कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद प्रस्ताव आपके सामने पढ़ना चाहूंगा।

---

[1]XXXX चिन्हित अंश अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाले गये।

प्रस्ताव (नियम-144)

Sir, I intend to move the congratualatory motion without noitce under rule 114 in the august House :

"Noting with gratitude that the Government of NCT of Delhi led by Shri Arvind Kejriwal has been earmarking the highest percentage of its budget for education and health, also noting with pride that the Minister of Education and Minister of Health are putting to the best use the enhanced budget for the welfare of the people.

Appreciating the deligent and honest efforts put in by Shri Manish Sisodia in unleasing the revolutionary refroms in education sector, Noting with a great sense of satisfaction that the Govt. Schools have positively responded to the constructive efforts of Shri Manish Sisodia by producing outstanding results in CBSE 12th Standard exams and proving to be way ahead of the expensive schools of private sector.

This House congratulates Shri Manish Sisodia, Ms. Atishi Marlena, the officers of GNCTD, most importantleach and every proud teacher, student and principal of all the Govt. Schools of Delhi for making such a stupendous result possible againt all odds."

बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद पूरी दिल्ली सरकार को, पूरे एजुकेशन डिपार्टमेंट को, मुख्यमंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री जी को और advisor to the Dy. CM Ms. Aatishi Marelina को बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सिरसा जी, आप बैठ जाइये। प्रवीण जी, आप बोलिये। सिरसा जी, यह ठीक नहीं है। आप बैठिये। मैं बताऊं, क्या गलत किया है? में उनसे भी बात करूंगा।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : आप जस्टिफाई करेंगे...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पहले आप बैठिये। मैं बताऊं? आप बैठ जाइये प्लीज।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : सदन के अंदर...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, आप बैठेंगे जरा। सिरसा जी, बैठ जाइये प्लीज। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं बैठ जाइये।

श्री प्रवीण कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए आपसे कहना चाहता हूं कि...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सिरसा जी, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं बैठ जाइये। मैं अध्यक्ष पद की मर्यादा रख रहा हूं, लेकिन जिस ढंग का व्यवहार आज हो रहा है, यह उचित नहीं है।

श्री प्रवीण कुमार : अध्यक्ष महोदय, अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए आपसे कहना चाहता हूं कि...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सिरसा जी, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं बैठ जाइये। मैं अध्यक्ष पद की मर्यादा रख रहा हूं, लेकिन जिस ढंग का व्यवहार आज हो रहा है, यह उचित नहीं है।

श्री प्रवीण कुमार : अध्यक्ष महोदय, अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए आप सब के सामने....

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सिरसा जी, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बैठ जाइये। मैं अध्यक्ष पद की मर्यादा रख रहा हूं, लेकिन जिस ढंग का व्यवहार आज आज हो रहा है, यह उचित नहीं है।

श्री प्रवीण कुमार : अध्यक्ष महोदय, अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए आप सब के सामने....

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ता : ऐसे कैसे कह दिया उन्होंने....

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, बैठिये प्लीज।

श्री प्रवीण कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं भी बोल रहा हूं यहां पर....

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : राजेश जी, बैठ जाइये प्लीज। मत कोई शब्द लाइये आप। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं बैठ जाइये।

श्री प्रवीण कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात रख दूं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नितिन जी, ऐसे नहीं चल पाएगा। देखिये, ऐसे नहीं चल पाएगा सदन।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिये सिरसा जी, मैं हंबल रिक्वेस्ट करके बात कह रहा हूं, इस बात को एक बार समझ लीजिए। हम हर बात को ट्विस्ट करके दूसरे एंगल में लेकर जाएंगे तो एक्शन का रिएक्शन होगा। प्रवीण जी ने बहुत सुंदर विषय रखा कि दिल्ली का रिजल्ट पब्लिक स्कूलों से ज्यादा अच्छा है। नहीं, दो मिनट रूक जाइये, अभी मेरे बीच में मत बोलिये विजेन्द्र जी। आप अपनी भावनाएं बहाना चाहते हैं और मैं बताना चाह रहा हूं, मैं एपिसोड को, एक सेकेण्ड, आप बोलिये नहीं प्लीज। सारा सदन खड़ा हुआ प्रशंसा करने के लिए, मैंने बड़ा हंसी मजाक में।

...(व्यवधान)

श्री जगदीप सिंह : अध्यक्ष महोदय, टेबल थपथपाया जाता है...ये विधानसभा की परंपरा है, केवल ये बताने की कोशिश कर रहा था।

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, आप फिर गलत कर रहे हैं। आप या तो

तय करके आए हैं, आप, जैसा उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जीएसटी पास नहीं होने देना चाह रहे हैं। आप लिखकर भेजिए, आपको अवसर मिलेगा बोलने का। आप लिखकर भेजिएगा, चर्चा जब होगी। आप चर्चा करने दीजिए। सिरसा जी, दो मिनट रूक जाइए प्लीज। दो मिनट रूक जाइए। प्रवीण, जी दो मिनट बैठ जाइए आप। आपकी बात पूरी हो गई। मैंने उस वक्त भी कहा, भई इस विषय पर तो कम से कम सरकार को बधाई दे दीजिए। नहीं खड़े हुए, कोई बात नहीं, विजेन्द्र जी, दो मिनट वहां दे दीजिए आप। आपने कुछ दूसरा कमेंट्स कर दिया तीनों ने। खड़े होकर बोल दिया, क्या मंत्री का इस्तीफा हो गया?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आपने बोला, दूसरी बात जो अभी जगदीप जी ने कहा है, मैं उसको दोहरा नहीं रहा। उन्होंने कोई आपका नाम कोट नहीं किया।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : अरे! मेरे आप वीडियो देख लीजिए, प्रूफ मंगवाइये।

अध्यक्ष महोदय : बस 'ताली का इशारा' ये बोला है। ये बोला है इन्होंने इसके अलावा और कुछ नहीं, कोई नाम कोट नहीं किया। उन्होंने किसी का नाम कोट नहीं किया।

...(व्यवधान)

(श्री मनजिंदर सिंह सिरसा वैल में आकर बैठ गए)

अध्यक्ष महोदय : भई, दो मिनट बैठ जाइये प्लीज। कमांडो जी, प्लीज। प्रवीण जी, बैठिये, आपका मोशन आ गया दो मिनट रूकिये। मैं आगे ये कह रहा हूं जो उन्होंने सुना नहीं। पहली बात तो उन्होंने नाम नहीं लिया, अगर फिर भी उन्होंने कुछ नाम लिया, कुछ कार्यवाही हुई है, जिससे उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है, वो कार्यवाही से निकाल दी जाए।

...(व्यवधान)

श्री ऋतुराज गोविन्द : सारा सदन, अगर एजुकेशन के ऊपर जो अचीवमेंट हुआ है, उस पर अगर एप्रीसिएट कर रहा है, मेज थपथपा कर के तो आप चाहे वीडियो निकलवा लीजिए उन्होंने बोला ऐसे ऐसे, ताली का इशारा।

...(व्यवधान)

श्री ऋतुराज गोविन्द : अगर सिरसा जी ने ऐसे नहीं किया हो तो आप जो कहेंगे वो करने के लिए तैयार हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं विजेन्द्र जी, इसीलिए कह रहा हूं। ये चीज जो है, ये सदन की मर्यादा के विरूद्ध है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अगर फुटैज देखने में विजेन्द्र जी, दो मिनट रूकिये, त्यागी जी, दो मिनट रूकिये, अगर विडियो में ये एक्शन हुआ तो सदन से माफी मांगेंगे? नहीं, नहीं, वो एक्शन का रिएक्शन है। ये सदन से माफी, नहीं पहले इनको मांगना। अगर फुटेज में ये एक्शन हुआ, ये सदन से माफी मांगें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं 15 मिनट के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर रहा हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अगर फुटेज देखने में...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, दो मिनट रूकिये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : त्यागी जी दो मिनट रूकिये।

...(व्यवधान)

सुश्री भावना गौड : अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय : दो मिनट रूकिये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अगर वीडियो में ये एक्शन हुआ सदन से माफी मांगेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, वो एक्शन का रिऐक्शन है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ना, ना, बिल्कुल नहीं, अगर फुटेज में ये एक्शन हुआ ये...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सदन से माफी मांगेंगे। नहीं, सदन से माफी मांगें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, विजेन्द्र जी, सदन से माफी मांगेंगें।

...(व्यवधान)

सुश्री भावना गौड़ : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के लोग केवल सदन का समय वेस्ट करने के अलावा....

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप पहले सीट पर आकर बोलिये। नहीं, मैं यहां से नहीं बोलने दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको बोलना है जो, सीट पर बोलें जा के।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिये, दो मिनट बैठेंगे? दो मिनट बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सोमनाथ जी, बैठिये प्लीज।

सुश्री भावना गौड़ : विजेन्द्र भाई, एक बात जरूर आपको कहना चाहूंगी।

अध्यक्ष महोदय : भावना जी, आप बैठिये। भई, आप किससे पूछ के खड़े हो गये? आप दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, खुद बिना पूछे खड़े होते हैं। मैं रोक रहा हूं न उनको।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : तमाशा है ये? आप जब मर्जी आये, खड़े हो जायें और वो मैं रोक रहा हूं उनको। आप खड़े हो रहे हैं। आपने तमाशा बना रखा है ये? आप किससे पूछ के खड़े हो गये? मैं उसको रोक रहा हूं। मैंने रोका है न उसको।

(माननीय सदस्य श्री मनजिंदर सिंह सिरसा सदन के वेल में आये।)

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित की जाती है।

(सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित की गई।)

सदन 4.29 बजे पुनः समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय **(श्री राम निवास गोयल)** *पीठासीन हुए।*

अध्यक्ष महोदय : सुश्री राखी बिड़ला, चौ. फतेह सिंह जी, नियम समिति का द्वितीय प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करेंगे। ये डिस्ट्रीब्यूट करवा दें।

सिरसा जी, हो बोलिए बोलिए। हां बस, एक मिनट हो जाने दीजिए।

सुश्री राखी बिड़ला : अध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से नियम समिति का द्वितीय प्रतिवेदन सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूं, धन्यवाद।[2]

अध्यक्ष महोदय : बहुत बहुत धन्यवाद। ऋतुराज जी।

श्री ऋतुराज गोविन्द : अध्यक्ष महोदय, अभी थोड़ी देर पहले जैसा कि सदन के अन्दर दिल्ली सरकार की एजुकेशन की जो अचीवमैन्ट है, इसके ऊपर बस हम लोगों ने एप्रिशएट किया था और उसके दरमियान जो हमने रिएक्शन दिया था, उससे अगर सिरसा जी की भावना को किसी तरह का ठेस पहुंचा है तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूं।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : मैं ऋतुराज जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतना हमारा सम्मान किया, इसके लिए और हाउस से, अगर मेरी किसी भी बात से इस दौरान आज ऋतुराज जी या और भी अगर कोई मेम्बर आहत हुआ है तो मैं भी उसके लिए माफी चाहूंगा। मेरा कोई इन्ट्रेस्ट नहीं है इस पर।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रवीण जी, मैं आ रहा हूं, चर्चा ले रहे हैं। आप लिखकर,

---

[2]पुस्तकालय में संदर्भ सं आर-19012 पर उपलब्ध।

समय का थोड़ा सा अभाव है उसमें सदस्य थोड़ा कम रखेंगे। एक सदस्य को मैं इजाजत दूंगा। भावना गौड़ जी।

सुश्री भावना गौड़ : अध्यक्ष महोदय, शुक्रिया आपका।

अध्यक्ष महोदय, भारत की शिक्षा जो है, वो शिक्षा मूल्य आधारित शिक्षा है जिसमें प्रत्येक बालक का सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक इस तरीके का विकास हो। मैं अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में चल रही सरकार और उसके उप मुय मंत्री जो हमारे शिक्षा विभाग को देख रहे हैं, अभी सीबीएसई में जो परीक्षा परिणाम आए हैं, उसके लिए मैं हृदय से अपनी सरकार को और सरकार में शिक्षा मंत्रालय को देख रहे आदरणीय उप मुख्य मंत्री जी मनीष सिसोदिया जी को मैं बहुत-बहुत हृदय की गहराइयों से उनको बधाइयां देती हूं और उनको शुभकामनाएं देती हूं।

अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि इस शिक्षा परिणाम को यहां तक पहुंचाने में मनीष जी के नेतृत्व में हमारे जो पार्टी के वालंटियर्स, हमारे एसएमसी की टीम, हमारे वो बालक जो विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, उनके अभिभावक, उनका सहयोग, उन सबको भी सदन की तरफ से उनको बहुत सारी शुभकामनायें और बधाई देनी चाहिए क्योंकि जब तक हम सब लोग मिलकर के एक कड़ी के रूप में काम नहीं करते, तब तक इस तरह का बदलाव आना अपने आप में संभव कार्य नहीं था।

अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद दूंगी उन सभी साथियों का, मैं धन्यवाद दूंगी उन सभी को जिन्होंने हमारी शिक्षा नीतियों को स्वीकार किया और उनको लागू

करने में अपना सहयोग प्रदान किया। अध्यक्ष महोदय, मुझे ये कहते हुए गर्व महसूस होता है कि सरकारी स्कूलों के अंदर बच्चे बहुत लगन से और बहुत मेहनत से अपने कार्य को कर रहे हैं। दिल्ली सरकार के प्रतिभा विकास विद्यालयों ने केंद्रीय विद्यालयों से भी बढ़-चढ़ करके प्रदर्शन किया। प्रतिभा बाल विकास विद्यालय का उत्तीर्ण प्रतिशत 99.7 प्रतिशत रहा। केन्द्रीय विद्यालयों का उत्तीर्ण प्रतिशत 94.6 प्रतिशत रहा।

अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के कीरब 33 बच्चों ने अपने विषय के अदर सौ में से सौ मार्क्स प्राप्त किये। मैं ऐसे सभी बालकों को इस सदन की तरफ से बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगी।

अध्यक्ष महोदय, देखिये, एक बालक है जिसका नाम है दुर्गेश, दृष्टिहीन बालक, हमारे मुखर्जी नगर में एक सेवा कुटीर है, उसके अन्दर पढ़ता है। वो रंग-बिरंगी दुनिया को नहीं देख पाता लेकिन उसके जो लक्ष्य हैं, वो अपने आप में उसके सपने जो हैं, वो लक्ष्यों को लिये हुए हैं। इस दृष्टिहीन बालक जिसका नाम दुर्गेश है, उसने 89.66 प्रतिशत मार्क्स हमारे सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में लिये। मैं ऐसे बालक को जो अपने तरीके से इस दुनिया को देखने का प्रयास कर रहा है, उसको मैं अपनी तरफ से बधाई दूंगी।

अध्यक्ष महोदय, इस बार जो सीबीएसई की परीक्षा हुई, उसमें लगभग 67817 बच्चों ने भाग लिया जिसमें लड़कों की संख्या 35959 रही और लड़कियों की संख्या 31858 के करीब रही। अध्यक्ष महोदय, यूं तो राधाकृष्णन आयोग बना। कोठारी आयोग बना। शिक्षा समिति के केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड बहुत सारे बने। उन्होंने अपने-अपने तरीके से शिक्षा की परिभाषा क्या होती है, उसको बताने

का प्रयास किया लेकिन जब हम इस सरकार में चुनकर के आये तो बजट के पहले भाषण में जब शिक्षा के बजट को बढ़ाया गया तो इस बजट को मानवीय निवेश का नाम दिया गया। मुझे लगता है कि जिन सपनों को लेकर के आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में आयी और मुझे लगता है कि चाहे कोई भी बढ़िया से बढ़िया इन्जीनियर बने, कोई बढ़िया से बढ़िया अभिनेता बने या नेता बने और वो किसी भी विषय को जाकर के अपने कैरियर को बनाने का प्रयास करे लेकिन उसको बनाने में अगर योगदान सबसे ज्यादा किसी का है, तो वो उसके टीचर्स का होता है। हमारे टीचर्स के लिए हमारी सरकार ने विदेशों में भेजकर के नये-नये प्रोग्राम से ताल्लुकात रखने का जो कार्यक्रम सरकार की तरफ से आयोजित किया गया, अपने आप में एक विशेष, एक ऐसे पायदान के रूप में हमारी सरकार ने काम किया है, जहां सभी अभिभावक अपने नित्य कर्म को करने के साथ-साथ में सरकार की जो योजनायें हैं, उसके साथ में कहीं न कहीं जुड़ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि शिक्षा, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है और स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर के सरकार जिस तरीके के काम कर रही है, मैं एक बार पुनः इस सदन की तरफ से बहुत-बहुत बधाई दूंगी और देखिये इतिहास कभी-कभी बनता है। हमारी सरकार और सरकार में काम कर रहे हमारे मंत्री, हमारे उप मुख्य मंत्री, उन्होंने जो एक व्यवस्था परिवर्तन के नारे को लेकर के और उसको किस तरह से हम धरातल के ऊपर लेकर के आये, उस तरह से दिन रात लगकर के जो काम कर रहे हैं, हृदय की गहराइयों से एक बार मैं पुनः आदरणीय मनीष जी को बहुत-बहुत बधाई दूंगी, बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगी और क्योंकि स्वयं भी एक महिला

हूं और लड़कियों का रिजल्ट इस बार लड़कों से भी बेहतर आया हैं लड़कियां 92.8 प्रतिशत इस बार पास हुई हैं और जबकि लड़कों का रिजल्ट 82.49 प्रतिशत आया है। मैं एक बार फिर आप सभी को और इस सदन में उपस्थित हमारी पार्टी के सभी विधायकों को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगी और विशेष तौर पर एसएमसी का जो प्रोग्राम अपने स्कूलों में के लिए तय किया, उनके माध्यम से बालकों को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह का सहयोग हम लोगों को लगातार प्राप्त हो रहा है, आप सच में बधाई के पात्र हैं। एक बार मैं आप सभी को कहूंगी कि हमारे इस सदन में अरविंद जी और मनीष जी मौजूद हैं, हम हृदय की गहराइयों से मेजें थपथपा के उनका स्वागत करेंगे, उनका सम्मान बढ़ायेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय : श्री गुलाब सिंह जी।

श्री गुलाब सिंह : धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय, इतने महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का मौका आपने दिया।

अध्यक्ष महोदय, सरकार जब बनी तो जनता के सामने एक जनप्रतिनिधि होने के नाते रोज सबसे मिलना-जुलना होता था। एक समय था जब पैरेन्टस ये कहते हुए मजबूरी में अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में डालते थे कि प्राइवेट स्कूल में फीस बहुत ज्यादा है, हम भर नहीं पा रहे हैं। क्या करें, अब तो सरकारी में पढ़ाना पड़ेगा लेकिन आज ठीक करीबन सवा दो साल बाद, ये रियलिटी आने के बाद, आज वही पैरेन्टस अपने बच्चों को खुशी-खुशी उन सरकारी स्कूलों के अन्दर सिर्फ इसलिए कह के डाल रहे हैं कि आपने हमारे प्राइवेट स्कूलों को पीछे छोड़ा। माननीय शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी ने जो

काम किया, निश्चित तौर पर दिल्ली के सभी अभिभावकों का इस पर विश्वास बढ़ा है और मैं न सिर्फ एक सदस्य के नाते सदन में बात रख रहा हूं, मैं ये बात एक अभिभावक होने के नाते भी रख रहा हूं, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। मैंने वो कोशिश की, एक छोटी सी कोशिश और वो कोशिश आज विश्वास में तब्दील हो गयी। मुझे आज यकीन हो गया। मैंने तो वो कोशिश शुरू की थी तो मुझे कभी नहीं लगा था। डर था मन में, क्या ऐसा हो सकता हैं? बड़ा मुश्किल है लेकिन जिस घुम्मनहेड़ा गांव के स्कूल के अन्दर, कभी मैं सोच भी नहीं सकता था, मेरे बच्चे का खेलने में भी इन्टरेस्ट था। उसने कहा, जब एडमिशन दिलाया कि देखो, आप मुझे प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी में डाल रहे हो, बहुत बुरा हाल है। मेरे लिए खेलने के लिए यहां पर कोई अच्छा ग्राउन्ड भी नहीं है और आज मुझे कहते हुए फख्र है कि आने वाली 24 जून को शिक्षा पर पूरे हिन्दुस्तान का गुगल सर्च मार लेना, पूरे हिन्दुस्तान का घुम्मनहेड़ा स्कूल, पहला स्कूल है, जिसमें करीबन साढ़े बारह करोड़ रूपये की लागत से हॉकी का एस्टोटर्फ बनाया गया है और तैयार हो चुका है। ये वो कार्य माननीय उपमुख्यमंत्री जी ने किया है, जिसका मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूं और जिस रिजल्ट पर आज हम बात कर रहे हैं 88.27 जो ये रिजल्ट आया दिल्ली का, जिस राज्य को उदाहरण माना जाता है मॉडल का, उस राज्य की स्थिति ये थी। 10वीं का 68 परसेन्ट और 12वीं का 56.82 परसेन्ट, गुजरात की ये हालत है। तो मैं सीधे तोर पर अपनी सरकार को, माननीय उप मुख्य मंत्री जी को जिन्होंने... और ये कोई रातों-रात नहीं हुआ। ये खाली कोई इसमें अगर कोई सोचे कि रातों-रात हो गया, मैं ये कहना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर सिर्फ

और सिर्फ बच्चों का रिजल्ट ऐसे नहीं आया, इसके पीछे एक बहुत बड़ी लगन थी, दिन-रात की मेहनत थी। मैं समझ नहीं पाता कि मनीष जी सोते भी हैं कि नहीं। दिन-रात स्कूलों का विजिट करते हैं। एक-एक स्कूल जाते हैं। 56 मॉडल स्कूल बने हैं जिसमें से एक मेरी विधान सभा में बन रहा है। कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इस देश के सबसे बड़े संस्थान डीपीएस जैसे स्कूल को इन्फ्रास्ट्रक्चर के मामले में कभी हम कभी पीछे छोड़ सकते हैं क्या! लेकिन आज मैं ये कहना चाहता हूं कि कि आज सरकारी स्कूल की जो बिल्डिंग बनायी जा रही हैं, जिसके अन्दर ग्रेनाइट पत्थर का इस्तेमाल हो रहा है। कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी पॉसिबल है क्या! ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि यहां के गेस्ट टीचर जिनको 16-17 हजार रूपये सैलरी मिलती है, जो दिन-रात मेहनत करके बच्चों को पढ़ाते हैं, ऐसा भी नहीं सोचा था कि कोई सरकार ऐसी आयोगी कि उनकी सैलरी डबल कर देगी, 34 हजार रूपये भी सैलरी हो सकती है! यह इस सरकार ने करके दिखाया है और इन सब का मिला-जुला परिणाम है कि आज दिल्ली के अंदर शिक्षा का स्तर सुधरा है वरना वही गुजरात मॉडल के अंदर 5500 रूपये में सरकारी स्कूल के अंदर गेस्ट टीचर पढ़ाने पर मजबूर है और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं गुजरात का प्रभारी रहने के नाते, डेढ़ साल मैंने वहां काम किया है और वहां शिक्षा की हालत जो खराब है, वहां के सरकारी स्कूलों की बदतर हालत है, उसको मैं शब्दों कह ही नहीं सकता। लेकिन हमारी सरकार ने दिन-रात यह काम किया है। हम अक्सर पंक्तियां पढ़ते हैं, हम अक्सर दोहे पढ़ते हैं और उन दोहों को पढ़कर छोड़ देते हैं। जिंदगी में उनको लागू करने की बहुत कम लोगों में ऐसी नीयत होती है कि अपनी जिंदगी में लागू कर

लें। लेकिन मनीष जी ने, मैं सोचता हूं, इस पंक्ति को कितना सार्थक साबित करके दिखा दिया है कि :

कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा,

अर्जुन सा तीर साध, मरूस्थल में भी जल निकलेगा।

इन्होंने उस मरूस्थल में जल निकाल कर दिखाया है कि कभी सोच नहीं सकते थे कि सरकारी स्कूलों की स्थिति क्या ऐसी हो सकती है। आठ हजार सरकारी स्कूलों में कमरे, दो साल के अंदर बहुत लार्ज स्केल पर सभी स्कूलों के अंदर काम चल रहा है। तो जिस तरह से यह काम पिछले दो साल में हुआ है, मेरे यहां पर राजकीय प्रतिभा विद्यालय है, जिसमें एक साइंस के विद्यार्थी हैं 92.4 परसेंट जो कि सैक्टर-10 में स्कूल स्थापित है, उसके बाद छावला गांव से हमारी एक बहन है सरिता जैन, जिन्होंने 93.6 फीसदी नंबर लिए हैं और मैं आज इस सदन के माध्यम से आपने बोलने का मौका दिया, मैं उन सभी अभिभावकों को, उन बच्चों को जिन्होंने कड़ी मेहनत करके न सिर्फ अपने पेरेंट्स का नाम रोशन किया है, दिल्ली का नाम रोशन किया है, देश का नाम रोशन किया है, उन सभी के साथ-साथ सभी अध्यापकों को और माननीय शिक्षा मंत्री सिसोदिया जी को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि अभी हमारे पूरे तीन साल बाकी हैं और मैं दावे के साथ कहता हूं जब दिल्ली सरकार के पांच साल पूरे होंगे, तो सबसे अच्छा कार्य जो होगा, वो शिक्षा के अंदर होगा, जो इस देश को मजबूत बनाने की दिशा में सबसे बड़ा कदम होगा और एक ऐतिहासिक कदम पूरा करेंगे मनीष सिसोदिया जी पांच साल बाद और यह रिपोर्ट कार्ड अपना इसी सदन में पेश करेंगे। मैं

दावे के साथ कहता हूं कि आने वाले इसी साल के अंदर दिल्ली के सरकारी स्कूलों की स्थिति और ज्यादा बेहतर होगी। इसी बात के साथ मैं अपना वक्तव्य खत्म करता हूं। बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री नरेश यादव जी।

श्री नरेश यादव : धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

अध्यक्ष महोदय, यह अपने आप में ऐतिहासिक रिजल्ट आया है जो दिल्ली में गवर्नमेंट स्कूल्स ने 88.27 परसेंट जो रिजल्ट आया है, मैं इसके लिए बधाई देना चाहता हूं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने इतने अच्छे शिक्षा मंत्री दिल्ली को दिये और उन्होंने वो इतिहास रच दिया जो शायद कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। जब पहले-पहले बजट पेश किया गया और 106 परसेंट बजट बढ़ाया गया, उसी से ही साफ हो गया था कि माननीय शिक्षा मंत्री जी का, जो एक विजन है, वो शिक्षा के क्षेत्र में बिल्कुल अलग है। ऐसा कभी नहीं हुआ, किसी सरकार में नहीं हुआ कि कहीं इतना बजट रखा गया और उसके बाद में स्कूलों में जिस तरह से पूरा इंफ्रांस्ट्रक्चर और टीचर्स के लिए पूरा एक एसएमसी का गठन किया गया और जिस सिस्टम में काम किया गया, उसी का ही यह नतीजा है कि आज सरकारी स्कूलों का जो रिजल्ट आया है, उससे हम सब को गर्व महसूस हो रहा है।

अध्यक्ष जी, मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ हूं। जिस स्कूल से मैं पढ़ा हूं, उसका भी 93.8 परसेंट रिजल्ट आया है। मुझे गर्व महसूस हो रहा है और उसी स्कूल में एक छात्र ने 100 परसेंट हिस्ट्री में लिया है, यह भी अपने

आप में एक इतिहास है गवर्नमेंट स्कूल में और जिस तरह से मेगा पीटीएम की गई, रीडिंग मेला का आयोजन किया गया और एसएमसी की पूरी टीम ने काम किया, मैं सभी को अपनी तरफ से बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि इसी तरह से आगे काम चलता रहे। साथ में मनीष जी के साथ में, इनकी टीम में आतिशी जी ने बहुत मेहनत की है। एसएमसी की टीम वो जो सेंटर में होती थी, वो दिन-रात हम लोगों को फोन करती रहती थी। हम लोगों से अपडेट लेते रहते थे। स्कूलों के लिए उन्होंने फ्लैग्स बना रखे थे, रेड, ब्लू, ग्रीन, कि किस तरह से, किस स्कूल में, कहां कितना काम चल रहा है और हम लोगों से डे-टू-डे बेसिस पर अपडेट लेने का यह नतीजा है कि आज जो यह रिजल्ट आया है, यह सब की जो मिलकर मेहनत हुई है, उसी का यह नतीजा है और हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी का विजन है जो पहले बजट में दिखा, दूसरे बजट में दिखा और उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया सब टीचर्स के लिए भी और साथ में जो हमारे एजुकेशन ऑफिसर्स हैं, एजुकेशन डिपार्टमैंट है, टीचर्स हैं, मैं इन सब को इस बात की बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने दिन-रात जो मेहनत की है और जिस तरह से माननीय शिक्षा मंत्री जी स्कूलों में जाकर औचक निरीक्षण करते थे तो यह बिल्कुल क्लियर हो गया था सभी टीचर्स, प्रिंसिपल्स यह सोचने लगे थे कि अब शिक्षा के मामले में, एजुकेशन में इस दिल्ली सरकार ने, कोई किसी तरह का कम्प्रोमाइज नहीं करना और उन्होंने मान लिया था कि नहीं, अब तो हमने करना ही है। स्टार्टिंग में जब शिक्षकों के ऊपर थोड़ा सा दबाव बना, तब तो कुछ परेशान लगते थे। शिक्षक शिकायत करते थे कि यह क्या हो रहा है। लेकिन बाद में अब कुछ शिक्षकों से मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने खुद ने कहा कि

जैसे ही सरकारी स्कूलों का रिजल्ट आया है, हमें भी मान-सम्मान का अनुभव हो रहा है। हमें गर्व फील हो रहा है। आज आप लोगों ने सभी ने देखा होगा कि किस तरह से जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स थे, उनका मान-सम्मान घट गया था। लेकिन जैसे ही यह गवर्नमेंट स्कूल की शिक्षा व्यवस्था बदल रही है, रिजल्ट बदल रहा है, तो उनका भी सम्मान बढ़ता हुआ जा रहा है। उन्होंने दिन-रात मेहनत की है, तभी यह रिजल्ट ऐसा आया है। मैं इसके लिए बधाई देता हूं, सारे विधायकों को बधाई देता हूं, जिन्होंने अपनी एसएमसी की टीम के साथ में दिन-रात मेहनत की। एसएमसी टीम में जो लगे रहे, उनको भी मैं बधाई देता हूं और साथ में आतिशी जी और उनकी टीम को भी बध ाई देता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष महोदय : इससे पहले कि विजेन्द्र गुप्ता जी अपनी बात रखें और माननीय मनीष जी उत्तर दें, प्रवीण जी से रिक्वेस्ट आई है कि उस वक्त शोर-शराबे में मैं अपा संकल्प पूरा ठीक ढंग से नहीं पढ़ सका था, वो शुरू करें।

श्री प्रवीण कुमार : अध्यक्ष महोदय, एक बार यह मोशन मैं दोबारा सदन के सामने रखना चाहूंगा।

I intend to move the following congratulatory without notice under rule 114 in the House :

"Nothing with gratitude that the Government of NCT of Delhi led by Shri Arvind Kejriwal has been earmarking the highest percentage of its

budget for education and health, also noting with pride that the Minister of Education and Minister of Health are putting to the best use the the enhanced budget for the welfare of the people.

Appreciating the deligent and honest efforts put in by Shri Manish Sisodia in unleasing the revolutionary reforms in education sector, Nothing with a great sense of satisfaction that the Govt. Schools have positively responded to the constructive efforts of Shri Manish Sisodia by producing outstanding resuslts in CBSE 12th Standard exams and proving to be way ahead of the expensive schools of private sector.

This House congratulates Shri Manish Sisodia, Mrs, Atishi Marlena, the officers of GNCTD, most importantly each and every proud teacher, student and principal of all the Govt. Schools of Delhi for making such a stupendous result possible against all odds."

अध्यक्ष महोदय, मैं पूरे सदन को बधाई देना चाहता हूं कि जिस तरीके से इस साल यहां पर प्रदर्शन रहा गवनमेंट स्कूल का। बैठकर मैं एक चीज सोच रहा था कि अगर यह दो साल में आम आदमी पार्टी की सरकार यह चीज कर सकती है कि रिजल्ट 9 प्रतिशत ज्यादा प्राइवेट स्कूल से बढ़ा सकती है, अगर यह पिछली सरकारों ने ध्यान दे दिया होता तो इतने लोग यहां पर बैठे हैं इन सारे लोगों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे होते। लेकिन पिछली

सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। इस कारण से सरकारी स्कूल में सारी सुविधा मिलने के बावजूद, फीस माफ होने के बावजूद, कपड़े मिलने के बावजूद, किताबें मिलने के बावजूद, खाना मिलने के बावजूद वहां पर गरीबों के बच्चे पढ़ने जाते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता। लेकिन अगर हम ये सारी सुविधाएं दे रहे होते, अगर पिछली सरकारों ने थोड़ा सा ध्यान दे लिया होता तो हम सारे लोग अपने बच्चे वहीं पढ़ा रहे होते।

अध्यक्ष महोदय, वहीं पढ़ाते और एक और बात मैं रखना चाहूंगा, एक तरफ तो दिल्ली सरकार लगातार काम कर रही है, अपने स्कूलों को बढ़ाने के लिए, स्कूलों को मजबूत करने के लिए, शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए, दूसरी तरफ बीजेपी शासित एमसीडी है जो अपने वहां पर बच्चे पढ़ते हैं एमसीडी स्कूल में, उनकी इतनी बुरी हालत है, एमसीडी स्कूलों की, वहां पर शिक्षा व्यवस्था की इतनी बुरी हालत है, अगर वहां से बच्चा ढंग से पढ़कर छठी में अगर दिल्ली सरकार को मिल जाए तो ये 88 परसेंट का रिजल्ट जो है वो 100 परसेंट तक अगले साल ही पहुंच सकता है। बस अध्यक्ष महोदय, मेरी इतनी बात थी, बाकी बात रख दी है।

अध्यक्ष महोदय : बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री विजेन्द्र गुप्ता जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, जो प्रस्ताव यहां रखा गया है, बधाई प्रस्ताव, हम उससे सहमत नहीं है। दिल्ली की शिक्षा स्थिति में और विशेष रूप से विद्यालयों की स्थिति में लगातार गिरावट हो रही है। मैं कुछ तथ्यों के आधार पर ही यहां सदन के समक्ष कुछ बातें रखना चाहता हूं। दिल्ली के अंदर, दिल्ली सरकार के विद्यालयों में 30 हजार अध्यापकों के पद खाली पड़े

हैं जिनमें निरंतर हर वर्ष बढ़ोत्तरी हो रही है। मुझे समझ नहीं आता कि अगर विद्यालयों में अध्यापक नहीं हैं तो क्या सरकार को ये अधिकार है कि वो इस पर अपनी पीठ थपथपाए! दूसरा जिस कंपेरीजन की आप बात कर रहे हैं, सरकार के द्वारा जो आंकड़े पेश किये जा रहे हैं प्राइवेट स्कूल के नाम पर, उसमें जो प्राइवेट कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं 12वीं के, ये उनकी संख्या को जोड़कर यहां ये स्थिति बताई जा रही है। वास्तविकता ये है कि दिल्ली के अंदर बहुत बड़ी संख्या में लोग प्राइवेट स्टूडेंट के रूप में बिना किसी विद्यालय के परीक्षा में बैठते हैं।

दूसरा, आपको तथ्यों के आधार पर बताना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या दिन प्रतिदिन कम हो रही है। उसका कारण ये है कि शिक्षा का स्तर लगातार गिरा है जिसके कारण अभिभावकों का विश्वास कम हुआ है और गवर्नमेंट एडेड स्कूल लगभग ढाई सौ के करीब हैं, उनके अंदर भी अध्यापकों के पद जितनी बड़ी संख्या में खाली पड़े हैं, सरकार ने उसका कभी ध्यान नहीं दिया। पिछले वर्षों से अगर तुलना की जाए तो इस वर्ष मात्र सौ विद्यालय ऐसे हैं। ये जो संख्या बताई जा रही है, ये उत्तीर्ण अर्थात कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स को जोड़कर जिनका किसी कालेज के दाखिले पर आपस में एक दूसरे की पीठ थपथपाकर दिल्ली के लोगों के साथ, शिक्षा पर दोगुना खर्च करने की बात कहकर, एक ऐसा प्रस्ताव पास करते हें जिसके मैं समझता हूं कि ये सरकार काबिल नहीं है तो ये सरकार को आत्मविश्लेषण करना चाहिए कि सिर्फ आप मार्केटिंग कर रहे हैं या वास्तविकता में शिक्षा के स्तर में सुधार करना चाहते हैं। मैं आपके समक्ष

ये रखना चाहता हूं कि नवीं कक्षा में एक लाख बच्चे फेल हुए हैं, एक लाख बच्चे! ग्याहरवीं कक्षा में भी कुल बारहवीं कक्षा तक पहुंचने वाले बच्चों का लगभग 30 से 40 प्रतिशत जो हैं, वो फेल हुए हैं। यानि कि एक तरफ आप कहते हैं कि दिल्ली के अंदर, मैं जानना चाहता हूं अध्यक्ष जी, वो फेल हुए हैं। यानि कि एक तरफ आप कहते हैं कि दिल्ली के अंदर, मैं जानना चाहता हूं, अध्यक्ष जी, आपके माधयम से आप डीडीए को दोष देते हैं जमीन को लेकर, लेकिन शिक्षा विभाग बताए आंकड़ों के साथ कि दस साल में आपके पास कितने स्कूलों के लिए जमीन आपके पास है लेकिन आप उन पर विद्यालय बनाने में नाकाम हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपने क्षेत्र की बता सकता हूं। मैंने खुद शिक्षामंत्री जी के साथ बैठक की थी डेढ़ साल पहले, ये कहकर के कि स्कूल की जमीन है, उस पर स्कूल बनवाना शुरू कीजिए। उस पूरे क्षेत्र में स्कूल नहीं है लेकिन शिक्षा मंत्री के साथ बैठक करने के बाद करने के बाद भी आज तक फाईल एक कदम भी आगे नहीं चली है। पिछले वर्ष ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो बच्चों का दाखिला होना था, दस हजार सीटें खाली रह गई। दस हजार बच्चे और अतिरिक्त ईडब्ल्यूएस में भर्ती हो सकते थे, जो नहीं हुए, जिससे सीटें खाली रह गई। हमारा ये कहना है कि दिल्ली के देश भर की शिक्षा सरकारी विद्यालयों की अगर देखी जाए तो उसमें हम पाते हैं कि आज भी हमारा नंबर पीछे है, हम आगे नहीं हैं। जो बात यहां की जा रही है, देश की राजधानी हैं। हम क्या देश में दिल्ली के स्कूल्स, दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था क्या पहले स्थान पर है, क्या आप अपने दिल पर हाथ रखकर बताएंगे? हमारा साफ रूप से कहना है कि जो कुछ यहां पर कहा जा रहा है वो बढ़ा-चढ़ाकर कहा जा

रहा है। इसी सदन में ये कहा गया था कि आठवीं कक्षा के बच्चों का अक्षर ज्ञान तक नहीं है, इसी सदन में कहा गया था। कभी आपने 'चुनौती' एक कार्यक्रम अपने हाथ में लिया था, उसी चुनौती के माध्यम से आपने कितने बच्चे, उस चुनौती के कार्यक्रम से, आंकड़े आप कुछ भी पेश करिए, लेकिन प्रश्न ये है कि वास्तविकता क्या है उस कार्यक्रम की? शिक्षा के स्तर में लगातार गिरावट आई है। आपके जितने एक्सपेरिमेंट हैं, वो तमाम एक्सपेरिमेंट पर क्वेश्चन मार्क हैं। क्योंकि इसमें साफ रूप से ये महसूस हो रहा है कि दिल्ली के अंदर शिक्षा व्यवस्था बद से बदतर हुई है और परिणामों का एक जगलरी ऑफ फीगर्स करके अगर आप ये कहना चाहते हैं कि दिल्ली के सरकारी विद्यालयों से पढ़ने वाले बच्चे अब बहुत काबिल होकर के निकल रहे हैं, बहुत अच्छे अंक, आप पूरा परसेंटेज दीजिए 70 प्रतिशत से अधिक अंक लेने वाले और पासिंग मार्क्स को आप और वो भी कुछ एडीशनल सब्जेक्ट्स को जोड़कर अगर यहां वाहवाही लेने के लिए समाचार पत्रों में सुर्खियां बनाने के लिए और ये कहें तो फिर जनता सब देख रही है क्योंकि असली तो जनता उसका पूरा परिणाम बताएगी कि वास्तविकता क्या है। वास्तविकता में कहीं सुधार नहीं है, उसको सुधार की तरफ बढ़ना चाहिए और शिक्षा मंत्री जी को भी और विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी जिनसे हम ये अपेक्षा करते हैं कि वो सही बात कहेंगे, उसको ध्यान में रखकर बात करेंगे, धन्यवाद हम इस प्रस्ताव के पक्ष में नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री मनीष सिसोदिया जी आदरणीय उप-मुख्य मंत्री।

उपमुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करता

हूं कि उन्होंने शिक्षा विभाग के कार्य के प्रति, उसके प्रदर्शन के प्रति एक प्रस्ताव सदन में पेश किया, मैं उसमें कुछ और चीजें सदन के समक्ष रखना चाहता हूं, लेकिन तहे दिल से आभार है। मैं सभी सदस्यों का, दिल्ली के सभी बच्चे जो दिल्ली के स्कूलों में पढ़ते हैं, उनकी तरफ से, सभी पेरेंट्स की तरफ से, सभी शिक्षकों की तरफ से, सभी प्रिंसिपल्स की तरफ से, अपने सभी शिक्षा विभाग के अधिकारियों की तरफ से, अपने सभी एसएमसी मेम्बर्स की तरफ से, इस विधानसभा का, इस सदन का धन्यवाद करता हूं कि आपने और अपने सभी एडवाइजर्स की तरफ से क्योंकि बहुत सारे एडवाइजर्स, वालियंटर्स दिन रात काम कर रहे हैं एजुकेशन को लेकर, उन सबकी तरफ से सदन का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस शिक्षा के काम को इस योग्य समझा कि इस सदन में उस पर थोड़ी सी चर्चा हो, उसके ऊपर उसको एप्रीसिएशन मिले।

लास्ट में, विजेन्द्र गुप्ता जी ने कहा आंकड़ों की जगलरी, ये जगलरी जुमले हमारे काम नहीं हैं, जगलरी और जुमले तो आपके काम हैं। हमारे काम तो क्योंकि देखिये, एक बुनियादी अंतर है और उनका मुझे पता था कि उनका समर्थन इस मुद्दे पर मिलेगा नहीं। क्योंकि ये फर्जी राष्ट्रवाद में यकीन करते हैं। हम शिक्षित राष्ट्रवाद में यकीन करते हैं। हमारे लिए शिक्षित राष्ट्र, समर्थ राष्ट्र है। इनके लिए फर्जी राष्ट्रवाद से राष्ट्र निकलता है। तो मुझे इनसे जो अपेक्षा थी, इन्होंने वही किया जो इनसे अपेक्षा थी क्योंकि देश के गरीब बच्चे अगर पढ़ने लगें तो इनका फर्जी राष्ट्रवाद एक मिनट नहीं टिकेगा। देश के गरीब बच्चों को अगर अच्छी शिक्षा मिल जाए तो किसी का फर्जी राष्ट्रवाद एक

मिनट नहीं टिकेगा, सब हवा निकल जाएगी इसीलिए ये विरोध करते हैं इस चीज का।

अध्यक्ष महोदय, कुछ आंकड़े रखे गये।

उप मुख्य मंत्री : मैं ये कहना चाहता हूं कि दिल्ली का क्या, देश का भी, क्योंकि शिक्षा में कम्पेरिजन कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। इस राज्य का इतना, इस राज्य का इतना, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि माननीय नेता प्रतिपक्ष को कि देश भर में बीजेपी शासित जितने भी राज्य हैं, किसी भी एक व्यक्ति से जिसको थोड़ा बहुत मैथमैटिक्स आता हो, ऐसे ही नहीं, किसी जग्लरी से नहीं, बीजेपी शासित जितने भी राज्य हैं, उनका रिजल्ट और दिल्ली का रिजल्ट कम्पेयर करवा लीजिये, आपके बीजेपी शासित राज्यों से दोगुना न निकल जाये तो बताना।

अध्यक्ष महोदय, मैं ये कह रहा था कि फेल होना, कम्पेयर करना, मुझे व्यक्तिगत रूप से कोई बहुत अच्छा नहीं लगता है कि किस राज्य में कितने बच्चे फेल हुए क्योंकि सिर्फ दिल्ली का नहीं, देश का भी कोई भी बच्चा फेल होता है तो मुझे लगता है कि देश फेल हो रहा है। मुझे ये लगता है। वो चाहे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक किसी भी राज्य का, किसी भी स्कूल का, चाहे सरकारी स्कूल का बच्चा फेल हुआ हो या प्राइवेट स्कूल का बच्चा फेल हुआ हो, व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि कहीं न कहीं उसके अंदर अंश भर देश फेल हुआ है। इसलिए हम इस बात को सैलिब्रेट न करें लेकिन दिल्ली सरकार के शिक्षकों के काम की सराहा करते हुए, यहां

के बच्चों की सराहना करते हुए, मैं इस सदन के सामने कुछ डेटा रखना चाहता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन सदन के रिकार्ड में रहे, दो साल से ये सदन लगातार शिक्षा पर दिल्ली सरकार का, दिल्ली की जनता का 25 परसेंट बजट का हिस्सा लगभग लगभग एक चौथाई हिस्सा खर्च करता रहा है, खर्च करने की अनुमति देता रहा है। उसका आउट कम क्या है? उसका आउट कम ये है कि इस बार हमने दिल्ली में नकल रोकने के लिए बहुत जबर्दस्त अभियान चलाया। मुझे कई अधिकारियों ने भी कहा, मुझे कई शिक्षकों ने भी कहा कि साहब आप थोड़ा बहुत तो सॉफ्ट कार्नर रखिये। मैंने कहा कि ये नकल करके पास किया हुआ देश नहीं चाहिए। पांच परसेंट नीचे आ जायेंगे रिजल्ट में, कोई दिक्कत नहीं है लेकिन इस बार हम इसी को अचीवमेंट मानेंगे। उसके बावजूद रिजल्ट अच्छा रहा। रिजल्ट कम नहीं हुआ उसके बावजूद। ये एक बड़ी उपलब्धि है। दूसरा बड़ी चीज है कि इस बार हंड्रेड मार्कस लाने वाले बच्चे बढ़े, जिन बच्चों के सौ में से सौ नंबर आये। अभी भावना जी ने किसी का जिक्र किया और कुछ साथियों ने किया। इस बार संख्या उनकी बढ़ी है। इस बार उनकी संख्या बढ़ के 33 हो गई है, ये बड़ी चीज है। इस बार हंड्रेड परसेंट रिजल्ट लाने वाले हमारे स्कूल 112 हैं, ये छोटी संख्या नहीं है। इस बार 90 परसेंट से ज्यादा रिजल्ट लाने वाले हमारे स्कूल 554 हैं सरकार के। ये बढ़ी है संख्या पिछले साल से और लगातार बढ़ रही है 70 परसेंट 60 परसेंट का इन्होंने जिक्र किया, उसका भी डेटा इनको उपलब्ध करा देंगे लेकिन जरा बीजेपी शासित राज्यों का डेटा भी अगर हमको तो नेट पर मिल गया है, मंगा रहे हैं, हम ले रहे हैं लेकिन आप भी कम्पेयर करके देखियेगा।

अध्यक्ष महोदय, अच्छी चीज है कि ये देश में केन्द्रीय विद्यालय बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और केन्द्रीय विद्यालयों का रिजल्ट हमेशा अच्छा रहा है। वो इस बार भी 94.6 परसेंट रहा है। देश भर में केन्द्रीय विद्यालय भारत सरकार चलाती है लेकिन दिल्ली सरकार जो आरपीवीवी चला रही है, प्रतिभा विकास विद्यालय चलाती है, उसका रिजल्ट 99.72 परसेंट है। केन्द्रीय विद्यालय के मुकाबले दिल्ली के प्रतिभा विकास विद्यालय कहीं आगे रहे हैं दिल्ली में। मैं अभी डेटा देख रहा था जो सीबीएससी का स्पेशियली था, उसको भी मैं देख रहा था। पूरे दिल्ली का जो पास आउट परसैन्टेज है, वो 88.37 परसेंट है और पूरे देश के प्राइवेट स्कूल्स का जो सीबीएसई एफिलेटिड हैं, विजेन्द्र गुप्ता जी ने कहा कि कुछ कुछ जो बच्चे प्राइवेट एग्जाम देते हैं, उनका भी शामिल हो गया। विजेन्द्र गुप्ता जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा देख लें। ये सीबीएसई का रिजल्ट है, ओपन स्कूल का रिजल्ट नहीं है। ओपन स्कूल के रिजल्ट से कन्फयूज न हों। 79.27 परसेंट देश भर के प्राइवेट स्कूल्स का रिजल्ट रहे हैं। पूरे देश के गवर्नमेंट स्कूल्स जो सीबीएसई के स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट के, वो 82 परसेंट पर थे, 82.29 परसेंट। उनसे दिल्ली के सरकारी स्कूलों से दिल्ली के स्कूल छह परसेंट आगे रहे हैं। पूरे देश के प्राइवेट स्कूलों से 9 परसेंट आगे रहे हैं। ये छोटा नहीं है। कम से कम एक ऐसे समय में, जब पूरे देश में और खास तौर से बीजेपी शासित राज्यों में, बीजेपी शासित नगर निगम में सरकारी स्कूल बंद किये जा रहे हैं। सरकारी स्कूलों की जगह इनके अपने पार्टी के नेताओं के प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इनके अपने मौसेरे भाई वाले यहां नेता जो हैं, उनके भी प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दिया

जा रहा है। ऐसे समय में गवर्नमेंट स्कूल्स पर खर्च करना, गवर्नमेंट स्कूल पर मेहनत करना और उसके बदले में गवर्नमैंट स्कूल्स के बच्चों का बेहतर रिजल्ट आना, हमारे लिये फख्र की बात है, देश के लिये फख्र की बात है। क्योंकि हम वापिस... मैं कह रहा हूं इसे लाईन मेकिंग करते हैं 'शिक्षित राष्ट्र समर्थ राष्ट्र।' राष्ट्र शिक्षित होगा तो समर्थ होगा।

मैं, अध्यक्ष महोदय, अंत में शुक्रिया अदा करता हुआ, एक चीज और क्योंकि उपलब्धियां कम नहीं हैं, पहली बार दिल्ली के 372 बच्चे सरकारी स्कूलों के जेई मेन्स के ईग्जाम में पास कर पाये हैं। इतनी बड़ी संख्या में कभी भी, बहुत नेग्लीजेबल संख्या होती थी आरपीवीएस के कुछ बच्चों की। इस बार जब जेई का रिजल्ट आया, जब चारों तरफ से मुझे प्रिंसीपल्स के एसएमएस आने शुरू हुए, आफिसर्स के फोन आने शुरू हुए कि जी फलां स्कूल में इतने बच्चे हो गये, इसमें दस हो गये, इसमें 8 हो गये। बहुत सारे प्रिंसीपल्स ने अच्छा काम किया और पहली बार 372 बच्चे शानदार इंजीनियरिंग कालेज में जा के जेई ट्रीपल-ई जा के आईआईटी जैसे संस्थानों में जा के पढ़ेंगे, ये छोटी बात नहीं है। पहली बार ऐसा हुआ है और अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिये, प्राइवेट स्कूलों में जो बच्चे जाते हैं, उमें से सबकी नहीं लेकिन बहुत सारे लोगों की तनख्वाह दस-दस, पंद्रह-पंद्रह लाख भी होती है, दो-दो तीन तीन लाख भी होती है। जिनकी दो तीन लाख होती है, पचास हजार होती है, वे बेचारे किस तरह से मेहनत करके अपना पेट काट के अपने परिवार का खर्चा काट के कैसे प्राइवेट स्कूल की फीस और कैपिटेशन फीस देते हैं, ये हम सब जानते हैं लेकिन सरकारी स्कूलों में जो बच्चे आ रहे हैं, उनके

माता-पिता की तनख्वाह बामुश्किल पंद्रह सोलह हजार है। बहुत सारे बच्चों की 50 परसेंट बच्चे ऐसे हैं, मैं तो जाता हूं स्कूलों में बच्चों से पूछता हूं कि आपके पेरेंटस क्या करते हैं, आपके पेरेंटस क्या करते हैं? 70-80 परसेंट बच्चों के पेरेंटस बेहद गरीब, दस से पंद्रह हजार मुश्किल से उनके परिवार की आमदनी होगी, उसमें किसी खोली का, किसी घर का, किसी कमरे का किराया भी देते हैं। अपनी आजीविका भी चलाते हैं, अपने बच्चों को भी थोड़ा बहुत सुविधाएं देते हैं। उनको पढ़ाना, मुझे लगता है, उनके लिए कुछ करना पुण्य का काम है। वो बहुत जरूरी है, वो हम कर रहे हैं। हमारे जो इतने बच्चे पास हुए हैं, जो टॉपर हैं, उसकी मदर ने मुझे बताया कि...

...(व्यवधान)

उप मुख्य मंत्री : 99.7 प्रतिभा स्कूल के बच्चों के आये हैं। वो बच्ची जिसने टॉप किया है, उस बच्ची की मदर मुझे बता रही थी कि हमारे घर में अगर लाईट चली जाये तो हम अपने बच्ची के लिये इनवर्टर नहीं ला सकते। बच्ची पढ़ने में बहुत अच्छी थी ढांसा गांव की। वो बता रही थी कि हम तो मोमबत्ती जला के अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। वो बच्ची अगर सरकारी स्कूल से पढ़ाई करके टॉप हो रही है तो ये हमारे सरकारी स्कूल के अध्यापकों के लिये, सरकारी स्कूलों के तमाम लोगों के लिये जो सरकारी स्कूलों पर काम कर रहे हैं, गर्व की बात है, फख्र की बात है। मैं आंकड़ों में नहीं जाता। मेरी ख्वाहिश ये है कि ये प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल का सारा झंझट खत्म करके सारे कम्पैरिजन खत्म करके दिल्ली के एक एक बच्चा पास हो, दिल्ली

के सारे बच्चे पास हों और आने वाले वर्षों में हम प्राइवेट स्कूल का रिजल्ट भी 100 परसेंट देखें, गवर्नमेंट स्कूल का रिजल्ट भी हम 100 परसेंट देखें और देश भर के सारे स्कूल का रिजल्ट हम 100 परसेंट देखें।

मैं ऐसी कामना के साथ सभी शिक्षा को, बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस सदन का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इसने दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग के काम को सराहना के योग्य समझा, बहुत-बहुत धन्यवाद।

इस सदन का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इसने दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग के काम को सराहना के योग्य समझा, बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : अब श्री मनीष सिसोदिया जी, माननीय उप मुख्य मंत्री, दिल्ली माल और सेवा कर विधेयक...

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ता : सर, आपे मुझे कहा था कि...स्टेटमेंट देने दिया जाएगा अस्पतालों पर।

अध्यक्ष महोदय : किस पर? देखो विजेन्द्र जी, अब हो गया विषय वो।

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ता : हुआ ही नहीं।

अध्यक्ष महोदय : वो इतना समय, अब दो मिनट भी समय नहीं है प्लीज। नहीं, अब मैं कोई एलाउ नहीं कर रहा हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिए, इतना समय सदन का खराब हो गया है। प्लीज, अब कुछ नहीं।

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ता : हम दो मिनट अपनी बात कहेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक सैकेंड अब श्री प्रवीण कुमार जी, माननीय सदस्य

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिये विजेन्द्र जी, ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था कि हम कितना सदन का समय खराब कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको दिक्कत क्या है?

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ता : मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अस्पतालों के मामले में क्या विपक्ष....

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अभी जीएसटी के बिल पर...क्यों हम लोग इतना परेशान नहीं हो रहे हैं?

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ता : हम बैठे थे लेकिन...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, चलिए

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ता : दिल्ली के अस्पतालों की हालत...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब श्री प्रवीण कुमार जी।

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ता : बहुत स्थिति दयनीय है।

अध्यक्ष महोदय : अब श्री प्रवीण कुमार जी, माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव सदन के सामने है;

जो इसके पक्ष में है, वो हां कहें,

जो इसके विरोध में है वो न कहें,

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता,

प्रस्ताव पारित हुआ।

विधेयक का पुर:स्थापन, विचार और पारण

अब श्री मनीष सिसौदिया, माननीय उप मुख्य मंत्री, 'दिल्ली माल और सेवा कर विधेयक 2017, (वर्ष 2017 का विधेयक संख्या-3)' को सदन में इन्ट्रोड्यूस करने की परमिशन मांगेंगे।

उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि 'दिल्ली माल और सेवा कर विधेयक 2017, (वर्ष 2017 का विधेयक संख्या-3)' को सदन में इन्ट्रोड्यूस करने की अनुमति प्रदान की जाए।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रस्ताव सदन के सामने है;

जो इसके पक्ष में है वो हां कहें,

जो इसके विरोध में है वो न कहें,

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता,

प्रस्ताव पारित हुआ।

अब माननीय उप मुख्य मंत्री विधेयक को सदन में इन्ट्रोड्यूस करेंगे।

उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की अनुमति से 'दिल्ली माल और सेवा कर विधेयक 2017, (वर्ष 2017 का विधेयक संख्या-3)' को सदन में इन्ट्रोड्यूस करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, इन्ट्रोड्यूस करते वक्त मैं इस विधेयक के संबंध में कुछ बहुत संक्षिप्त में सदन की जानकारी के लिए और सदन के रिकार्ड के लिए रखना चाहता हूं।

भारत के संविधान में '101वां संशोधन' करते हुए 8 सितम्बर, 2016 को देश की संसद ने केन्द्र और राज्यों को जीएसटी लगाने के लिए विधायी शक्तियां दी हैं। ये जो विधेयक मैंने प्रस्तुत किया है, ये जीएसटी के कर के प्रावधानों को, टैक्स के प्रावधानों को लगाने के लिए प्रस्तावित हैं, राज्य की शक्तियों के लिए। जीएसटी, मैं समझता हूं कि मैं, एम्पावर्ड कमेटी जो जीएसटी काउन्सल की बैठकों में जितना समय रहा हूं और जितना मैंने इसका अधययन किया है, एक अच्छा प्रस्ताव है। पूरे देश में टैक्स की चोरी, तुलनात्मक चोरी रोकने के लिए और नागरिकों की सुविधा के लिए, व्यापारियों की सुविधा के लिए ये एक अच्छा प्रस्ताव है। 'जीएसटी का कानून, जीएसटी की प्रस्तावना।' इसको काफी विचार विमर्श के बाद कानून के रूप में तैयार किया गया। मुझे लगता है ये अप्रत्यक्ष करों में अब तक का देश का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म है, इसका हम स्वागत करते हैं। इसमें 17 तरह के टैक्सिस को मिलाकर एक टैक्स जीएसटी बनाने का प्रस्ताव है। इसमें राज्यों के पास भी अधिकार रहेंगे, केन्द्र के जो डिपार्टमेंट हैं, उनके पास भी अधिकार रहेंगे। ये शायद दुनिया भर में पहला ऐसा कानून है, जहां तक मेरी जानकारी है, क्योंकि कई देशों में जीएसटी कानून लागू हुए। कहीं पर केंद्र सरकार उसको नियंत्रित करती है, कहीं पर राज्य सरकारें नियंत्रित करती हैं और वो पैसा इकट्ठा करके केंद्र को देती हैं, कहीं केंद्र इकट्ठा करके राज्य को देते हैं। यहां जीएसटी काउन्सिल

संविधान की पहली ऐसी फेडरल संस्था है जो फैसले लेगी राज्यों के बिहाफ पर भी और केन्द्र के बिहाफ पर भी और राज्य के मंत्री केन्द्र के मंत्री बैठकर उसमें फैसले लेंगे। ये एक अच्छा फेडरल स्ट्रक्चर का सबूत है। इसके कुछ प्रासीजरल इश्यूज हैं। मुझे लगता है, मानीय सदस्यों की चर्चा के बाद उस पर मैं जरूर कुछ कहना चाहूंगा लेकिन फिलहाल मैं इस विधेयक को सदन में इन्ट्रोड्यूस करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब ये प्रस्ताव सदन के सामने है,

जो इसके पक्ष में है वो हां कहें,

जो इसके विरोध में है वो न कहें,

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता,

प्रस्ताव पारित हुआ।

अब श्री मनीष सिसोदिया जी माननीय उप मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि सदन में पुर:स्थापित 'दिल्ली माल और सेवा कर विधेयक 2017, (वर्ष 2017 का विधेयक संख्या-3)' पर विचार किया जाए।

उप मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन में पुर: स्थापित 'दिल्ली माल और सेवा कर विधेयक 2017, (वर्ष 2017 का विधेयक संख्या-3)' पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रस्ताव सदन के सामने है,

जो इसके पक्ष में है वे हां कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे ने कहें,

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता,

प्रस्ताव पारित हुआ।

अब माननीय सदस्य चर्चा में भाग ले सकते हैं। सोमनाथ भारती जी।

प्रतिवेदन पर सहमति

श्री सोमनाथ भारती : अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, मैं इसके ऊपर अपने विचार रखूं, इसके पहले मैं दो बातें कहना चाहता हूं। चूंकि मनीष जी आशा कर रहे थे कि विजेन्द्र गुप्ता जी भाजपा की तरफ से हमें मुबारकाबाद देंगे, हमारे रिजल्ट्स के ऊपर। मनीष जी, ये हमारे क्या होंगे, ये अपने के नहीं हैं। माननीय आडवाणी जी जिनको राष्ट्रपति बनने का एक मौका था, वो राष्ट्रपति बनाने की बजाय उनको वहां जेल भेजने की प्लानिंग कर रहे हैं ये। ये तो अपने के न हुए।

...(व्यवधान)

श्री सोमनाथ भारती : अध्यक्ष महोदय, मैं स्कूल पर दो बातें रखना चाहता था।

अध्यक्ष महोदय, जब ये रिजल्ट आया था क्योंकि मैं मॉर्निंग में पार्कों में जाता हूं। पार्कों के अंदर जो बड़े-बड़े लोग घूमने आते हैं, मैंने उनको आपस में बात करते सुना। एक दूसरे को कह रहे थे कि ये तो बड़ा गजब हो गया, 'आम आदमी पार्टी' की सरकार में तो सरकारी स्कूल बेटर हैं। हमने फालतू के अपने लाखों रूपये खर्च कर दिए प्राइवेट स्कूलों के पीछे। तो मुझे इस पर बड़ा गर्व महसूस हुआ और लगा कि हमारी सरकार ने कोई ऐसा काम करके दिखाया है जो इतिहास के अन्दर किसी भी सरकार ने आज तक नहीं किया होगा और मनीष जी, उसमें कारण उसका ये है कि दुनिया में दो ही वर्ग है 'एक शोषक एक शोषित'। हमारी सरकार शोषितों की सरकार है। सरकार, जो कि सरकारी स्कूलों पर इतना पैसा खर्च करे, जो आम आदमी की एम्पावर्ड करने की तैयारी करने का प्रयत्न कर रही है, उससे तो इनको तकलीफ होगी और बहुत तकलीफ होगी क्योंकि आप बेजुबानों को जुबान दे रहे हैं। आप उनको बोलने की ताकत दे रहे हैं जिनको कि ये कुचला करते हैं। जिस तरह सहारनपुर के अन्दर कुचला जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, इनको तकलीफ होगी।

अध्यक्ष महोदय : सोमनाथ जी, जीएसटी पर प्लीज। आपकी बात हो गयी।

श्री सोमनाथ भारती : अध्यक्ष महोदय, क्योंकि आज जीएसटी पर चर्चा में मुझे आपने, अक्सर मुझे आप आखरी में कहत थे, आज पहले ही कह दिया तो मैं इस डिस्कशन को इनिशएिट करते हुए अध्यक्ष महोदय सबसे पहले मनीष जी को मैं मुबारकबाद दे दूं कि मनीष जी, कम से कम इस बहाने एक फुलफ्लेज्ड स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर का आपको दर्जा दिया गया। आप ओरों

के साथ बैठते हैं जाकर वहां पर, तो आपको बहुत-बहुत मुबारकबाद और चूंकि ये कहने को नहीं है क्योंकि आपने करके दिखाया है। मैं कई बार ये कह चुका हूं। आपने जब अपने बजट के अन्दर कहा था कि पहली ही सरकार है जिन्होंने अपने बजट स्पीच में फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि हमारे लिए इलैक्ट्रोल प्रॉमिसिज सिर्फ प्रॉमिसिज नहीं हैं, वो एक कन्ट्रैक्चूअल ऑब्लगेशन है। ये आपने अपनी पहली बार करके कहा। इसके लिए बहुत-बहुत आपको मुबारकबाद देता हूं और आप वही हैं जिन्होंने इस देश को और इस दुनिया को करके दिखाया कि टैक्स को, टैक्स के रेट्स को लोअर करने के बावजूद आपने पीछे तेरह आइटम्स के ऊपर साढ़े बारह परसेंट से पांच परसेंट आपने रेट को लोअर किया था उसके बावजूद दिल्ली के अंदर टैक्स कलैक्शन ही नहीं, टैक्स का कम्पलाइंस भी बढ़ा। अध्यक्ष महोदय, इसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मुझे याद है और अभी मनीष जी ने अपनी पीसी के अंदर भी कहा कि स्टेट का बजट बत्तीस हजार करोड़ से साठ हुआ था और आज ये बहुत गर्व की बात है, पूरे सदन के लिए गर्व की बात है कि ये स्टेट का बजट अब आज की तारीख में अड़तालीस हजार करोड़ हो गया, ये बहुत बड़े गर्व की बात है अध्यक्ष महेदय और ये ऐसा नहीं है कि इसमें कोई कन्ट्रीब्यूशन आया सैन्ट्रल गर्वमेंट की तरफ से। सैन्ट्रल गवर्नमेंट का कन्ट्रीब्यूशन तो जहां का था, वहीं है। तो ये बड़े गर्व की बात है कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने एक ईमानदार आदमी की कूबत का नमूना पूरे देश को, पूरे संसार को पेश किया जिसके अंदर बत्तीस हजार करोड़ का बजट दो साल के अंदर बढ़कर अड़तालीस हजार करोड़ हो गया, अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय, चूंकि फाइनेंस मिनिस्टर हमारे शिक्षा मंत्री भी हैं और शिक्षा के अंदर जो अभी हमने सदन के जरिए रेजलूशन पास करके दिखाया है, अध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही शानदार कार्य मनीष भाई ने एजुकेशन और फाइनेंस के अंदर करके दिखाया है, वो हम सबको गौरवान्वित करता है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदया, चूंकि मानीय केजरीवाल साहब यहां पर बैठे हुए हैं, I want to thank him कि इन्होंने इतना एबल फाइनेंस मिनिस्टर और एजूकेशन मिनिस्टर दिल्ली को दिया। मैं पीछे पूरा देख रहा था दिल्ली का इतिहास और मुझे वहां जो अचीवमैंटस हमारी सरकार के रहे हैं, शिक्षा में और फाईनेंस में, आज तक दिल्ली के राजनीतिक इतिहास में कोई भी एजुकेशन मिनिस्टर और किसी भी फाईनेंस मिनिस्टर ने इतना अव्वल काम करके नहीं दिखाया, अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय, मैं ओर राज्यों के रिजल्ट्स भी देख रहा था, उसके अंदर भी दिल्ली बहुत आगे निकली है। अध्यक्ष महोदय, लीगल और टैक्नीकल अंडरस्टैंडिंग, चूंकि जीएसटी की, जो जीएसटी का बिल आज दिल्ली के अंदर पेश हुआ है, जैसा मनीष जी ने बताया 17 टैक्सेज को एक करके इसके जरिये जो देश के अंदर 'One country one tax' की एक प्रक्रिया करने का प्रयत्न किया गया है और उसमें मनीष जी ने पिछले दिनों जब ये कार्यक्रम किया अरविन्द सुब्रहमणयम साहब का, उसके जरिये एमएलएज को एजूकेट करने का प्रयत्न किया, चूंकि संविधान के अंदर, 7वें शैडूयल के अंदर जितने भी टैक्सेज हैं; list one and list two के अंदर उसके अंदर देख करके लग रहा था कि जो कन्फ्यूजन है, टैक्सेज के अंदर, उस कन्फ्यूजन को हटाने का प्रयत्न किया गया लेकिन जो साथ में एटैच कर दिया गया कि रियल एस्टेट जो

आपने भी उस डिस्कशन के दौरान बात कही थी और मैं आपको मुबारकबाद देता हूं अध्यक्ष महोदय कि आपने भी और मनीष जी ने भी you did call a spade a spade and for that I must congratulate. आपने बात कही कि रियल एस्टेट और अल्कोहल को छोड़ने का क्या मतलब बनता है, ऐसे कौन से कारण हैं जिसके कारण और ये हमने भी कहा और अरविन्द जी जो आये थे चीफ इकोनोमिक एडवाईजर उन्होंने भी कहा इस बात को, उन्होंने बकायदा एक आर्टिक्ल लिखा और कहा कि किन कारणों से अल्कोहल को और रियल एस्टेट को छोड़ा गया है, एक चिंता का विषय है।

अध्यक्ष महोदय, चूंकि ये किस तरह से आम आदमी की जिन्दगी को अफैक्ट करेगा और किस तरह से ये चूंकि सबसे पहले हम सल्स टैक्स में थे, सेल्स टैक्स से वैट में आये और वैट से हम जीएसटी में जा रहे हैं तो इसके जो टैक्सेज और जो मल्टीपल टैक्सेज का एक तरह से भुगतान करना पड़ रहा था कन्जूमर्स को, उससे जो बचाव होगा, अब जितना वैल्यू एडेड होगा, उस पर ही टैक्स लग पाएगा और पूरे देश के अंदर सैल्स टैक्स से ऊपर उठकर वैट और वैट के ऊपर जीएसटी आने से टैक्स का जो रिजीम है, पूरे देश के अंदर वो एक हो जाएगा। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं कि ये जो हमारे आगे जो बिल हाउस के अंदर पेश हुआ है, उसके बाद दिल्ली भी उसमें शामिल हो जाएगा, अध्यक्ष महोदय और आज मैंने चूंकि ये एक टैक्नीकल सब्जैक्ट है, उसके साथ-साथ में जिस तरह से ये हमारी जिन्दगी को अफैक्ट करेगा, उसमें मैंने आम आदमी से भी जानना चाहा कि भई, किस तरह से आपको लग रहा है, किस तरह से ये आपको अफैक्ट करेगा तो कुछ लोगों

ने अपने सुझाव दिये उसके अंदर। अध्यक्ष महोदय, हमने कुछ सुझाव नोट किये हैं और उसमें से मैं कुछ पढ़ना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, एक आम बिजनेसमैन क्या कहता है, जब मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या कहना है इसके बारे में तो कहा है कि It is essential to many central and state levies however, the rates applied are too many. There should have been one law for essential commodities affecting the poor and another higher not more than 18% and then they could have added a sin tax for items like colas, chunk snacks, cigarettes, alcohol etc, the groups of items that you can brand unhealthy.

अध्यक्ष महोदय, इसमें उन्होंने खासकर ये भी कहा, अभी मनीष जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि रियल एस्टेट और एल्कोहल इसीलिये एड नहीं किये गये क्योंकि उसमें पोलिटिशन्यस एन्वॉल्व है, अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, एक आम हाउस वाइफ कह रही है कि जीएसटी अच्छा तो है लेकिन हायर टैक्स स्लैब में, चूंकि इसमें 5 स्लैब बनाए गये हैं, जीरो परसैंट, 5 परसैंट, 12 परसैंट, 18 परसैंट, और 28 परसैंट। तो अभी बहुत सारे आइटम्स ऐसे हैं, जो कि हायर टैक्स स्लैब में हैं, अध्यक्ष महोदय। मनीष जी से मैं गुजाशि करूंगा कि जब दिल्ली के लिये यह बने तो उसमें ऐसा ख्याल रखें कि जो आम जरूतमंद की चीजें हैं, उसको हॉयर टैक्स स्लैब में न रखके, उसको नीचे के टैक्स स्लैब में रखा जाये, अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय, एक एनजीओ ने मुझसे कहा कि सैनेटरी नैपकिन्स जो अभी 12 परसैंट पे है, उसको टैक्स फ्री किया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, किसी ओर ने कहा कि एक Industrialist GST apparently has deviated from its original objective of one tax one country in the wake of 5 slabs and mutiple registrations. All business owners are worried of the large over-head for compliance to GST procedures including filing of returns thrice in a month and generating E-Way bill for every sale exceeding 50,000. Further, more the concept of centralize registration presently prevalent in the service industry has been done away with under GST. Consequently, a service provider is essentially required to seek registration in all states where is service is provided leading to fear and apprehesion amongest service providers.

अध्यक्ष महोदय, चूंकि मनीष जी ने जब कल पीसी किया था, उसमें कहा कि इन्होंने 32 ट्रैडर्स ओर्गेनाइजेशनस के साथ सलाह मशवरा किया।

अध्यक्ष महोदय : कन्क्लूड करिये सोमनाथ जी।

श्री सोमनाथ भारती : हमारी सरकार ने जब भी कुछ नया करने का प्रयास किया है, उसमें आम आदमी का इनपुट इन्होंने जरूर लिया है, इसके लिये मैं इनको मुबारकबाद देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, साथ में क्योंकि इसके बाद पूरे देश के अंदर एक ऐसी व्यवस्था बनेगी जिसमें वन कन्टरी वन टैक्स का एक तरह से स्टार्टिंग प्वाइंट

होगा, लेकिन अभी तो इसके अंदर एक ऐसी व्यवस्था बनेगी जिसमें वन कन्टरी वन टैक्स का एक तरह से स्टार्टिंग प्वाइंट होगा, लेकिन अभी भी तो इसके अंदर बहुत कुछ करना है। अध्यक्ष महोदय, एक आम आदमी की तरह से जब टैक्सेस को देखा जाता है तो उसके बारे में क्या कहता है? आम आदमी कहता है अध्यक्ष महोदय, जो भी टैक्स चार्ज किया जा रहा है उसके मैपिंग, हर टैक्स का एक कन्सर्न है। जैसे कि स्वच्छता अभियान टैक्स लगा, सैस लगा, अब स्वच्छता अभियान सैस तो हमने दे दिया, हमारे ऊपर इसको कोई कण्ट्रोल नहीं है लेकिन जो मेरे घर के इर्द-गिर्द जो सफाई है, उसपे हमारा कोई होल्ड नहीं है, जब तक इस देश के अंदर टैक्सेज के साथ-साथ में उसकी एकाउंटिबिल्टी भी नहीं सुनिश्चित करेंगे, अध्यक्ष महोदय, तब तक इस देश का आम आदमी अपने आपको ठगा महसूस करेगा।

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हमारे फाईनेंस मिनिस्टर ने कहा कि दिल्ली सरकार इस बिल के साथ हम सब साथ हैं लेकिन साथ-साथ में उन्होंने अपने अप्रेहैन्सन्स ये जताई थी कि जो भी कमियां हैं, उसको हम सुनिश्चित करके उसे समय के अनुसार दूर करें।

अध्यक्ष महोदय : सोमनाथ जी, कन्कलूड करिये प्लीज। समय की भी सीमा है मेरे साथ। बहुत वक्ता हैं।

श्री सोमनाथ भारती : चूंकि मैं टैक्स के ऊपर बोल रहा था, अध्यक्ष महोदय ये कहना बड़ा जरूरी है, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये बात कही, मैं चाहूंगा मनीष जी अब अपने वक्तव्य में कहें तो इसको भी एड्रेस करें कि Citizen

should refuse to pay taxes, if the govt. fails to check graft. अगर सरकार करप्शन को कन्टेन नहीं कर रही है तो सिटिजन्स के पास civil disobedience का non-cooperation का राइट होनाा चाहिए, अध्यक्ष महोदय। मुझे लगता है कि टैक्सेज तो लें, जीएसटी तो बने लेकिन साथ-साथ में जब इसकी ऑन्सरेबिलिटी की जरूरत हो तो उस वक्त सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि जिस मद में टैक्स लिया गया है, उस मद के अनुसार उस दायित्व को सरकार निभाए, अध्यक्ष महोदय। इसका भी कहीं प्रोविजन होना चाहिए, अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय : कन्कलूड करिये सोमनाथजी।

श्री सोमनाथ भारती : मैं आखिर में, चूंकि जैसा मनीष जी ने कहा कि ये जो जीएसटी बिल है It is surely a way ahead, it is surely something which the entire country is looking forward to. But it is apt to become, it has long way to go to become traders friendly, consumers friendly and peoples friendly at large.

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि पहले भी कहा गया कि दो चीजें इसके अंदर हैं, एक तो हॉयर टैक्स रेट।

अध्यक्ष महोदय : सोमनाथ जी, ये बात आ गई है, रिपीट न करें, अब कन्कलूड करें।

श्री सोमनाथ भारती : दूसरा इसके अंदर कॉम्प्लैक्सिटी है। कॉम्प्लैक्सिटी

से तो जो व्यवस्था के लोग हैं, जैसे भी बग्गा साहब बैठे हुए हैं, लॉयर्स लॉबी को फायदा पहुंचे, कॉम्प्लैक्सिटी को सॉल्व कौन करेगा? कॉम्प्लैक्सिटी को सॉल्व करने के लिये लॉयर्स चाहिए होगा।

अध्यक्ष महोदय, लेकिन हॉयर टैक्स स्लैब से टैक्स एवेजन बढ़ेगा, चोरी बढ़ेगी और उससे करप्शन बढ़ेगा। मुझे लगता है कि जब अपनी सरकार रेटस तय करेगी, तो उस रेटस को तय करते वक्त इसका खास खयाल रखेंगे। मुझे इतनी बात कहनी थी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : मेरी माननीय सदस्यों से प्रार्थना है अपनी बात को रिपीट न करते हुए पांच मिनट से बात रखें क्योंकि वक्ताओं की लिस्ट बहुत लम्बी है।

सुश्री अलका लाम्बा : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी, आपने जीएसटी के मुद्दे पर मुझे बात रखने का मौका दिया।

अध्यक्ष जी, मैं जीएसटी के ऊपर जब पढ़ रही थी तो मुझे वो सब वीडियो याद आ रहे थे कि संसद के बाहर मीडिया खड़ा हुआ जब पहली बार देश के प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने जीएसटी शब्द का इस्तेमाल किया तो ऐसा लग रहा था कि जैसे पहली बार कोई शब्द सुना है। ये जो बहुत बड़े बदलाव की ओर अगर किसी ने ले जाने की कही है तो किसी और की सोच नहीं, वो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है और ये वही सांसद हैं जो कम से कम 17 सालों तक देश की लोकसभा में किसी न

किसी वजह से विपक्ष में होने के नाते जीएसटी को रोकते रहे। उन्हीं सांसदों से जो विपक्ष में थे, आज से पहले 14 से पहले उनसे जब कैमरा लगाकर पूछा गया कि जीएसटी की फुल फॉर्म मालूम है। उन भाजपा के खासतौर से उन सांसदों को मैं कहूंगी जिन्होंने सत्रह सालों तक जीएसटी को पास ही नहीं होने दिया, उस पर चर्चा नहीं होने दी। उसका विरोध करते रहे। उनको जीएसटी का फुल फॉर्म ही नहीं मालूम था। इससे होने या न होने से क्या फर्क आएगा, नहीं मालूम था। और सबसे बड़ा खुलासा देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने जब जीएसटी पर भाषण की शुरूआत की, तब हम लोग बहुत रूचि लेकर उसको देख रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी इस पर क्या कहेंगे और उनका पहला वाक्य ये था कि वे उन विपक्ष के मुख्य मंत्रियों में शामिल थे, गुजरात के जब मुख्य मंत्री थे जिन्होंने जीएसटी का पुरजोर विरोध किया, जिन्होंने इसको पास नहीं होने दिया। अगर आज तक किसी को दोषी माना जाए तो उन दोषियों में नरेन्द्र मोदी जी सबसे आगे खड़े हैं, उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत बार कोशिश की, प्रणव मुखर्जी जी से मिला और उनसे समझने की कोशिश की। जीएसटी उन्हें समझ नहीं आया। लेकिन उन्हें समझ कब आया, जब वो देश के प्रधानमंत्री बन गए और उन्हें देश को चलाने के लिए धन की जरूरत पड़ने लग गई। तो उन्हें समझ आ गया कि सत्रह साल पहले या सन् 2000 में देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी ने जो बात की थी, उसके बाद मनमोहन सिंह जी ने जो बात कही थी, वो बात उनकी प्रधानमंत्री बनने के बाद समझ आई। पर हमें खुशी है कि कम से कम कम उन्हें समझ आई और उन्हें ये भी समझ आ गया कि विपक्ष

की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है कि सत्रह साल पहले जो बहुत बड़ा बदलाव आ सकता था, उसे विपक्ष ने रोके रखा और जब वो प्रधान मंत्री बने, उन्होंने पूरे देश में विपक्ष की भूमिका को ही खत्म करना शुरू कर दिया और विपक्ष को जीरो कर दिया।

अध्यक्ष जी, ये जो जीएसटी है, हमें सिर्फ एक बात की तसल्ली है कि जो जीएसटी कांउसिल है, उसमें हमारे वित्त मंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी सदस्य हैं और हमें इस बात की भी खुशी है कि बहुत पुरजोर तरीक से वो व्यापारियों के हितों की बात हो, छात्रों के हितों की बात हो, महिलाओं के हितों की हो, उन सबको जीएसटी काउंसिल में पूरी ताकत के साथ रख रहे हैं। इस लिए इस जीएसटी से हमें उम्मीद लग रही है क्योंकि हमारे वित्त मंत्री पुरजोर तरीके से इस बात को रख रहे हैं।

अध्यक्ष जी, मैं महिला हूं। इसलिए महिलाओं की जो सबसे बड़ी चिन्ता है, एक महिलाओं का पूरा ग्रुप है, मेरी सहेली करके, डा. सुरभि भी एक बहुत बड़ा आन्दोलन चला रही है। मैं तारीफ करती हूं और उन्होंने सब महिलाओं ने मिलकर 'लाल लगाम' क्योंकि सेनेटरी नेपकिन्स के ऊपर भी 12 प्रतिशत लगाने की बात कही गई है। मुझे नहीं माूलम कि जो हमारी जीएसटी काउंसिल है, इसमें कोई महिला भी है या नहीं है। लेकिन मुझे इस बात की तसल्ली है कि इस मुद्दे को जीएसटी काउंसिल में अगर कोई महिला सदस्य नहीं, जिसने एक बार भी नहीं सोचा कि उस पांच दिन का खर्चा एक महिला के ऊपर सौ रूपये आता है। अगर वो गरीब है, उसकी एक बेटी है या दो बेटियां

है, उसको वो पांच दिनों का खर्चा जो है इस सैनेटरी नेपकिन्स पर जीएसटी लगाने के बाद उसके पांच दिन का खर्चा दो से तीन सौ रूपया हो जाएगा जो मुझे लगता है किसी के लिए भी सम्भव नहीं है। मुझे खुशी है कि मनीष सिसौदिया जी उप-मुख्य मंत्री/वित्त मंत्री और हमारे मंत्री जी से ये जरूर कहना चाहूंगी, आपने चूड़ियों पर, चूड़ी को, बिन्दी को, सिन्दूर को जीएएसटी से बाहर रखा है। मैं कहूंगी कि चूड़ियां आप रख लीजिए लेकिन सेनेटरी नेपकिन्स आपके किसी काम का नहीं है, उसे जीएएसटी से बाहर कर दीजिये। हम महिलाएं, आधी आबादी इसकी मांग उठाती हैं कि जो हमें चीज बाहर चाहिए, वो आप हमें दे दीजिए और चूड़ियां आप बिल्कुल जीएसटी में रख लीजिए, उसे ले आइए।

अध्यक्ष जी, छात्रों को लेकर कहूं तो हायर एजूकेशन जहां पर हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने दिल्ली के स्कूलों का जब रिजल्ट देखा तो आगे बच्चों को, अभी हमें पता लगा कि एक फॉर्म हमें दिया जा रहा है कि हर विधायक अपने स्कूलों में जाकर जिन बच्चों ने 100 प्रतिशत लिया है, उनको आगे की हायर एजूकेशन के लिए लोन तक दिल्ली सरकार देने की बात कर रही है और दस लाख रूपये तक का लोन। वही जीएसटी कहता है कि हायर एजूकेशन के लिए आपको जो है 18 प्रतिशत जीएसटी के अंदर जो है, वो हायर एजूकेशन के लिए और पे करना होगा। ये मुझे लगता है कि यह छात्रों के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ होगा, खासतौर से जो शिक्षा को आगे जारी रखना चाहते हैं।

अध्यक्ष जी, नेत्रहीन संगठन की मैं बात करना चाहूंगी। नेत्रहीन संगठन पूरा

का पूरा वित्त मंत्री से मिला और बाकी मंत्रियों से भी मिला। प्रधानमंत्री जी से भी मिलने की कोशिश की गई, उन्हें समय नहीं मिला, मैंने जो सुना है। नेत्रहीन जो हैं, उनके उपरण, जिसका वो इस्तेमाल पढ़ने लिखने में करते हैं, उन उपकरणों पर भी 18 प्रतिशत जीएसटी लगाने की बात है। तो मेरा इस सदन के माध्यम से हमारे जीएसटी काउंसिल के सदस्य, आदरणीय मनीष सिसौदिया जी से निवेदन करूंगी कि नेत्रहीन संगठन की जो मांग है कि नेत्रहीनों के लिए जो उपकरण इस्तेमाल होते हैं, उन्हें जीएसटी से बाहर किया जाए। जो हायर एजूकेशन के ऊपर 18 प्रतिशत लगाया जा है, उन्हें जीएसटी से बाहर किया जाए। महिलाएं जो आधी आबादी का सबसे बड़ा कन्सर्न है, मैं उसके लिए कहना चाहूंगी कि आप इस मुद्दे को जरूर जीएसटी काउंसिल में रखिए और सैनेटरी नेपकिन्स को पूरी तरीके से जीएसटी से बाहर ले आएं।

अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ इसके पीछे सबसे बड़ा कारण बता रही हूं। 88% girls used alternatives like cloth, plastic and newspapers यही कारण है कि वो afford नहीं कर पाते और जीएसटी लगने के बाद तो आप भूल ही जाएं कि हम उनको जो है इस तरफ प्रमोट करने की बात भी कर सकते हैं। मैं केरल की सरकार की तारीफ करती हूं अध्यक्ष जी। केरल की सरकार को जब ये पता लगा कि सेनेटरी नेपकिन्स के ऊपर जीएसटी लगाया जा रहा है, उन्होंने 'शी पैड' करके एक मुहिम चलाई है, केरल की सरकार ने। जिन्होंने पांच सालों तक सेनेटरी नेपकिन्स स्कूल की जो हमारी बेटियां हैं, जो हमारी छात्राएं हैं, उनके लिए अगले पांच सालों तक मुफ्त कर दिया है। चाहे उनका इसके ऊपर 30 करोड़ रूपया पांच साल का जो है, खर्चा आ रहा है। मैं

अपने वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि पहली कोशिश आपकी तरफ से यही हो। हमें उम्मीद है 3 जून को जब आप जाएं तो कहें कि पूरी तरह से सैनेटरी नेपकिन्स को जीएसटी से बाहर कर दिया जाए। अगर ऐसा करने में हम कहीं न कहीं नाकामयाब होते हैं तो मुझे लगता है कि जिस तरह से केरल सरकार ने किया, उसी तर्ज पर दिल्ली सरकार हमारी स्कूल्स में पढ़ने वाली बच्चियों को मदद करें।

अध्यक्ष जी, मैं लास्ट में सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूं जो व्यापारियों को लेकर है। बत्तीस के करीब जो हमारे संगठन हैं, मुख्य मंत्री जी को मिले और सबसे बड़ा व्यापारी वर्ग मेरे चांदनी चौक और कश्मीरी गेट से था। जिन्होंने कहा कि ट्रैक्टर और किस तरीके से कुछ टूल्स के ऊपर जीएसटी काफी लगने से चीजें महंगी हो रही हैं। व्यापारियों ने एक बात ही कही कि पहले उनकी कमर नोट बंदी ने तोड़ी थी, रही सही कसर जो है, वो जीएसटी पूरा कर रहा है। पहले पड़ी नोट बंदी की मार अबकी बार जीएसटी मार। तो मैं आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन करूंगी कि इस जीएसटी को हम एक बड़े बदलाव की तरह देख रहे हैं। हम एक साकारात्मक विपक्ष की तरह इस हाउस में चर्चा कर रहे है और हमें भी ये महसूस होता है कि जीएसटी समय की और देश की कर प्रणाली में एक बड़े बदलाव को लेकर एक बड़ी पहल है जिसका हम सब स्वागत करते हैं। पर जो चिंताएं है अध्यक्ष जी, मैं उम्मीद करती हूं कि उन चिन्ताओं को जो है, वो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में पूरी तरह से रखा जाएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका धन्यवाद कि आपके इस मुद्दे पर मुझे बोलने का अवसर दिया।

अध्यक्ष महोदय : बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। राजेश गुप्ता जी।

श्री राजेश गुप्ता : धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने इस विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया। समय सीमा का ध्यान रखते हुए मैं किसी भी चीज को रिपीट नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल देकर बात करना चाहता हूं क्योंकि मेरी जो विधानसभा है वजीरपुर, उसके अंदर स्टील की फैक्ट्रीज हैं जो कि एशिया में सबसे बड़े बाजार के रूप में मानी जाती है और इस बिल के अंदर वो ही काफी गलतियां की गई जो पहले भी होती रहीं। सबसे बड़ी अजीब बात ये है कि उदाहरण के साथ मैं बताना चाहूं तो जिस तरह पहले भी होती रहीं। सबसे बड़ी अजीब बात ये है कि उदाहरण के साथ में बताना चाहूं जिस तरह से कढ़ाई को बारह प्रतिशत में रखा गया। लेकिन जो इसके अंदर से पूरी निकालने के लिए कड़छी कहिए, उस पर ज्यादा लगा दिया गया। चम्मच हो, जितनी भी कटलरी है, उन सबकी, चम्मचों की कीमतें ये बढ़ाते रहते हैं तो इन्होंने चम्मचों की कीमतें बढ़ा दी और ये ही सबसे भी हुआ। लेकिन आदरणीय वित्त मंत्री जी ने मुझे नहीं लगता कि उसमें 15-20 मिनट भी लगाए जैसे ही बात उनकी समझ में आई कि ये दोनों एक ही चीजें हैं। ये सभी बर्तनों का ही एक रूप है और उन्होंने दोनों को बिलकुल सेम रेट में नीचे लोअर रेट में लाकर रख दिया। तो मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं अपने व्यापारी वर्ग की तरफ से कि बर्तनों को और जो कटलरी आइटम्स हैं, उनको सबको एक ही रेट में रखा जाए। इस पर हाईकोर्ट के आर्डर्स भी हैं कि इनको सभी को एक ही रेट में रखा जाए और जो स्वच्छ भारत अभियान है, उसमें भी

कटलरी आईटम एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करते हैं क्योंकि लोग हाथों से खाएंगे फिर उसके बाद में और कुछ बीमारियां बढ़ेंगीं। तो मेरा ये अनुरोध है कि माननीय वित्त मंत्री जी इस बात पर ध्यान दें और इसके अलावा भी जो भी ऐसे प्रोडक्टस हैं जिनके अंदर ये दिक्कतें आ रही हैं। जिनके अलग-अलग रेटस हैं, उनको एक समान रूप में लाया जाए, बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : बहुत-बहुत धन्यवाद राजेश जी। श्री महेन्द्र गोयल जी।

श्री महेन्द्र गोयल : धन्यवाद अध्यक्ष जी, जो आपने मुझे जीएसटी पर बोलने का मौका दिया और समय की ओर देखते हुए अपनी बातों को मैं कुछ शॉर्ट भी रखूंगा और दो लाइनें कहना चाहूंगा मनीष जी के लिए।

'राह संघर्ष की जो चलते हैं, वहीं दुनिया को बदलते है।

जीती हो जंग जिसने रातों से, वही सूर्य बनकर निकलते हैं।'

इसी हिसाब से अरविन्द जी ने और मनीष जी ने अपनी रातों की नींद खोई है और दुनिया के लिए जागे हैं। उसी पर आज जीएसटी पर चर्चा हो रही है और बधाई देना चाहूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में हमने जो तरक्की की और इस रिजल्ट के लिए एक बार फिर आपको मैं बधाई देता हूं और इस सदन ने तो वैसे भी बहुत से इतिहास रचें है, चाहे आप हॉस्पिटलों के मामले में ले लें, चाहे आप बस सर्विसेज के बारे में ले लें या पानी के बिल माफ करने के बारे में ले लें या बिजली के रेट घटाने के बारे में ले लें, इतिहास रचने का काम किया है और ये सदन इतिहास रचता रहेगा और मैं आपके

माध्यम से कहना चाहूंगा माननीय सदस्य सिरसा जी को कि जिस समय जीएसटी का बिल प्रस्तुत कर रहे थे और माननीय सदस्य बाहर...

अध्यक्ष महोदय : भई महेन्द्र जी, अब इस चीजों को छोड़ो आप, प्लीज चर्चा पे आएं, नहीं, नहीं, ये व्यक्तिगत दु:ख के कारण बन गए हैं।

श्री महेन्द्र गोयल : नहीं, उसी पे आ रहा हूं। उसी पे आ रहा हूं क्योंकि ये जो बिल इतना महत्वपूर्ण है एक केन्द्र सरकार का और दिल्ली सरकार उसको पास करने के लिए उतारू है, मैं इसलिए ये बात कहना चाहता हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वो छोड़ दीजिए सिरसा जी। अब मैंने रोक दिया न? सिरसा जी, मैंने खुद रोक दिया, प्लीज। महेन्द्र जी क्या कन्ट्रोवर्सी खड़ी कर लेते हैं!

...(व्यवधान)

श्री महेन्द्र गोयल : कोई बात नहीं सिरसा जी, आप आ गए हैं, उसके लिए आपका स्वागत है। जीएसटी पे काफी बातें अभी तक आती रही और मेरे से पूर्व साथियों ने भी काफी बातें कही हैं। लेकिन कुछ काम्पलिकेटिड आइटमें हैं, इसमें जैसे टमेटो है, ये वेजिटेबल है या फ्रूट है, एक तो इसके बारे में मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा। सैंडल और चप्पल, सैंडल और चप्पल, ये काम्पलिकेटिड जो आइटम्स हैं, इसमें आप लोगों ने क्या किया, क्या नहीं, क्योंकि मैंने एक बार देख था किटकैट ने, किटकैट, एक ये चौकलेट होती

होती है और इसमें बिस्कुट के हिसाब से मतलब ओट के अन्दर जाकर उसके ऊपर टैक्स लो आया था। विक्स और टॉफी का भी इसी हिसाब से रहा था। तो इस प्रकार से जो ये आइटम्स हैं, उसका भी आपसे मैं चाहूंगा कि क्लियर हो जाए और टैक्स स्लेब के अन्दर जो बहुत सी आइटमें हैं, 28 परसेंट के अन्दर रखें और आपने उसको रखा है। उसके लिए मैं मनीष जी का धन्यवाद भी करना चाहूंगा कि इस प्रकार से आपने रखा है औ वो बातें सभी की सभी मान ली जाएंगी जितने भी प्रस्ताव आपने रखे हैं और बहुत ज्यादा बातें न कहते हुए मैं यही कहना चाहूंगा कि इस जीएसटी बिल को जो ये सदन में आया है, ये पास हो लेकिन मुझे कही न कही डर भी है कि इससे दिल्ली को नुकसान होगा। क्योंकि दिल्ली का नागरिक हूं। दिल्ली को अभी तक हॉलसेल हब के रूप में जाना जाता था, हॉलसेल मार्किट होती थी। लेकिन जीएसटी बिल लाने से दिल्ली से व्यापार घट जाएगा बिलकुल। वो बराबर के स्टेटों में चले जाएंगे दिल्ली के अंदर व्यापार इतना ज्यादा नहीं होगा।

सर्विसिज का है, सर्विस टैक्स के रूप में जो भी आएगा उससे दिल्ली को गुजारा करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे पैट्रोल से हमारे पास टैक्स आता है। जब बाहर से व्यक्ति नहीं आएगी माल लेने के लिए, दिल्ली के अन्दर जब व्यक्ति नहीं आएगा तो उसके ऊपर पैट्रोल हमारा बिकेगा नहीं, तेल, डीजल हमारा बिकेगा नहीं तो उसके अन्दर और गेस्ट हाउस के अन्दर कोई ठहरने के लिए जाएगा नहीं। तो दिल्ली को ये सरासर लॉस है, देख लीजिए आप भी। दिल्ली का नागरिक हूं, दिल्ली के हित की बात करता हूं और दिल्ली के हित की बात करना मेरा फर्ज बनता है और ये फर्ज आपका भी बनता है। इसमें हंसने

की कोई बात नहीं है। क्योंकि मुझे यहां पर डर है इस बात के लिए क्योंकि होलसेल मार्किट होती थी दिल्ली और यहां से माल हर जगह बाहर जाता था और यहां से सब सेल होती थी तो उसके ऊपर दिल्ली को टैक्स मिलता था और दिल्ली के अन्दर जब व्यापारी ही नहीं आएगा तो टैक्स कहां से आएगा?

मैंने एक सवाल परसों भी किया था कि जब हमारी ऑरिएंटलशिप पे प्रोग्राम चल रहा था कि दिल्ली के अन्दर जो रजिस्टर्ड कम्पनी हैं, जैसे टीवी चैनल्स हैं, इसके ऊपर जो ब्रॉड्कास्टिंग होती है, तो उसका दिल्ली को कैसे टैक्स मिल पाएगा? उसके ऊपर भी आप एक बार जहां पर दिल्ली के अन्दर एग्रेशन है या देख लेंगे जो जैसा भी होगा आर एक एन्टरटेन्मेन्ट टैक्स के बारे में ये दिल्ली सरकार के पास जाएगा या एमसीडी के पास में जाएगा, इसके अन्दर कहीं न कहीं फर्क है। मैं इस बात को भी आपके माध्यम से क्लियर करना चाहूंगा क्योंकि दिल्ली के हित की बात है, हमारे सदन के हित की बात है। इस बात को मैं कहना चाहूंगा और इसके टैक्स स्लैब 0, 5, 12, 18 और 28 बनाए गए हैं जो बहुत सी आइटमें 28 परसेंट में लेकर गए हैं, उसमें से उनकी वकालत आप भी कर रहे हैं और आपके माध्यम से हम चाहेंगे कि उन आइटमों पे वो टैक्स घटकर 12 और 18 परसेंट के दायरे में आ जाए तो बहुत ज्यादा बातें न आज कहते हुए, धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

अध्यक्ष महोदय : संजीव झा जी।

श्री संजीव झा : बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जैसा अभी बहन अलका बता रही थी कि जीएसटी का जो

रोमांस था, वो कोई पहली बार अभी नहीं आया। यह 2000 में शुरू हो गया था। जब वैट भी ठीक तरह से इम्पलीमेंट नहीं हुआ था और रोमांस का अपना एक कारण था। क्योंकि सभी ये मानते थे कि जब जीएसटी आएगा तो टैक्स में रियायत होगी, स्पेंडिंग बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, निवेश बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, ये केसेडिंग इफेक्ट्स से निजात मिलेगी। टैक्स कम होगा कॉम्पलाएंस ज्यादा होगी तो रेवेन्यू बढ़ेगा। व्यापार करना बेहद आसान होगा। व्यापारियों को के हित में होगा। तो इसीलिए लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, 17 साल लग गए इसमे और एक मेरी एप्रिहेन्सन भी है कि आज ये जो माना जा रहा है कि जीएसटी आने के बाद कोई अलाउद्दीन का चिराग हाथ लग गया, ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि जब अटल जी के समय ये बाद में मनमोहन जी या चिदम्बरम साहब कहते थे कि अगर ये इम्पलीमेंट हो जाता तो जीडीपी दो फीसदी बढ़ जाएगा। लेकिन आज हालांकि मैं एक चीज की बधाई देता हूं जीएसटी काउंसिल के सभी मेम्बरों को और सभी राज्य सरकारों को कि जिस तरह से दरें तय की गई हैं और पारदर्शिता बढ़ती गई है, लेकिन शॉर्ट टर्म में नुकसान होने वाला है जो हम कम्पंशेसन देने वाले हैं स्टेट को। पांच सालों तक तो ये इमीडियेट कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन एक चीज ये भी सच है कि ये तरह-तरह के जो टैक्सेज थे, इनसे जो परेशानियां हो रही थी, उससे लोगों को निजात मिलेगी। अब एक ही तरह का टैक्स हर जगह एक ही दर हर जगह रहेगा तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अभी बहुत बारीक बात अभी हमारे गोयल साहब कह रहे थे कि एक छोटे-छोटे प्रॉडक्ट हैं जैसे लग्जरी की बात कर रहे थे कि भाई लाइफ अच्छा बेहतर होना चाहिए। लेकिन लग्जरी

आइटम पे टैक्स स्लेब 28 परसेंट के स्लेब में रखा गया है। मेरे ख्याल से कल ही बात कर रहे थे, कोई हमारी वर्कशॉप चल रही थी तो अभी अगर सारे टैक्स को ऐड कर देते हैं, अगर होटल के व्यवसाय में बाकी लग्जरी की जो आइटम्स हैं, उसमें तो टोटल मिला के 20 परसेंट तो और महंगा हो गया वो। आज ही मैंने देखा पेपर में कि कुछ व्यापारी विरोध कर रहे थे कि मोटर पार्ट्स स्लेब 28 परसेंट में रखा गया है जो पहले 15-17 परसेंट के स्लेब में था। तो मेरा ये कहना है कि अमूमन ये देखता हूं कि जिस जिस देश मे ये जीएसटी इम्पलीमेंट हुआ है, 15से 8 परसेंट से ज्यादा किसी भी देश में टैक्स का स्लेब नहीं है। तो इसीलिए अगर ये इम्पलीमेंट होने पर लोग अगर ये मानते थे कि ये व्यवसाय या कोई भी लोग कि हमें रियायत मिलेगी, उससे नुक्सान न हो, ये जिम्मेदारी जीएसटी काउंसिल के सभी मेम्बरों की और मैं अपने वित्तमंत्री के जरिए मैं चाहूंगा कि ये बात वहां तक पहुंचे।

दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है और जिस पर मुझे चिन्ता है कि जीएसटी काउन्सिल की नेटवर्किंग को देख रहा है। जीएसटीएन में मैं एक आर्टिल कहीं पढ़ रहा था। इसमें प्राइवेट जो एनटिटी है, उनका इन्वेस्ट 51 परसेन्ट है। गवर्नमेंट का स्टेक 49 परसेन्ट है और अभी तक चार हजार करोड़ रूपये लग चुके हैं और मैं बताऊं आपको कि इसमें इन्वेस्ट करने वाली एक कम्पनी है जिस पर पहले से ही सर्विस टैक्स की चोरी का मामला बनता है और सीएजी ने कहा था कि हम इसकी जांच करना चाहते हैं। उसको जांच नहीं करने दिया गया। जीएसटीएन की जांच सीएजी नहीं कर सकती है। ऐसा केन्द्र सरकार के जरिये प्रावधान किया गया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रसन्ना जी, दिखवाइए। शायद बन्दर है। प्रसन्ना जी, एक बार भेजिए। जरा भेजिये। झा जी, चलिए।

श्री संजीव झा : जी अध्यक्ष महोदय, देखिये एक बहुत गम्भीर मसला है। जो जीएसटीएन का ऑडिट करने से सीएजी को रोका जा रहा है। हालांकि इसमें इन लोगों की महारत है। आपको पता होगा कि अभी कुछ दिन पहले जब वीडीएस से कितने पैसे आये। इसकी ऑडिट की बात भी सीएजी ने कहा था, उनको मना कर दिया गया। तो मेरा ये कहना है कि सीजी एक ऐसी एजेन्सी है जिसके बारे में अम्बेडकर साहब जब संविधान निर्माण...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : भई उधर थोड़ी देर ध्यान छोड़ दीजिये। वो गये हैं। सुरक्षा गार्ड चले गये हैं।

श्री संजीव झा : डा. अम्बेडकर ने कहा था कि सीएजी सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा महत्वपूर्ण संस्था है और इसे केन्द्र और राज्यों के राजस्व को प्रमाणित करने का संवैधनिक अधिकार है। तो मेरा ये कहना है कि उसके संवैधानिक अधिकार से रोका ज रहा है।

दूसरा जो गम्भीर मसला है, जो मैं अपने वित्त मंत्री के जरिये मैं चाहूंगा कि ये काउंसिल में चर्चा हो जिसके बारे में हालांकि अप्रिहेन्सन आपने भी जताया था और बाकी मैम्बरों ने कहा है और ये मैं चाहता हूं कि ये सेन्स ऑफ हाऊस बनकर के वहां जाये कि रीयल एस्टेट और एल्कोहल को किस

लॉजिक से उससे बाहर रखा गया है। हालांकि आपने भी कहा था और हम सब लोग मानते हैं कि ये रीयल एस्टेट और एल्कोहल को बाहर रखने मे कोई कान्सिपेरेन्सी तो नहीं है। चूंकि सबसे बड़ा करप्शन कहीं है, तो वाइन में है। दिल्ली में वैट कुछ और है और हरियाणा में कुछ और है, यूपी में कुछ और है पंजाब में कुछ और है। तो इसका मतलब है कि क्या कोई लॉबी इस पर हाबी तो नहीं हो गयी है? तो मेरा ये कहना है कि हमारे वित्त मंत्री चर्चा करेंगे ही करेंगे और आज इस हाउस का सेन्स भी जाये वहां कि ये पूरा हाउस ये चाहता है कि किसी भी तरीके से, चूंकि आप देखिये कारोबार में कई सारे बड़े पावरफुल लोग, नेता, मंत्री एन्वॉल्व हैं और हर स्टेट के लोग हैं तो किसी तरह से अगर या तो अलग रखने का कारण क्या या कोई समय सीमा है और अगर समय सीमा नहीं है तो लॉजिक क्या था। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन प्रिंसिपल हम बिल्कुल सहमत हैं कि ये एक बहुत बड़ा स्टेप है लेकिन उसमें जो कुछ अप्रिहेन्संस हैं, उसको दूर कर लिया जाये ताकि छोटे व्यापारियों को कई सारे इसमें पहले ये था कि दो बार रिटर्न भरना पड़ेगा। अब 35-36 रिर्टन भरना पड़ेगा। तो छोटा व्यापारी है उसके लिए अब वो मैच करने के लिए कम्प्यूटर रखना पड़ेगा, साथ में एक इम्प्लाई रखना पड़ेगा। रोज वो अपना ऑन लाइन मैच करता रहे तो वो भी ठीक से अपना व्यापार चला पाये। उसकी कोई व्यवस्था की जाये ओर ऐसा किया गया तो मैं मानता हूं कि ये क्रान्तिकारी कदम होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री अनिल बाजपेयी जी। एक ही नाम आया मेरे पास।

श्री अनिल कुमार बाजपेयी : सर मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माधयम से डिप्टी सीएम साहब का गांधी नगर की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आज जब मैं आ रहा था सुबह मार्निंग में, कुछ हमारी एसोसियेशन के पदाधिकारी हमसे मिले थे। सबसे पहले उन्होंने ये भी कहा कि मैं आपकी सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं इसलिए भी कि पिछली बार जब हमारी सरकार ने बजट में कपड़ा व्यापारियों के लिए टैक्स आया था, तो दिल्ली की ये एक पहली सरकार थी जिसके अन्दर माननीय मुख्यमंत्री साहब ने और मनीष जी, आपने प्रस्ताव लाकर तुरन्त पांच परसेंट के टैक्स को वापस लिया, आज गांधी नगर में एक बहुत बड़ा उद्योग है, चाहे वो कम्प्यूटर एम्ब्राएडरी का हो, चाहे वो रेडीमेड गारमेन्टस का हो और चाहे उससे जुड़े हुए बटन बनाने की फैक्ट्री हो, वो सारे लोग कहीं न कहीं चिंतित हैं। सर, कहीं न कहीं आज ये, क्योंकि वो चाहते हैं कि कहीं ऐसा न हो जाये कि अगर हम पर टैक्स लग जाये तो एक लाख से अधिक कर्मचारी वहां पर काम करते हैं। बहुत से रेडीमेड गारमेन्टस की, बटन बनाने की फैक्ट्री बहुत से कम्प्यूटर इन्बैल्डरी की फैक्ट्री जो लोग अपना रोजगार चला रहे हैं, उन्होंने आज मुझसे सिर्फ ये कह था कि माननीय मुख्यमंत्री साहब से और अपने फाईनेन्स मिनिस्टर साहब से हमारी भावनाओं को आप पहुंचा दीजिएगा। मैं तो सिर्फ आपसे ये प्रार्थना कर रहा हूं। अपनी गांधी नगर के पूरे क्षेत्र के व्यापारियों की ओर से, एसोसिएशन की ओर से कि जब भी इस पर कोई बात हो उनके हितों की रक्षा जरूर की जाये। मैं इस ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद बाजपेयी जी। श्री एस. के. बग्गा जी।

श्री एस. के. बग्गा : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जीएसटी की चर्चा में भाग लेने के लिए मौका दिया और इसके लिए धन्यवाद करता हूं अपने वित्त मंत्री जी को जो इतने टाईम से बिल को तैयार करने में लगे हैं ओर लोगों की समस्याएं भी सुन रहे हैं। जीएसटी का हम स्वागत करते हैं इण्डिया में What is the Goods and Service Tax, GST? It is a destination based tax on the consumption of the goods and serivces, it is proposed to be levied in all states right from manufacturing upto final consumption with credit of the tax paid at previous stage available at the set of in an nut-shell only value addition will be taxed and the burden of the tax is to be brone by the final consurmer, GST would replace the following taxes; tax currently levied and collected by the centre, centeral excise duty,duty of excise, additional duty of Excise, goods of special importance, additional duty of the excise and textile and texitle product and additional duty of the custom, special additional duty of the custom, cess, service tax, central surcharge under cess so far as they relate to supply of goods and services, State tax that, luxury tax, entry tax, entertainment tax and tax on the advertisment, purhase tax, tax of the lotteries, betting and the gambling, state surcharge in cess so far as related to the supply of the goods and services. Problem in the existing system, different tax rates

in the dfferent states, tax cess and the credit station, no off-set of the CST against vat, no service tax creditied in the case of the trading and entity, excise on the capital goods not available to the trading entity of the services providers, list where input credits available on the capital goods, branches being maintained uncessarily for reducing the input impact of the tax of the CST is not connotable. Credit available on the capital goods will applicable if the proprietor is late over a number of years. Above resulting unnecessary proce increase, from requirment C, F, E-1 etc. form different compliance based on the different tax laws for example 25 states have different law compliance procedure form filing. Some filing are even manual are not system provide. Different types of the invoices format under each law, multiple tax vat, excise, octroi, service tax requiring multiple compliance. Abatement on the goods and the service protion unnessarily increaed the transitional value like in case of the works contract. But vat and the service tax on the same transaction like software, trademark, returns, copyright, works contract, food supply in the AC Rosauants. Buyers also impact at high cost multiple authorities to deal with by a taxpayee each authority undertaken all the assessment and audit. Next then, station PAN based station required to be obtained for the each state from where taxable supplies are being made. A person having a multipoe business will take up in the stay may obtain the separate station for the each business. Libility to be registered, every person

who is registered or who hold the licence under an earlier law. Every person whose turnover in a year exceeds the limit a person doesnot liable to registered may take voluntary registration. Vendor registered on E-commerce, market place to be also registered as e-commerce company will be collecting TCS on behalf of the vendor. The tax rates, four tax rate namely 5%, 12%, 18% and 28%. In the end, I request to finance minister to keep in mind when the meeting will be held regarding retrun file, date of filing of return, date of filing of return, 10th, 15th and 20th every month. The small dealer can not file the return monthly, please make the date of 28th and quartely return to be prescribed every quarterly commission is here.

अध्यक्ष महोदय : बग्गा जी, कन्क्लूड करिए।

श्री एस. के. बग्गा : The tax rate four tax rate namely 5%, 12%, 18% and the 28% and in the end I request to Finance Minister to keep in the mind when the meeting will be held regarding return file, date of filing of return. Date of filing of return 10th 15th and 20th every month. The small dealer cannot file return monthly please make date of 20th and quarterly retrun to be prescribed every quarterly commission is here. हर बार रिटर्न का टाइम बढ़ाना पड़ता था, क्वार्टर के बाद भी। मंथली रिटर्न में 17 तारीख को टैक्स जमा करायेंगे, 20 को रिटर्न जायेगी तो यह कम्पलाएन्स छोटे डीलर्स के लिए बहुत मुश्किल है सर।

दूसरा, इसमें एडवांस पेमेंट के ऊपर आप जीएसटी ले रहे हैं। उस टैक्स का क्या होगा जो माल खरीदा ही नहीं मैंने। कल को वो एडवांस पेमेंट नहीं मिलती मेरे को या कोई डिसप्यूट हो जाता है। सर, इसको भी ध्यान में रखें।

दूसरा, अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज का है। अनरजिस्टर्ड डीलर से मैं परचेज करूंगा तो उसका रिवर्सल मैं जमा करा कर बाद में उसको वापस लूंगा, जिससे छोटे व्यापारियों को बहुत दिक्कत आने वाली है। इसलिए इसका भी ध्यान रखा जाये। रीयल एस्टेट को भी जीएसटी में लाया जाये। 28 परसेंट टैक्स से महंगाई बढ़ेगी और लोगों का बिजनेस भी नहीं चलेगा। लोग नंबर दो में माल बेचने की कोशिश करेंगे अगर 28 परसेंट टैक्स होगा तो। आपसे प्रार्थना है कि इस टैक्स रेट को रिवाइज करें और जो यह रिटर्न की प्रॉब्लम है, इसको दूर करें, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं सदन का समय कृपया एक घंटा बढ़ाया जाये। श्री नितिन त्यागी जी।

(सदन की सहमति मिलने पर समय एक घंटे के लिए बढ़ाया गया)

श्री नितिन त्यागी : Thank you speaker sir, for giving me an opportunity to talk on GST today and I will start see....most of the people have talked about the micro things in GST. But I would like to speak on the micro aspect and I would talk about the apprehensions that I have been discussing with the lot of people in my constitutency and otherwise also and first of all there is a huge confusion and

ambiguity. why? What is the intention behind the implementation of GST? Because not only me but there is so many people I have talked to and I come from Laxmi Nagar I, represent Laxmi Nagar and it is a hub of CAs if you know so there are lot of people who know a lot about GST and every article says that it will help in curbing tax evasion, so what is the actual intention behind bringing in GST? Is it that we are taking all the traders all the manufacturers all the service proivding people as dis-honest except for those who are dealing with real estate and liquor and because we consider them as dis-honest ane we think that they are trying to evade tax every single day which we thought before 8th of Nov. also that we are going to profit in lakhs of crores if we bring in demonetization, but we were sadly wrong. It was a huge mis-adventrue, but when we talk about GST today. It is our intention and do we take our traders our manufacturers for the back bone of the economy as dishonest? One, if do not take that into consideration, we then present GST as we going to simplify the taxation system sorry....I would say sorry to you, but these are the apprehensions that I am talking about. When we talk about simplifying the taxing, we also talk about reducing and removing the multiplicity of the taxes. Then what is this R N R that we....RNR let me tell you who hae not talk about it is Revenue Natural Rate. Because of the removal of multiplicity of taxes. जो कि बहुत सारे स्टेट्स और सेंटर अलग-अलग किस्म के टैक्सेस लगाते हैं और वो टेक्सेस की मल्टिप्लिसिटी खत्म

होने की वजह से बहुत सारा टैक्स कलैक्शन में लॉस होता, तो उसक लिए एक आरएनआर लगाया जायेगा। उसके ऊपर आज तक एम्बिग्युटी है, उसके ऊपर रेट आज तक फिक्स नहीं हुआ है। वो रेट क्यों नहीं फिक्स हुआ है कि हम इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाने के बाद आज तक यह नहीं बता पाये हैं कि वो आरएनआर पर हम कहां स्टेंड करेंगे। 15 to 15.0 percent probably. Sir, India is a developing country. India is not developed country where the central govt. is responsible to develop the infrastructure for law and order. They are spending hugely in developing this country and every year, year after year we have a deficit budget. We cannot afford to have soical security systems like in the western countries where the budget is in surplus. They can provide social security services. These options are not available with us when they are not available with us, we will not be able to help those people those low end purchasers and buyers who going to be affected by this GST. We have to take into consideration.

बड़े आराम से हम लोग कह तो देते हैं कि जीएसटी आयेगा और 14 परसेंट तक का जो है, हम लोग अगले पांच साल तक, उनका जो भी लोस होगा स्टेट्स का, हम लोग उसको करेंगे। अरे, स्टेट्स का तो करोगे पर इन्डिवुज्युअल्स का कौन करेगा?

And our country is not at all in a position to help those people.

Everybody says that 10% wealth is with the 90% percent of the people. Most of them are poor. How is it going to help them. There has to be absolute increase in prices with 15 RNR sir. Nobody can help that. I think we should have a more eleborate presentation on RNR we do not know about it. The whole chane that stands today is going to stay the same. There is the Manufacturer who will send it to wholeseller, whole seller will send to the retailer. The retailer will sell it to consumer once the consumer purchases the good, he is going to pay the tax. No matter how much he tries to sell it that ultimately the manufacturer is going to be taxed. खरबूजा छुरी पर गिरेगा, छुरी खरबूजे पर गिरेगी, कटेगा खरबूजा ही। कैसे ही पकड़ लो सर, टैक्स तो अल्टीमेटली कंज्यूमर की जेब से ही जाना है। जब हम सर्विस टैक्स की बात करते हैं तो सर्विस टैक्स जो आज तक today whatever service tax is levied on the service provider or by the service consumer, ultimately the service consumer pays it. Similarly in all taxes the consumer pays it. Here also the consumer pays it but the problem is the goods the consumer pays it. Here also the consumer pays it but the problem is the goods on manufactured in some other states and they are consumed in some other state and like, बात तो एक जी गांधी नगर से है। पूरा का पूरा ट्रेडर हब है और पूरे इंडिया में गारमेंट्स जो है, बाजपेयी जी शायद गांधी नगर से ही जाते होंगे और स्पेयर पार्टस चांदनी चौक से जाते होंगे अब गवर्नमेंट का क्या इन्सेंटिव है कि उन मार्किट्स को बढ़ाये क्योंकि वहां से गवर्नमेंट टैक्स

नही कमाएगी। जहां पर मेन्युफेक्टचरिंग हब्स है अगर वहां पर बनता है और बनने के बाद में, आपने सर, ये उठाया था पाइंट, वो दूसरी जगह पर जाता है तो दूसरे स्टेट में जहां कंज्यूम होता है, वहां पर वो टैक्स कमाएगा तो इस स्टेट के पास क्या इंसेंटिव है कि वो मेन्युफेक्चरिंग युनिट्स के एरिया को डेवलप करे, वहां के इन्फ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करे, उसे वर्ल्ड क्लास बनाने की कोशिश करे, कंपीट करे इंटरनेशनल मार्किट के साथ में there is absolutely no insentive. क्या परसेंटेज होती है कॉस्ट की जो इम्प्लायमेंट की बात को रखेंगे? बड़े आराम से एक्सप्लेनेशन ये मिल जाएगी कि इम्प्लायमेंट बढ़ाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिटस लाई जाएंगी। नहीं सर, इम्प्लायमेंट बढ़ाने के लिए नहीं लाई जाती है, पैसा भी कमाने के लिए लाई जाती हैं। इम्प्लायमेंट बढ़ाने के लिए तो मार्किट खोल दिये जांएगे, उससे भी बढ़ जाएगी। Apart from this, there is huge ambiguty in the revenue loss. जब मल्टिप्लिसिटी ऑफ टैक्सेज हटेगा, जब नम्बर ऑफ टैक्सेज रेड्यूस हो जाएंगे जो स्टेट्स जैसे बिहार में लिक्कर प्रोहिविशन है और लिक्कर से एक बहुत मेजर चंक ऑफ टैक्सेज का आता था, वो हट जाएगा। वो कहीं न कहीं कम्पनसेट करते थे किसी और प्रोडक्ट पर लगाके ये इन्डिपेन्डेंट स्टेट के पास से चली जाएगी तो उसके बाद क्या अगर कोई लिक्कर बैन करना चाहता है स्टेट, वहां की जनता करना चाहती है, महिलाएं करना चाहती हैं तो क्या हमें इम्पोज करना पड़ेगा? नहीं जी, लिक्कर करो क्योंकि आपका लॉस पूरा नहीं हो पाएगा और रेवेन्यू लॉस ओवरऑल होग। उसको कम्पीट करने के लिए आप आरएनआर लगाओगे। आप प्रोडक्ट्स के ऊपर आरएनआर लगाओगे, कितना लगा दोगे, उससे प्रोडक्ट्स की प्राईसिंग पर

क्या फर्क पड़ेग, इसके बारे में everything is silent. जो रेवेन्यू लॉस होगा तो उसको एस्सेप्ट करना पड़ेगा। We are already in deficit, the country is run in deficit. How are we going to fund the development schemes? Are you going to load the public which is probably not responsible for bringing in this GST?

Sir, I am more worried about the individuals also, yes the states are going to accommodate even the individuals are going to accommodate. In the public accommodated and cooperated with a huge misadventure of the Cental Government on 8th o f November also and prior to that even before a lot of Central Government's schemes, people have aloways appreciated and stood with them, but the government should also stand with them. GST, probably is a fantastic concept, but if the intention is right. If the intention is not right then going where this money is to to go?

अध्यक्ष महोदय : कन्क्ल्यूड करिये अब नितिन जी, प्लीज कन्क्ल्यूडक करिए।

श्री नितिन त्यागी : सर, थोड़ा सा, थोड़ा सा।

अध्यक्ष महोदय : नहीं अब कन्क्ल्यूड करिए बहुत हो गया, काफी अच्छे पाइंट रेज कर लिए आपने।

श्री नितिन त्यागी : एक सर इसमें एण्टी प्रोफिटीयरिंग प्रोविजन का पाइंट है। सर, एण्टी प्रोपिटीयरिंग प्रोविजन जो है, वो इसलिए है कि जब भी टैक्स कम है किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर तो वो टैक्स का बैनिफिट जो है, वो पब्लिक के पास जाना चाहिए मतलब वो कॉस्ट कम होने का पब्लिक के पास जाना

चाहिए। ये एण्टी प्रोफिटीयरिंग प्रोविजन है। आज तक केंद्र सरकार ने, जितना पेट्रोलयम का दाम कम हुआ हो क्या इस कान्सेप्ट को माना है या हर बार टैक्स बढ़ा के पब्लिक के सामने वही दाम रखा और कौन रोक सकता है किसी को भी ये उसके प्रोडक्ट्स का प्राइसिंग सेट करने से? आप टैक्सेस तो कर सकते हो पर प्राईसिंग तो वो अपने हिसाब से ले सकता है, कार्टल बनाके सारे के सारे एक साथ ले सकते हैं। सारे के सारे अपने आप प्राईसिंग बनाके पब्लिक को लूट सकते हैं तो ये एण्टी प्रोफिटियरिंग प्रोविजन जो है, ये बहुत ज्यादा क्लेरिटी नहीं है इसके अंदर एक और चीज, सर लास्ट कि It should be implemented. We welcome it in Delhi. Delhi is a serivice industry driven economy. It would benefit us, get us more revenue. I was talking about the whole nation when I was putting it all this apprehension there are so many people from across the nation who come and live in Delhi but we should not exclude real estate and liquor from this. It raises a huge cloud of doubt over the whole intention of the GST when we exclude these two things and there is the huge need ot technological support and the govt. should ensure every single state govt. and all the centre, they should ensure that this techno ogical support doel not burden the people who are going to support us in this adventure which we are calling GST right now test for their love of the country. Thank you.

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद, नितिन जी बहुत सुंदर। शिवचरण गोयल जी।

श्री शिवचरण गोयल : धन्यवाद अध्यक्ष जी, मेरी विधानसभा में 5 परसेंट टैक्स लास्ट इयर ही मार्बल पर, लक्कड़ पर, प्लाईवुड पर किया गया था। अब

उसको 28 परसेंट कर दिया गया हैं इस विषय में न जाकर, मैं एक जो सबसे बड़ी गंभीर समस्या आने वाली है, मैं उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारी दिल्ली मैं अधिकांशत: मिडिल क्लास ज्यादा है। छोटे-छोटे व्यापारी हैं, या माध्यम व्यापारी हैं। इस टैक्स के लगने के बाद या तो हायर क्लास रहेगी या लोअर क्लास रहेगी, मिडिलमैन खत्म हो जाएगा।

मैं उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं आपको। ये तीन पार्टियां पकड़ लें आप हाशिम भाई, राजेश जी और मनोज जी ये बॉम्बे से डील करते हैं हाशिम जी। हाशिम जी से माल लिया, बॉम्बे से सौ रूपये का। इसके ऊपर 28 परसेंट टैक्सल लग गया। ये सौ रूपये का दिल्ली आकर इनको 128 रूपये का पड़ गया, ये फस्ट पार्टी हो गई। इन्होंने माल बेचा और ये सौ रूपये के माल के ऊपर 5 रूपये प्राफिट लिया और आगे बेच दिया। इनको 133 रूपये का पड़ा। अब इनसे माल कौन लेगा? इनको तो 28 परसेंट जो टैक्स था, वो रिफंड हो गया। इनको 28 परसेंट टैक्सरिफंड हो गया। लेकिन इनको टैक्स रिफंड नहीं होगा क्योंकि ये छोटे व्यापारी हैं। इनके पास जीएसटी नंबर नहीं है, 20 लाख से नीचे। 133 रूपये और यहां सौ रूपये तो 33 रूपये कहां से आएंगे? अब 33 रूपये के लिए कोई जाएगा इनके पास? बीच का मिडिल मैन लोअर मैन डे बाई डे खत्म हो जाएगा या तो हॉयर क्लास या लोअर क्लास। मिडिल मैन रहेगा नहीं। ये एक साजिश है देश को लूटने की, खत्म करने की साजिश है ये। जैसे फॉरेन में है, या तो हायर क्लास या लोअर कलास, ये देश के अंदर एक किस्म की, एक सोची समझी, एक लूटने की या तो कर चोरी बढ़ेगी और या फिर गरीब आदमी और गरीब और अमीर आदमी और अमीर, ये आपके सामने है और जो मैंने एग्जाम्पल दिये हैं, इसके अंदर कोई फर्क

हो तो मुझे बताएं आप। सौ रूपये का सामान लेगा बंबई से 128 रूपये का उनको पड़ेगा 28 रूपये इनको रिफंड हैं, इनको 133 रूपये में रिफंड नहीं है तो 33 रूपये का डिफरेंस कहां से वहन करेगा, ये आप थोड़ा सोचें और ये देश को जो लूटने की साजिश चल ही है। ये बड़े-बड़े कारपोट के लिए जो ये काम किया जा रहा है, सबसे बड़ी ये जो साजिश है, अभी तक इसके बारे में किसी ने सोचा नहीं है। क्योंकि मैं बिजनेसमैन हूं, मैं जानता हूं इस विषय में। तभी मैंने आपको कहा है कि ये जो साजिश है अभी तो देश को खत्म करने की है। यदि इसके ऊपर गंभीरता से सोचा नहीं गया तो बहुत भयंकर परिणाम होंगे। अभी पहले साल फिर दूसरे साल फिर तीसरे साल एक समय के बाद इकानॉमी इंडिया की खत्म होने वाली है। अभी इसके ऊपर यदि गहन अध्ययन नहीं किया गया और इसको लागू कर दिया गया तो इसके दुष्परिणाम इतने होंगे, इसके बारे में ज्यादा मैं बता सकता नहीं लेकिन जो मैंने एग्जाम्पल दिया है, इसमं कहीं फर्क हो तो आप मुझे बताएं, बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया।

अध्यक्ष महोदय : राखी बिड़ला जी।

सुश्री राखी बिड़ला : धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे इतने अत्यंत गंभीर मुद्दे पर बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

मुझसे पूर्व तमाम वक्ताओं ने जीएसटी में किस प्रकार से होने वाले फायदे नुकसान टैक्स की बढ़ोत्तरी, इन सब पर प्रकाश डाला। अध्यक्ष जी, उस जीएसटी पर कुछ बोलने से पहले मैं एक बार इस बात पर भी चर्चा करना चाहूंगी कि जो हमारी ये कन्द्र की सरकार है, आज इसे बने हुए पूरे तीन साल हो

गये और तीन साल में इस सरकार को अगर मैं अपने शब्दों में समझ पाई हूं और मेरे जैसे बहुत से लोग अगर समझ पाये हैं तो इस सरकार को अगर कापी पेस्ट, जीरोक्स या नकलची का नाम दिया जाए तो मुझे लगता है केई उसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसका कारण ये है कि मैं इस सरकार को कापी पेस्ट या नकलची सरकार क्यों बोल रही हूं क्योंक आज तीन साल हो गये। तीन साल के अंदर केंद्र की सरकार आज तक कोई ऐसी कोई भी नीति लागू नहीं कर पाई देश के अंदर जो इनकी खुद की ईजाद की हो, जो इन्होंने खुद से बनाई हो। तीन साल के अंदर 2014 से लेकर आज तक केंद्र सरकार ने जो भी नीतियां पास कीं हैं, वो जो पुरानी सरकारों से चलती आ रही हैं, जो लगातार आज तक पेश हुए बिल या और जो नीतियों पर काम चल रहा था, केंद्र सरकार के माध्यम से उन्हीं को लागू करा है सिर्फ एक को छोड़कर और वो क्या थी जो 8 नवंबर को इन्होंने नोटबंदी की घोषणा करी और देश का सत्यानाश कर दिया। देश का व्यापारी अभी उस से उभर भी नहीं पाया था कि अब ये ले आये जीएसीटी। वही जीएसटी कि जब ये विपक्ष में थे, उसी जीएसटी पर छाती पीट पीट कर इन्होंने खूब विरोध करा। राज्यसभा में भी किया, लोकसभा में भी किया। राज्य सरकारों ने भी किया और मुख्यमंत्रियों ने भी किया। जब खूब ड्रामा करा जब कांग्रेस लाना चाह रही थी जीएसटी, तब जीएसटी में लाखों कमियां थी। तब जीएसटी महंगाई बढ़ा रहा था। तब जीएसटी व्यापारी विरोधी था तब जीएसटी उपभोक्ता विरोधी था लेकिन अचानक से जैसे ही ये सरकार में आये, तो जीएसटी बहुत अच्छा हो गया, जीएसटी व्यापारियों के हित में हो गया, जीएसटी महंगाई कम कर देगा, जीएसीटी टैक्स की चोरी को रोक लेगा, जीएसटी भ्रष्टाचार को रोक लेगा, ऐसा क्यों? क्योंकि

केंद्र सरकार में बैठे हुए ये बीजेपी के नुमाइंदों को जाति धर्म की गंदी राजनीति से फुरसत मिलती नहीं। दलित और दूसरे लोगों को हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कराने से इन्हें फुरसत मिलती नहीं। फिर जब ये जाते हैं सदन में, तो कुछ पेश करने के लिये तो होना चाहिए तो फिर ये वही घिसी पिटी जो कांग्रेस की नीतियां थी, जो कांग्रेस के प्रपोजल थे, जिसके विरोध में प्रदर्शन कर विरोध आवाज उठाकर हंगामा करकर, जिसको ढाल बनाकर ये चुनकर आये, न सिर्फ चुनकर आये प्रचंड बहुमत लेकर आये, उस प्रचंड बहुमत के बाद भी इनके दिमाग का दिवालियापन इतना है कि उन्हीं योजनाओं को आज ये लागू कर रहे हैं! सिर्फ जीएसटी का एक उदाहरण मात्र नहीं है, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो कांग्रेस के समय से चलती आ रही हैं। महज नाम बदलकर ब्रेडिंग कर कर इन्होंने वो इम्पलीमेंट कर दीं। चाहे वह 'नेशनल ई गवर्नेंस की योजना' हो, 'आम आदमी बीमा योजना' हो, उसे 'अटल पेंशन योजना' का नाम दे दिया। 'राजीव गांधी शिल्प स्वास्थ्य बीमा योजना' हो, उसे इन्होंने 'प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना' का नाम दे दिया। 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना' हो, इन्होंने उसका नाम बदलकर 'प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना' दे दिया। 'राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना' हो, उसका नाम बदकर इन लोगों ने 'दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना' रख दिया। 'जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रूरल मिशन योजना' हो उसका नाम बदल कर इन्होंने 'अमृत योजना' कानाम रख दिया या फिर 'निर्मल भारत अभियान' हो, उसको बदलकर इन्होंने 'स्वच्छ भारत अभियान' रख दिया। ऐसा इस सरकार ने तीन सालों में क्या कर दिया जो हम इसका श्रेय दें कि तीन साल के अंदर केंद्र सरकार ने बहुत अच्छा काम करा और रहा सहा अब जीएसटी ले आये देश का बेड़ा गर्क करने के

लिए, व्यापारियों का बेड़ा गर्क करने के लिये।

अध्यक्ष महोदय, पहले स्लोगन लाये थे 2014 के अंदर कि 'बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार।' लोगों को लगा कि महंगाई कम होगी, लोगों को लगा कि हमारी कर पर जो महंगाई का बोझ पड़ रहा है, उसको कम करने में ये लोग कमयाबी हासिल करंगे लेकिन हर बार की तरह वो भी जुमला साबित हुआ और आज ये जीएसटी को लागू कर रहे हैं और श्रेय ले रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आता कि केंद्र रसकार इतनी बेशर्म कैसे हो सकती है कि जिस बिल का विरोध वो लगातार सोलह सालों से करते आ रहे हैं, सोलह साल के बाद अचानक से उस बिल से इन्हें क्या अच्छाई, क्या सच्चाई दिखाई देने लग गई!

ये 20 मई का पेपर है हिंदुस्तान का और इसमें पूरा, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है कि सोलह साल का लंबा समय लगा जीएसटी का पास होने में। बहुत सारा उन्होंने इस पर जो है 2004 का, 2002 का कब कब इस बिल को प्रपोज किया गया, सारा बहुत विस्तृत रूप से रखा है। इसमें सबसे जो इंट्रेस्टिंग बात है, अक्तूबर 2013 के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जो कि उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ये कहकर जीएसटी का विरोध करा, ये कहकर गुजरात असेम्बली गुजरात राज्य के अंदर जीएसटी को लागू नहीं होने दिया कि अगर जीएसटी लागू हो जाता है देश के अंदर तो उनके राज्य को सालाना 14 हजार करोड रूपये का नुकसान होगा, इसलिए वो इसका विरोध करते हैं। जब वो मुख्यमंत्री रहते हुए इसका विरोध कर रहे थे और 14 हजार करोड़ सालाना नुकसान एक राज्य को हो रहा था, जीएसटी के आने पर तो

आज वो देश के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री तो वो सिर्फ हैं लोगों के लिये, हमारे लिये लेकिन असल में तो वो परिधानमंत्री और टूरिस्ट मंत्री हैं। अभी भी घूमने गये हुए हैं विदेशों में। समर वकेशन मनाने गए हुए हैं। आप ये बताइये, देश में दंगें हो रहे हैं, देश में महंगाई बढ़ रही है, देश में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़ा हो रहा है, शिक्षा, स्वास्थ्य सब चीजों पर सवाल खड़ा हो रहा है लेकिन आज जो जीएसटी इनको 2000 से लेकर आज 2013 तक एक बहुत बड़ी समस्या देश के भविष्य, देश के व्यापारी, देश की जनता के लिये लगता था, आज अचानक से मैं जानना चाहती हूं अध्यक्ष जी कि ऐसा क्या हो गया जो ये जीएसटी देश हित में हो गया? ये जीएसटी बिल आज जनता के हित में हो गया, इस जीएसटी के आने से कैसे महंगाई कम होगी, मुझे समझ नहीं आता!

अध्यक्ष जी, ये अपने आप में बहुत बड़ा संदेह खड़ा करता है कि जीएसटी में आपने झाड़ू जो कि हर घर की बेसिक नीड है, झाड़ू पर आपने पांच परसेंट का टैक्स लगा दिया जो कभी नहीं लगा आज तक। जीरो परसेंट स्टेट में भी और जीरो परसेंट सेन्टर में भी। कहीं पर भी चले जाइये, झाड़ू पर कभी टैक्स नहीं लगा। चूंकि अब झाड़ू आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह हो गया और इन्हें दिन रात डराता रहता है तो जीएसटी के माध्यम से इन्होंने झाड़ू पर भी पांच परसेंट का टैक्स लगा दिया। ऐसा क्या हो गया भाई? झाड़ू से अब तुम्हें इतना डर क्यों लगने लग गया? झाड़ू पर बताओ, भला कौन टैक्स लगाता है? झाड़ू तो एक गरीब की जरूरत और एक अमीर की भी जरूरत है। इन्होंने झाड़ू पर भी टैक्स लगा दिया। लेकिन वाईन पर नहीं लगायेंगे, लिक्कर पर टैक्स नही लगाएंगे। लिक्कर को जीएसटी से बाहर रखेंगे क्यों? क्योंकि, वहां पर इनका

काला धन सफेद होता है, वहां पर इनकी जो आय से अधिक संपत्ति है, वहां पर उसे छुपाया जाता है। वो एक जरिया है कि आय से अधिक संपत्ति और काले धन को कैस यूटिलाईज किया जाये। वो इस कांग्रेस और बीजेपी के लोगों की साजिश के तहत एक बहुत बड़ी लॉबिंग के तहत आज वाईन को और लिक्कर को जीएसटी से बाहर रखा गया। वहीं इनका बस चले तो देश में झाड़ू बैन करा दें, झाड़ू से इन्हें इतना डर लगता है क्योंकि वो आम आदमी पार्टी और अरविंद की पार्टी का चुनाव चिन्ह है। मजबूरी है कि झाड़ू से सफाई होती है और एक दिन इनकी भी हो जायेगी, जैसे दिल्ली के अंदर हुई है।

उसी प्रकार से प्लास्टिक वेस्ट पर दिल्ली सरकार ने भी कोई टैक्स नहीं लगाया। पहले कोई टैक्स नही था लेकिन आज अचानक से इन्होंने 18 परसेंट का टैक्स कर दिया। प्लास्टिक वेस्ट का काम कौन करता है? प्लास्टिक वेस्ट का काम गरीब लोग करते हैं जिस पर कोई टैक्स नहीं था, कुछ नहीं था। लेकिन अचानक से इन्होंने उस पर 18 परसेंट कर दिया।

इसके अलावा टिंबर पर इन्होंने बढ़ा दिया, 18 परसेंट कर दिया। होटल्स पर, बहुत सारे होटल मालिकों से बात हुई, वे कह रहे हैं कि टूरिस्ट खत्म हो जायेगा हमारा। किस तरह से ये, मुझे ये समझ नहीं आता अध्यक्ष जी जो नीति आपको सन् 2000 के अंदर व्यापारी विरोधी लगती थी, जनता के विरोध में लगती थी, वो अचानक से हम लागू क्यों कर रहे हैं! ये बहुत बड़ा सवाल है। उसी प्रकार से स्टेनलैस स्टील के जो बर्तन हैं, उस पर भी पांच परसेंट का टैक्स लगता था, दो परसेंट एक्साईज लगता था। उसे बढ़ाकर अब इन्होंने दोबारा से 12 परसेंट कर दिया लेकिन ये बिल्डर्स के ऊपर टैक्स नहीं लगायेंगे।

ये लोग रियल स्टेट को इससे बाहर रखेंगे क्योंकि दोबारा से जिस प्रकार से शराब के अंदर इनका काला धन सफेद होता है, इनकी जो दो नंबर की कमाई होती है, उसको उसमें छुपाया जाता है, उसी प्रकार से रियल स्टेट भी इसी तरह की एक जो इनका तरीका है अपने काले धन का सफेद करने का।

अध्यक्ष जी, अभी मुझसे पूर्व जो वक्ता थे उन्होंने बताया कि हम लोग विकसित देश नहीं, विकासशील देश हैं और यहां पर जहां पर हमें अभी बेसिक चीजें लोगों को प्रोवाइड नहीं करा सकते। सुबह जब बहुत हंगामा हुआ सेशन शुरू होते ही कि एक व्यक्ति की हत्या इसलिये हुई क्योंकि शौचालय आस पास नहीं था और उसे खुले में पेशाब करने के लिये एक रिक्शे वाले ने रोका। हम लोग मूलभूत सुविधाएं अभी तक अपने देश के नागरिकों को नहीं दे सकते, लेकिन जीएसटी लागू करेंगे। हम लाग जीएसटी लागू करके यह साबित करना चाहते हैं कि 'मेकइन इंडिया' के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं बताना चाहती हूं अध्यक्ष जी, जिन देशों के अंदर जीएसटी लागू हुआ, उनका क्या हाल हुआ। जापान के अंदर जीएसटी लागू हुआ, उनका क्या हाल हुआ? जापान के अंदर 1989 के अंदर जीएसटी लागू हुआ जब ये लागू हुआ तो जापान की जो जीडीपी ग्रोथ थी, वो दो प्रतिशत थी और लागू होने के बाद जब जीएसटी लागू हुआ और लागू होने के बाद जो जापान की जीडीपी थी वो एक प्रतिशत हो गई। सोचिए, तो भारत का क्या होगा जहां पर आज हम रोजगार ढंग से नहीं दे पा रहे, जहां पर आज हम लोगों को पीने का पानी, जहां पर लोगों का दो वक्त का खाना हम नहीं दे पा रहे हैं, वहां पर अगर जीएसटी बिल लागू होता है तो देश को हम तरक्की की तरफ ले जा रहे हैं या देश को हम नरक की आर ले जा रहे हैं, ये सोचने का विषय है।

उसी प्रकार अध्यक्ष जी, कनाडा के अंदर 1 991 में जीएसटी लागू हुआ तब जब लागू हुआ तो इसकी जीडीपी थी 1.75 प्रतिशत और लागू होने के बाद इसकी जीडीपी रह गई 0.5 प्रतिशत, माइनस में। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण आंकड़े हैं। मुझे नहीं पता कि जब ये लागू करने की योजना बनाई जा रही थी तो इसके पॉजीटिव-नेगेटिव इफेक्ट्स पर बहुत सारे विशेषज्ञों ने बैठकर चर्चा की होगी, बात की होगी, लेकिन इसे अपने दैनिक जीवन में जब हम लोग धारण करेंगे वो किस तरह की मुश्किलें, हम उन मुश्किलों का सामना कैसे करेंगे, उन मुश्किलों को कैसे खत्म करेंगे, उस पर मुझे लगता है किसी ने भी विचार नहीं करा। क्योंकि जो ये पॉलिसी बनाने वाले लोग थे, उन सब लोगों ने अपने आपको महसूस करके पॉलिसी बनाई लेकिन गरीब व्यक्ति, जो मजदूर व्यक्ति है, उन पर ध्यान नहीं दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : राखी जी, कंकलूड करिए अब, कंकलूड करिए प्लीज।

सुश्री राखी बिड़ा : अध्यक्ष महोदय, 1994 के अंदर जीएसटी बिल लागू हुआ जब जीएसटी बिल लागू हुआ तो जीडीपी ग्रोथ जो सिंगापुर की थी वो 5.6 प्रतिशत थी और जीएसटी लागू होने के बाद जीडीपी रह गई सिंगापुर की -3 प्रतिशत। ये बेहद दु:खद है।

उसी प्रकार से आस्ट्रेलिया का हाल हुआ। 2000 में जब वहां से जीएसटी लागू हुआ, जीडीपी थी एक प्रतिशत और जीडीपी घटकर रह गई-1.75 प्रतिशत। मलेशिया में भी 2015 के अंदर जीएसटी जब लागू हुआ उसकी जीडीपी थी दो प्रतिशत और घटकर रह गई–एक प्रतिशत।

ये आंकड़े अध्यक्ष जी, मैं आपके सामने इसलिए रख रही हूं कि देश के बहुत सारे विशेषज्ञ बैठे, देश के राज्यों के वित्त मंत्री बैठे लेकिन जिस प्रकार से दिल्ली के वित्त मंत्री ने सवाल उठाए और एक पूरी लिस्ट प्रपोज करी है कि जिन पर हम लोगों ने टैक्स बढ़ाया है, क्या प्रपोज्ड टैक्स होंगे जैसे ऑटो स्पेयर पार्टस के एक्साइज लगता है साढ़े बारह परसेंट और जीएसटी क बाद ये बढ़कर हो जायेगा। 28 प्रतिशत लेकिन दिल्ली सरकार के वित्त मंत्री ने इसका प्रपोज्ड टैक्स स्लैब रखा है। 18 प्रतिशत उसी प्रकार से मार्बल पर 5 प्रतिशत लगता है लेकिन बढ़ाकर 28 प्रतिशत कर दिया। हम लोगों ने पुनः उसे 5 प्रतिशत लगाने की बात कही है या इलैक्ट्रिकल पार्टस हो जिसको बढ़ाकर जीएसटी में 28 प्रतिशत किया जा रहा है, हमारी फिर से गुजारिश है कि इसे 12 प्रतिशत किया जाए। तमाम मुद्दें हैं अध्यक्ष जी, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, लगभग चार-साढ़े चार हजार आइटम इसके अंदर हैं।

अध्यक्ष महोदय : कंकलूड करिए राखी जी, अब प्लीज कन्कलूड करिए।

सुश्री राखी बिड़ला : बिल्कुल, कन्कलूड कर रहीं हूं अध्यक्ष जी। आपके माध्यम से और पूरे सदन के माध्यम से ये बात पहुंचे, हमारे वित्त मंत्री वहां पर हमारे नुमाइन्दे बनकर जाएंगे कि लिक्कर को भी, वाईन को भी और जो रियल स्टेट है, उसको भी जीएसटी के अंतर्गत लाना चाहिए तभी काला धन रूकेगा, तभी भ्रष्टाचार रूकेगा वरना उसके बिना ये सब रूकना असंभव है। बस इन्हीं शब्दों के साथ एक बार ये जीएसटी बिल जो लागू होगा चूंकि हम सहयोग करने में विश्वास रखते हैं लेकिन बिल की जो खामियां हैं, इस बिल से जो नुकसान होने वाला है जनता को, वो भी रखना जिम्मेदारी के

साथ हम लोगों का अधिकार है। तो ये जीएसटी बिल कि समर्थन में तो हम हैं ही, लेकिन इससे होने वाले जो नुकसान हैं, उस पर मुझसे पूर्व भी वक्ताओं ने प्रकाश डाला और जब ये लागू हो जाएगा एक जुलाई से तो देखिएगा किस प्रकार से देश में हा-हाका मचता है। अभी लगातार व्यापारी प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार व्यापारी हम लोगों से मिल रहे हैं, अपनी समस्याओं को रख रहे हैं तो जितना संभव हो सके जो 28 प्रतिशत का यहां पर लगा रहे है टैक्स, उसे कम करन की कोशिश करें और रियल स्टेट के लिए हमारी लगातार मांग है और शराब के लिए हमारी लगातार मांग है कि जीएसटी के दायरे में इसे लाना चाहिए। आपने मुझ बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री विजेन्द्र गुप्ता जी, नेता-प्रतिपक्ष।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, जीएसटी एक बड़ा फैसला है। एक ऐतिहासिक कदम है। देश के इन्डायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर में एक बड़ा बदलाव है। डिजीटल इंडिया इसकी पृष्ठभूमि में है। दो तरह के टैक्सिज हैं देश में, डायरेक्ट टैक्सिस और इन्डायरेक्ट टैक्सेज। दुनिया के विकसित देशों में डायरेक्ट टैक्स अर्थात् इंकम टैक्स क्योंकि हर इन्डविजुअल देता है तो इसलिए वहां पर डायरेक्ट टैक्स जो है, वो मेन स्ट्रिंग होता है। लेकिन चूंकि भारत जैसे बड़े विशाल देश में डाइरेक्ट टैक्स जिसमें 60 प्रतिशत लोगों को कृषि से जुड़े हुए व्यवसाय में गरीबों को और सभी प्रकार के लोगों को टैक्स से एग्जेम्प्ट किया जाता है, इसलिए हम डायरेक्ट टैक्स पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। हमें अपने इन्डायरेक्ट टैक्सैशन को मजबूत करने की जरूरत है। इन्डायरेक्ट टैक्सिज दिल्ली में जो करदाता हैं, उनकी संख्या लगभग आठ लाख हैं।

अध्यक्ष जी, मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि आपने दो दिन पूर्व सदन के सभी सदस्यों के लिए एक ओरियन्टेशन प्रोग्राम ऑर्गनाइज किया। मैं मंत्री जी को भी बधाई दूंगा कि उन्होंने सदस्यों के सामने विस्तार में इस पूरी योजना की जानकारी बांटी। 43 हजार करोड़ रूपया प्रति वर्ष दिल्ली को जीएसटी में जो सब्स्यूम किया गया है, सैन्ट्रल टैक्सिज को और दिल्ली स्टेट के टैक्टिसज को उसमें 43 हजार करोड़ रूपया लगभग आ रहा है यानि कि दिल्ली की आमदनी में पांच से छः हजार करोड़ की बढ़ोत्तरी होगी और उसके आधे के हकदार 43 हजार करोड़ में से साढ़े इक्कीस हजार करोड़ की हकदार दिल्ली की सरकार होगी, दिल्ली की जनता होगी। ये दिल्ली के रैवन्यू को बढ़ाने में एक कारगर और टैक्स की चोरी को रोकने में, टैक्स इवेजन को और साथ में जो कम्प्लिकेशंस थी कि बहुत सारे टैक्सिस, बहुत तरह के टैक्सिज एक्साइज अलग, सैन्ट्रल को बढ़ाने में एक कारगर और टैक्स की चोरी को रोकने में, टैक्स इवेजन का और साथ में जो कम्प्लिकेशंस थी कि बहुत सारे टैक्टिसम, बहुत तरह के टैक्टिसज अलग-अलग, अलग तरह के उमसें बहुत सार लोग निकल जात थे 'वन नेशन वन टैक्स' की ये जो थ्योरी है, ये बहुत हद तक कारगर सिद्ध हो रही है। यहां पर मैं ये कहना चाहूंगा कि इस सारे कार्यक्रम में दिल्ली के वित्त मंत्री, जिस तरह से बताया गया कि 27 प्रदेश और दो यूनियन टेरिटॅरी विद एसम्बेली और केंद्र से एफएम और एमओएस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ रैवन्यू उसके सदस्य होंगे। एक तिहाई, दो तिहाई वोटिंग राईट होगा, कुल मिलाकर कहा जाता है कि ये कन्सेन्सस का एक प्रोग्राम है। जीएसटी काउन्सिल जो बनाया गया है, जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेन्ड्मन्ट हुआ है। ये पहली बार देश के इतिहास में हुआ होगा कि पूरी

की पूरी लोकसभा ने सर्वसम्मति से किसी भी पार्टी का एक्रॉस दि टूबल सबने यूनैनिमसली इस संविधान के संशोधन को पारित किया। राज्यसभा में सौ प्रतिशत सभी सदस्यों ने, ऐसा शायद हिन्दुस्तान के आजाद इतिहास में बहुत कम बार हुआ होगा। पचास प्रतिशत राज्यों की आवश्यकता होती है कि वो अपने राज्यों से उसको पारित करके अपनी-अपनी विधान सभाओं से भेजें लेकिन देखा गया है कि हर विधान सभा ने उसको पारित करके यूननिमसली, वहां भी यूनैनिमसली यानी कि एक ऐसा बिल जिस पर पूरा दश 'वन नेशन वन टैक्स' की सही परिभाषा को परिभाषित किया गया।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस तरह के इस आर्थिक बदलाव के दौर में इस सदन के समक्ष खुशी का इजहार करता हूं लेकिन कुछ बातें उठ रही हैं, जिन पर बात की जा रही है लिक्कर की, रियल स्टेट की, पैट्रोलियम की पैट्रोलियम अर्थात् पैट्रोल, डीजल, नैचुरल गैसिज पांच तरह के, उसक बाद इलैक्ट्रिसिटी की, एजुकेशन की और हैल्थ की, जिसको जीएसटी से बाहर रखा गया है। वास्तविकता तो ये है कि हमारा स्टैंड एक होना चाहिए। मैं हालांकि कहना नहीं चाहता था लेकिन मैं सदन के समक्ष कहूंगा कि चौदह मीटिंग हुई हैं जीएसटी काउन्सिल की। पहली मीटिंग जो कोन्सटीट्यूटी हुई थी। 12 सितम्बर, 2016 को हुई थी और 31 मई, 2017 यानी कि आज तक लगभग हर मीटिंग में हमारे प्रतिनिधि वित्त मंत्री मीटिंगों में मौजूद रहे हैं। फैसला कन्सैंसस से हुए हैं और उन फैसलों के बराबर के हिस्सेदार दिल्ली के वित्त मंत्री हैं। वो दिल्ली का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उन्होंने उन फैसलों को ओन किया है, उन पर अपनी मोहर लगाई है। एक मुझे बड़ी हैरानी हुई जब ओरिएंटेशन प्रोग्राम में मंत्री जी ने कुछ डीएनए की बात की। ये हम सब जानते हैं कि ये कन्सैंसस

का विषय है, ये भी हम जानते हैं कि केन्द्र का बड़ा साफ मत था। ये जो कन्सैंसस बना है पूरे देश में, इसमें समय जरूर लगा है, इसको जबरन कोई धक्का पेल करके, कोई धक्का मुक्की करके किसी को दबा के इतने बड़े टैक्स रिफॉर्म नहीं हो सकते, इतने बड़े टैक्स रिफॉर्म सबको साथ लेकर ही सम्भव है। क्योंकि जब हम एक नई दिशा की ओर टैकऑफ करें और इसके प्लस और माईनस उन सबको हमको बराबर शेयर करना चाहिए उनको ओन करना चाहिए, ये एक अच्छी स्पोर्टस मैन स्प्रिट इसको मैं कहूंगा। केन्द्र की सरकार चाहती थी लेकिन राज्य नहीं चाहते थे, क्योंकि राज्यों की अपनी वित्तीय व्यवस्थाएं हैं। दिल्ली की व्यवस्था को देखें, हम इस हक में हैं कि सब चीजें भी जीएसटी में शामिल होनी चाहिए थी, लेकिन अगर जब हम आज ये बात कहते हैं कि हमें 5 से 6 हजार करोड़ रूपया अतिरिक्त मिलेगा लेकिन जब हमारी स्टॉम्प ड्यूटी, ट्रांसफर, ड्यूटी, एक्साईज, हमारा कंजम्पशन ऑफ इलैक्ट्रीसिटी, ये तमाम चीजें अगर ये जीएसटी में चली जाती तो आज 50 प्रतिशत का जीएसटी से जो लाभ हमें मिल रहा है, वो समाप्त हो जाता। हम माइनस में भी जा सकते थे। कहने का अर्थ ये है कि कोई भी स्टेट सरकार, राजनीति में पॉलिटिकल पार्टियां आएंगी, जाएगी, सरकारें बनेंगी बिगड़ेंगी। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि हम किस तरह की व्यवस्था खड़ी कर रहे हैं, क्या वो व्यवस्था किसी प्रदेश की वित्तीय व्यवस्था पर कोई बड़ा प्रहार तो नहीं कर देगा। हर रोज पैट्रोल, पेट्रोल को जीएसटी से बाहर क्यों रखा गया, हम जानते हैं कि पैट्रोल से हमें दिल्ली को लगभग 5 हजार करोड़ रूपया, 4 हजार करोड़ रूपया रेवेन्यू आता है। लेकिन अगर हम तमाम रेवेन्यू अपना छोड़ दें, दूसरे हाथ में दे दें पूरा, पहले ही स्ट्रोक में राज्य डिपैंडैन्ट हो जाए तो क्या ये

जीएसटी, जिसको आज हम बड़ी खुशी-खुशी पारित करना चाहते हैं, क्या ये सम्भव होगा कि हम उस खुशी को दूर तक ले जा सकें। लेकिन मैं इसके साथ एक बात ओर कहना चाहता हूं और वो बात ये है कि जो टैक्स स्ट्रक्चर में मंत्री जी से हम उम्मीद करते हैं, मंत्री जी, हमारे मनीष सिसोदिया जी ने कहा कि 32 ऑर्गनाईजेशन हमारे पास आईं और उन्होंने कहा कि हमारा टैक्स बहुत बढ़ गया दिल्ली का। बिल्कुल, हम ट्रेडर्स हैं बेसिकली, दिल्ली के पास क्या है अपना? न हमारी खनन है, न हमारी कृषि है, न हमारे पास कोई औद्योगिक शहर है, ये ट्रेडिंग शहर है। यहां ट्रेडिंग होती है। ये ट्रेड पर निर्भर है, यहां व्यापार होता है। लेकिन मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि क्या उन्होंने जीएसटी की काउंसिलिंग की मीटिंग में एक बार भी व्यापारियों के दर्द को वहां रखा? क्या आपने वहां के फैसलों पर अपनी डिसैंट नोट कराई? ये नहीं हो सकता कि एक तरफ आप कन्सैंसिस बनाने के लिये मोहर लगाएं और दूसरी तरफ बाहर आकर आप ये कहें।

मैं उदाहरण देता हूं, एमसीबी होता है एक, Miniatures Circuit Breaker electirc आईटम है, कैपिसिटर है। मुझे बिजली व्यवसाय के लोगों ने बताया है कि 5 परसैंट वैट था, लगभग सवा 12 परसैंट एक्साईज थी, 2 परसैंट सीएसटी था। टैक्स था 19.25 परसैंट के करीब। अब वो बढ़कर के 28 परसैंट सीएसटी था। टैक्स था 19.25 परसैंट के करीब। अब वो बढ़कर के 28 परसैंट हो गया। ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जिसमें टैक्स 9-10 परसैंट अधिक हुआ होगा। बहुत सारी चीजें ऐसी भी होंगी जिसमें टैक्स कम हुआ, लेकिन मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब ये स्लैब बने 0, 5, 12, 18 और 28 परसैंट के, उससे पहले क्या आपने कोई होमवर्क किया कि दिल्ली के कमोडिटिज पर वो टैक्स

का जो इम्पोजिशन होगा, जो नया स्ट्रक्चर होगा, उसमें कितने ही आइटम्स में टैक्स बढ़ रहा है, कितनी में घट रहा है? अगर आपने होमवर्क किया होता और आपने किया होगा, मैं ये मानता हूं तो वो सदन को उससे जरूर अवगत कराएं और अगर आपने नहीं किया तो ये आपकी बड़ी भूल है कि आपको स्लैब डिसाइड होते वक्त वहां पर दिल्ली के व्यापारियों की बात को प्रमुखता से कहना चाहिए था और अगर उससे विशेष नुकसान हो रहा है, लोगों के ऊपर टैक्स बर्डन बढ़ रहा है, किसी व्यवसाय पर इसका असर पड़ रहा है, तो वो आपको वहां पर रखना चाहिए था। आपने नहीं रखा। मैं माफी चाहूंगा मंत्री जी, आपने जीएसटी लागू हो, इसके लिये कड़ी बात है, मुझे नहीं कहनी चाहिए, इतने अच्छे वातावरण में डिस्कशन हो रहा है लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि आप ऑस्ट्रेलिया गये, 2015 में, वहां का जीएसटी औ वैट सिस्टम स्टडी करने के लिये, 27 सितम्बर, 2015 को गये। उसमें सहाय साहब भी साथ थे और भी एक-दो लोग साथ थे लेकिन बिल हमारी असेम्बली में सबसे बाद में आया जब सब कुछ हो गया, स्लैब बन गये। आप कहेंगे कि दिल्ली को constitutional amendment का पार्ट नहीं बनाया गया, आप कहेंगे स्लैब डिसाईड होने के बाद दिल्ली को सदन में पारित करना था, आप कुछ भी कहेंगे, मुझे मंजूर है। जो भी इस पर अपनी बात कहेंगे लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि आपको स्लैब डिसाईड होते समय आपके पास पूरी जानकारी होनी चाहिए थी और आपको अगर लगता कि ये स्लैब किन-किन कोमोडिटिज को इफैक्ट डाल रहे हैं, किन-किन कोमोडिटिज के ऊपर इसका वर्टिकल इफैक्ट है, किन-किन कोमोडिटिज पर इसका नैगेटिव इफैक्ट है, बड़ा गैप आ रहा है, आपको वो बात वहां रखनी चाहिए थी और अगर आपकी बात नहीं मानी

जा रही, क्योंकि ये तो फैसला स्टेट्स का है, ये फैसला किसी एक स्टेट का नहीं है, किसी एक सरकार का नहीं है, किसी केन्द्र का नहीं है। इसका जो वन/थर्ड, टू/थर्ड, फिर उसके बाद 75 परसैंट, फिर जो मिनिमम जो वहां का कोरम है, वो 75 परसैंट होना चाहिए। फिर उसको जो कोई भी फैसला लेना है, वो 75, या फिर जो फैसला, आप जिसके हक में नहीं है, उसमें कम से कम 12 स्टेट्स आपके साथ होनी चाहिए। तो ये सब इसके कन्सैन्सस के जो पूरे डायलॉग हैं, पूरा जो जीएसटी काउंसिल का की थीम है, मैं समझ सकता हूं लेकिन दिल्ली की आवाज वहां उठनी चाहिए थी। इस प्रकार से और अगर नहीं मानी जा रही थी, 12 स्टेट्स आपका साथ नहीं दे रही थी, अगर आपको लगता था कि हमारी आवाज मंदी है तो आपको वहां डेसेंट नोट कराकर आना चाहिए था जिससे कि लोगों को लगता कि हमारी बात कही जा रही है।

अंत में, मैं एक इम्पोर्टेन्ट बात जरूर कहूंगा कि म्यूनिसिपल टैक्सेज पर जो इफेक्ट आएगा, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता कि कितना आएगा लेकिन तीन टैक्स जो पूरा मैंने स्टडी किया है, उसमें तीन टैक्स ऐसे हैं, टैक्स ऑन एडवरर्टाइजमेंट एक, दूसरा थियेटर टैक्स और तीसरा टोल टैक्स, हालांकि ओरिएन्टेशन प्रोग्राम में ये बताया गया था कि टोल इसमें कवर नहीं होंगे, वा जीएसटी का पार्ट नहीं होगा। लगभग 634.8 करोड़ रूपया दिल्ली की नगर निगमों को टोल टैक्स से आता है लेकिन मैंने जब इसकी गहराई से जानकारी प्राप्त की तो पांचवें फाईनेंस कमिशन ने जब नगर निगमों से जब पूछा कि आप लिखकर बताएं कि ये जो जीएसटी आ रहा है, इससे आपके किसी टैक्स पर इफेक्ट तो नहीं आ रहा तो उसके बारे में नगर निगमों ने डीएफसी के

सामने लिखकर ये संशय रखा कि टोल्स को एक बार दुबारा से क्रॉस चैक कर लेना चाहिए। क्या ये टोल्स एण्ट्री टैक्स ऑक्ट्राय, क्योंकि मुम्बई म्युनिसिपल कोर्पोरेशन को ऑक्ट्रॉय से एक बड़ी आमदनी होती है, हजारों करोड़ में, और वहां की स्टेट गवर्नमेंट ने उस औक्ट्रॉय को जो जीएसटी का पार्ट बन रहा है, अबोलिश हो जाएगा, ऑक्ट्राय, अलग से उसका कम्पनसेशन देने के लिये महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट ने, मुम्बई म्युनिसिपल कोर्पोरेशन को ये कमिटमैंट किया कि ये सारा पैसा हम आपको उपलब्ध कराएंगे, तो ठीक इसी प्रकार इन तीन टैक्सीज में जहां-जहां भी आवश्यकता हो, आज सदन के समक्ष मंत्री जी इस बात को जरूर एडमिट करें और सदन को ये विश्वास दिलाएं कि म्युनिसिपल टैक्सेज में जो भी कमी आएगी, जो गैप होगा, उसको दिल्ली की सरकार पूरा करके देगी और टोल्स को भी हम बहुत जल्द, हालांकि मुझे स्पष्टीकरण दिया था फाइनेन्स सैक्रेटरी साहब ने कि टोल्स नहीं आएगा लेकिन क्योंकि नगर निगमों के मन में ये संशय है कि जल्द से जल्द उसको दूर करना चाहिए। क्योंकि इसमें बहुत एक हेयर लाईन जितनी भी बात है कि टॉल्स आर एंट्री टैक्स को आप डिफरैन्शिएट कर रहे हैं। डिफरैन्स उसमें क्रिऐट कर रहे हैं। तो वो टोल जो रोड के एगेंस्ट दिया जाता है या ये एन्ट्री टैक्स है क्योंकि एंट्री टैक्स और ऑक्ट्रॉय, ये दोनों को जीएसटी में सब्सिट्यूट किया गया है। तो इसलिए एन्ट्री टैक्स से उसको कैसे आप अलग करेंगे, डिफाईन करेंगे अलग से, इसको गहनता से देखना पड़ेगा। क्योंकि म्यूनिसिपैलिटी जो हे, वो डायरेक्ट जीएसटी का हिस्सा नहीं है और उसके लिए देश की सरकार को ही अल्टीमेट उसको वो करा हो। मैं इतना कहकर ये कहूंगा कि यहां अभी तक ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम इस बिल को पास करने जा रहे

हैं या...क्योंकि जो सदस्यों की भावनाएं यहां आ रही हैं, हो सकता है कि उनको अलग-अलग फीडबैक दिया गया हो कि आप ये बात कर देना, आप ये वाली बात कह देना और दिल्ली की जनता में और देश की जनता में. ..तो दोनों हाथ में लड्डू रखकर आप चलेंगे तो साहब दो नाव पर सवारी करने का फल बहुत अच्छा नहीं मिलता है। इसलिए इस दिशा में चलिए। आंख बंदकर कभी तो दिखाइए कि हम जमकर इस मामले को सफल बनाएंगे। दिल्ली के रेवेन्यू को बढ़ाएंगे, दिल्ली का विकास करेंगे और किसी को कोई तकलीफ नहीं होने देंगे औ ये टैक्स स्ट्रक्चर जो है, उसको सफल करेंगे और पूरे देश के सामने एक उदाहरण बनेंगे, बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : माननीय उप-मुख्य मंत्री जी चर्चा का उत्तर दें उससे पहले सदन में सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए श्री विशेष रवि जी माननीय सदस्य अपना संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

श्री विशेष रवि : सर, आपकी आज्ञा से मैं ये संकल्प सदन के बीच में रख रहा हूं कि सदन का जीएसटी के कानून एवं विचार को समर्थन है लेकिन जिस प्रकार जीएसटी काउंसिल की बैठक में 18 और 28 परसैंट दर के टैक्स को देश पर लादा जा रहा है, ये सदन इसका विरोध करता है। सदन का मानना है कि टैक्स दर ज्यादा रखने से कभी भी सरकारी खजाने में अधिक पैसा नहीं आता है। इससे महंगाई बढ़ती है और टैक्स की चोरी बढ़ती है। इस सदन का प्रस्ताव है कि पूरे देश में 10 परसेंट से अधिक जीएसटी किसी भी गुड्स या सर्विस पर न लगाया जाए और पूरे देश में अधिकतम जीएसटी

10 परसैंट हो जिसका 5 प्रतिशत राज्य के पास हो और 5 प्ररसैंट केंद्र के पास हो, धन्यवाद।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : जा आलरेडी टैक्स लेती है सैन्ट्रल गवर्नमेंट, वो माफ कर दें? वो भी तो हमारा इसका हिस्सा बन रहा है।

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, उन्होंने संकल्प सदन के सामने रखा है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : सैन्ट्रल टैक्सेज जो हैं, उनको आप खत्म कर रहे हैं या चाहते नहीं आप कि वो लिये जाएं, बताइए आप?

अध्यक्ष महोदय : वो काउंसिल डिसाइड करेगी। अभी तीन जून को मीटिंग है, वो जवाब दे देंगे। मानीय गोपाल राय जी भी कुछ कहना चाहेंगे। उससे पहले मैं मनीष जी से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं। अनेक देशों में हम जाते हैं, वहां से कोई चीज परचेज करके लाते हैं। तो एयरपोर्ट पर या उन्होंने व्यवस्थाएं की हुई हैं जो टैक्स मैंने पे किया, वो वापिस मिलता है। जो लेना चाहते हैं। इंडिया में अब तक नहीं था। ये एक बहुत बड़ा कदम होगा टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। क्योंकि अभी दिल्ली में या पूरे देश में अलग-अलग स्टेटों में अलग-अलग टैक्स सिस्टम था। अब जीएसटी हो जाएगा वन टैक्स। तो ये प्रथा अपने देश में भी लागू हो। तीन जून को आप इसको रखेंगे तो मैं समझता हूं कि ये लागू हाने से टूरिज्म देश में बहुत बढ़ेगा। श्री गोपाल राय जी।

श्री गोपाल राय (श्रम मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जीएसटी का लेकर के काफी विस्तार से चर्चा सदन में हुई और न सिर्फ सदन में बल्कि पूरे देश के अंदर इस

पर चर्चा हुई है। जीएसटी से तात्कालिक क्या फायदे होंगे और क्या नुकसान होगा, इसको भी सदन ने कई एंगल से कई पहलुओं से रखा है लेकिन इस सदन के अंदर तीन बातें मैं आपके सामने रखना इस लिए चाहता हूं कि कोई भी परिकल्पना जब समाज और राष्ट्र के सामने आती है तो उसका एक तात्कालिक प्रभाव होता है और दीर्घकालिक प्रभाव होता है। जीएसटी इस हिन्दुस्तान के अंदर, हमारे राष्ट्र में लागू हो, ये भारत की जरूरत नहीं रही है। आज भाजपा जो उसका विरोध करती थी, आज लागू करने का तैयार है। कांग्रेस इसकी पैरवीकार बनी। उसके पहले जब इस तरह के राष्ट्र के फायदे के नाम पर जो-जो बड़े-बड़े फैसले इस देश में आए हैं, उसके पीछे दुनिया के कुछ सोचे समझे लोगों की एक मंशा रही है। जीएसटी जिस तरह से लाई जा रही है, देश में 'वन टैक्स वन नेशन' के नाम पर और देश के फायदे की बात हो रही है। इस जीएसटी के आने से देश को फायदा कब है? देश का इकोनोमिक सिस्टम एक न एक दिन इस देश के भविष्य को नुकसान करेगा। इस देश की जो भी ताकत है, उसको एक दिन प्रभावित करने वाला है।

अध्यक्ष महोदय, मैं दो तीन बातों की तरफ जिक्र करना चाहता हूं। इस सदन का इस बात पर गम्भीरता से सोचना जरूरी है। इस देश के अंदर जब न्यू इकॉनोमिक पॉलिसी लेकर के आई गई थी, ऐलान किया गया, डंका पीटा गया। डंकल प्रोपोजल को स्वीकार किया इस देश के सदन ने। किस के प्रपोजल पर? वर्ल्ड बैंक के प्रपोजल पर। आईएनएफ के प्रपोजल पर डंकल प्रपोजल स्वीकार किया गया। कहा गया कि इससे देश का फायदा हो गया। General agreement in Trade and trainee guide को स्वीकार किया इस देश के

पार्लियामेंट ने। उसके बाद क्या हुआ? हिन्दुस्तान की जो पैदावार कुछ नहीं कर पाया। हमारा विकास नहीं हुआ। उन बड़ी-बड़ी कंपनियों ने पैटेंट करा लिया, हिन्दुस्तान कुछ नहीं कर पाया। हमारा विकास नहीं हुआ। उन बड़ी-बड़ी कम्पनियों ने पैटेंट करा दिया गया। इस नाम पर दिया गया कि इस देश का विकास हुआ। आज तक कोई पलट करके पूछने वाला नहीं है। गैटस से इस देश को क्या फायदा हुआ? कोई पलटकर पूछने वाला नहीं, स्पेशल इकॉनोमिक जोन हजारों-हजार एकड़ जमीन जो किसानों से छीनकर बड़ी-बड़ी कम्पनियों को दिया गया, वहां कितना रोजगार पैदा हुआ है। वहां कितना उत्पादन हो रहा है। वहां कितनी फैक्ट्रियां लगी है। सारे स्टेट माफिया हजारों-हजार जमीन जो इस जमीन के खेल को इस जीएसटी में नहीं लाया जा रहा है। इसलिए नहीं लाया जा रहा है कि स्पेशल इकॉनोमिक जोन के नाम पर हजारों-हजार एकड़ बड़ी-बड़ी कंपनियों ने कब्जा करके रखा हुआ है, रियल स्टेट चलाने के लिए कब्जा किया जा रहा है। इस देश के अंदर एक बार फिर इस देश को धीरे-धीरे गुलामी की तरफ पहुंचाया जा रहा है। दुनिया के अंदर आज जितनी पॉलिसियां आ रही है देश के नाम पर, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नाम से कराया जा रहा हो, चाहे कांग्रेस के नाम से कराया जा रहा हो, चाहे थर्ड फ्रंट के नाम से कराया जा रहा हो। न्यूक्लीयर डील इस देश के अंदर कराया गया, फायदा किसका हुआ? दुनिया के अंदर जब इकॉनामी का क्राइसिस पैदा हुआ। दुनिया में जो इकानामिक वर्ल्ड सिस्टम जब क्रैश कर गया, दुनिया जब मंदी की तरफ बढ़ने लगी, उस समय भी हमारा देश खड़ा था। अपने खुदरा व्यापार के दम पर खड़ा था। अपने लघु उद्योग के दम पर खड़ा था। आज इस देश को अंदर से कमर तोड़ने की कोशिश की जा रही है। वॉल

मॉर्ट को लाने की कोशिश हुई। खुदरा व्यापार में लाने की कोशिश हुई। वो भी पॉलिसी पास की जाएगी, इस देश के अंदर रक्षा मंत्रालय में विदेश निवेश का फैसला किया गया। मसला बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का नहीं है। अध्यक्ष जी मैं केवल इतना दर्ज करना चाहता हूं आज सदन के माध्यम से कि इस देश को धीरे-धीरे गुलामी की तरफ ले जाया जा रहा है और एक सोची समझी प्लान्ड और योजना के तहत ले जाया जा रहा है। देश को एक बार सोचना पड़ेगा, नहीं तो हम ऐसी अंधी गली में पहुंच जाएंगे, जहां से शायद वापिस आना मुश्किल हो। अंग्रेजों के जमान में प्रत्यक्ष गुलामी थी। आज इकॉनोमिक गुलामी की तरफ देश का बढ़ाया जा रहा है। अंग्रेजों के जमाने में प्रत्यक्ष गुलामी थी। आज इकॉनोमिक गुलामी की तरफ देश को बढ़ाया जा रहा है। इस सदन को, किसी न किसी को इस पर गम्भीरता से सोचना पड़ेगा। क्योंकि आज का फायदा सोचना, जितनी हमारी जिम्मदारी है, अपनी आगे वाली पीढ़ियों को इस राष्ट्र के बारे में सोचना भी हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : बहुत-बहुत धन्यवाद गोपाल जी। मैं सदन से आधा घंटा समय बढ़ाया जाए, इसकी प्रार्थना कर रहा हूं। माननीय उप-मुख्य मंत्री श्री मनीष सिसौदिया जी।

उप मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले तो सदन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने सदन के साथियों ने इसके विभिन्न जीएसटी बिल के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की है और ये अच्छी चर्चा है क्योंकि जो माननीय गोपाल राय जी ने बात रखी है, विजेन्द्र गुप्ता जी ने रखी है,

अन्य कई साथियों ने रखी है, राखी बिड़ला जी, अलका जी, सोमनाथ भारती जी से चर्चा शुरू हुई। कई साथियों ने जो भी इनपुट्स मिले हैं, क्योंकि ये एक ऐसा बिल है जो सभी राज्य की विधान सभाएं पास कर रही हैं, धीरे-धीरे कर रही हैं। माननीय विजेन्द्र गुप्ता जी को शायद तथ्यों की जानकारी नहीं है जैसा कि उन्हें कई बार नहीं होती है और हमेशा, हां, और कई बार आधे अधूरे तथ्य ले के आत जाते हैं। आधे अधूरे तथ्य ले के जाते हैं, उसकी सूचना भी इन्हें नहीं होती, उसकी जानकारी भी उन्हें नहीं होती। उसकी कोई प्रामाणिकता नहीं होती। वो कुछ भी बता देते हैं। खैर! मैं मानता हूं, वो अब क्या करें? अगर थोड़े ज्यादा होते तो बता देते। ये 12वीं विधान सभा है देश में जो इस बिल को पास कर रही हैं। आज इसपे चर्चा कर रही है, विशेष बैठक बुलाई है। करेगी, लेकिन धीरे धीरे सब करेंगे। मैं, क्योंकि मेरी सभी वित्त मंत्रियों से लगातार बात होती रही है, हो सकता है अगले एक दो हफ्ते एक हफ्ते एक हफ्ते के अन्दर अन्दर अधिकतर विधान सभाएं करें। सर जी, बीजेपी वालों ने भी नहीं किया, उनसे तो बोला...

श्री विजेन्द्र गुप्ता : आप तो बुरा मान गए।

उप मुख्य मंत्री : बुरा मैं क्यों मानूंगा, आप मानो। बीजेपी की चिंता मैं क्यों करूं, आप करो, ठीक। तो तथ्य आपके गलत है, मैं क्यों बुरा मानूंगा। लेकिन इसके जितने भी पहलुओं पे बात की, वो पहलू इम्पोर्टेंट हैं। देश का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म है। रिफॉर्म कोई भी रेवलूशनरी चैंज, सरकार उसको आगे बढ़ के, उसके प्रोज एण्ड कोन्स को समझते हुए हमेशा समर्थन करती रही है। हम कोई जुमला या डबल स्टैंडर्ड वाली सरकार नहीं हैं कि राज्य

की सरकार में बैठेंगे और केंद्र में किसी ओर पार्टी की सरकार हुई तो केंद्र की नीतियों का विरोध करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति हो सकती है, ये आम आदमी पार्टी की राजनीति नहीं है। इसीलिए आज हम इस बिल को इस सदन में ले के आए, नहीं तो हम कॉपी पेस्ट मोदी जी मार सकते थे। हम भी मोदी जी की पॉलिसी को कॉपी पेस्ट कर सकते थे। जब राज्य की सरकार में रहो तो केन्द्र का विरोध करो। कई सदस्यों ने जो बातें रखी उनमें से मूल बात ये है कि जीएसटी, नितिन भाई ने कई चीजों को रखा कि हम ला क्यों रहे हैं, इसका इंटेंट क्या है कि देश में गुड्स एण्ड सर्विसिज के और कई जो 17 तरह के टैक्सेज हैं, इनकी मल्टीप्लिसिटी है। कई तरह के टैक्स हैं इनकी रिटर्न अलग फाइल करनी पड़ती है। उनके हिसाब से, उनके दफ्तर अलग, उनके अपुसर अलग, उनक रूल्स अलग सब कुछ अलग अलग। तो देश के व्यापारी के लिए ये फायदे की चीज है कि उसको 17 तरह के अलग अलग टैक्स के गवर्न होने की जगह एक से गवर्न में आना पड़ेगा। इन प्रिंसिपल ये एक अच्छी चीज है और इसीलिए हम जीएसटी का समर्थन करते हैं। इसीलिए आज हम इस जीएसटी को यहां पर लेकर सदन में प्रस्तुत हुए हैं। ये देश के व्यापारियों के लिए और देश के व्यापारी को जितनी सहूलियतें होगी, उतनी ही देश कन्ज्यूमर को, देश के आम आदमी को सहूलियत होगी, ऐसा इससे आकलन है। तो ये बात जिस दिन मैं फाइनेंस मिनिस्टर बना और मैंने अपने डिपार्टमेंट का सक्रेटरी और डारेक्टर और सब के साथ रिव्यू लिया उसमें जीएसटी पे चर्चा हुई उस दिन से बल्कि उस दिन से पहले से जब से ये केन्द्र सरकार ने जीएसटी के बारे में बात करना शुरू किया, जब से

उम्मीदबंधी कि अब भारतीय जनता पार्टी आ गई है। कांग्रेस के समय में भले ही विरोध करती थी लेकिन मनमोहन सिंह जी का विरोध किया, पी. चिदम्बरम जी का विरोध किया, अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी योजना में शामिल रहा, उनकी भी योजना का विरोध किया, जब मुख्यमंत्री थे। लेकिन जब केन्द्र सरकार ने अपने को स्पष्ट किया, मैंने तब से तब तक, हम उस दौर में हम सत्ता में नहीं थे। उस दौर में हम यहां सरकार के रूप में नहीं थे, तब भी हमें लगा। हम उस दौरान यहां पे प्रेजीडेंट रूल था, एलजी रूल था। उस दौरान भी मैंने सोचा कि ये दिल्ली के लिए अच्छा है और जब सत्ता में आए तो हमने इसको समर्थन करने के लिए अपना पूरा खाका तैयार किया, अधिकारियों के साथ बैठ करके कि हम इसको आगे बढ़ाएंगे और ये दिल्ली के लिए अच्छी चीज है, देश के लिए अच्छी चीज है जीएसटी, इन प्रिंसिपल, इसीलिए हर बैठक में शामिल हुआ और बल्कि मैंने तो माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध किया है कि जीएसटी की बैठक में किस मंत्री ने क्या कहा, इसके मिनट्स बनते हैं, किसी समय पे क्योंकि ये बहुत बड़ा टैक्स रिफॉर्म है, इसको बकायदा शब्दशः प्रकाशित किया जाए, पता तो चले देश की जनता को कि कौन जीएसटी की काउंसिल में देश के व्यापारियों ओर देश की जनता के हित में बोल रहा था और किस पार्टी का कौन वित्त मंत्री खड़ा होके ये कहता था कि अगर अफसरों ने तय कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, अब हम क्यों चर्चा कर रहे हैं, छोड़ो इसको। पता तो चले वो कौन सी पार्टी के वित्त मंत्री हैं। पता तो चले देश को कि किस पार्टी की बुद्धिमत्ता ये कहती है कि अगर अफसरों ने एक बार तय कर लिया तो माननीय चेयरमैन साहब तो तय

कर लें, सो कर लें, अब हम काहे को चोंच लड़ा रहे हैं इसमें? इस भाषा में भी किसी पार्टी के, मैं क्योंकि मैं, दूसरी पार्टी विजेन्द्र गुप्ता जी समझ रहे हैं मैं किस पार्टी की बात कर रहा हूं उनको पता है किस पार्टी की ओर इशारा है, पता तो चले देश को। तो मैंने इसीलिए उनको रिक्वेस्ट किया था, मैंने इसीलिए माननीय वित्त मंत्री जी का, केन्द्रीय वित्त मंत्री जी को रिक्वेस्ट किया था कि इसके मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स पब्लिक के डॉमेन में जाना चाहिए। जैसे आज कांस्टिट्यूएन्ट असेंबली की डिबेट्स पब्लिक डॉमेन में है, उसी तरह से जीएसटी काउंसिल की जो डिबेट्स हुई, किस वित्त मंत्री ने किस पक्ष को, किस पुरजोर तरीके से रखा, किस पर ऑब्जेक्शन रखा, किस पे प्वाइंट ऑफ ऑर्डर रखा, किस पे डिसेंट हो गया, हो गया, हां, तो वो चीजें पता तो चले देश को कौन पूरी 14 बैठकों में एक बार भी नहीं बोला, कौन क्या बोलता था ये सब चीजें आएंगी और उसमें आपको नहीं, अपनी पार्टी के नेताओं को लगे कि ये यार! कहा से चुन लाए हम ऐसे ऐसे लोगों को! अब बात करेंगे उसके बाद। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ये भी आपको पता चलेगा...नहीं, नहीं, मैं कह रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, कई सदस्यों ने बात रखी, मैं उसमें उसके लब्बोलुआब को समराईज करते हुए कहना चाहता हूं कि देखिए, यहां जितनी बातें रखी गई, एक है जीएसटी कॉन्सेप्ट और जीएसटी एक्ट के बारे में आज हम सदन में टेक्निकली जिस बात पे चर्चा करने के लिए बैठे हैं कि जीएसटी की कॉन्सेप्ट और जीएसटी का जो बिल यहां पे रखा है। दूसरा है, जीएसटी के प्रोसिर्जस; टैक्स सलेब्स, फिटमेंट्स उसके रिटर्न, उसके फार्म्स, इसको एक्ट में नहीं रखा

गया है। इसको जीएसटी काउंसिल हमेशा डिसक्स करेगी और अगे भी करती रहेगी। सरकारें केन्द्र में भी बदलेंगी, राज्यों की भी बदलेंगी, मंत्री, वित्त मंत्री सब बदलते रहेंगे, समय-समय पे लेकिन ये लांग रन में हमेशा तय होता रहेगा। एक है इसकी फाउंडेशन जीएसटी एक्ट। तो आज हम जिस चीज के लिए डिसिजन लेने के लिए यहां बैठे हैं कि हम जीएसटी एक्ट को मंजूर करते हैं कि नहीं करते। तो मेरा सदन के सदस्यों से आग्रह रहेगा कि जीएसटी एक्ट हो, क्योंकि इन प्रिंसिपल एक अच्छी कॉन्सेप्ट है, इसको मंजूर किया जाए लेकिन जहां तक माननीय सदस्यों ने कुछ चीजें रखी हैं, नेता विपक्ष ने भी उन चीजों की तरफ कुछ इशारा किया। उनका दर्द मैं समझता हूं कि पार्टी से हैं, विपक्ष में हैं, तो बोलना तो पड़ेगा ही। लेकिन रोहिणी जिस विधान सभा को रिप्रेजेंट करते हैं, दिल्ली में भी नेता विपक्ष के नाते उनके पास भी लोग आते होंगे, उनसे बताते होंगे कि भाई, ये जीएसटी में क्या करवा दिया! कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनको समराईज करके मैं क्योंकि कल मेरे पास कुछ लोग आए थे, क्योंकि मैं यहां सदन में आने से पहले भी और तीन तारीख की बैठक में आने से पहले नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बात रखी, आपने वहां रखा कि नहीं रखा, मैं इस सदन को सूचित करना चाहता हूं, इस सदन के रिकॉर्ड में लाना चाहता हूं कि जितना फिटमेंट का काम था, टैक्सेशन का, टैक्स के स्लैब्स का, वो एक घण्टे में खत्म हो गया होता। मैं विरोध नहीं करता तो, वो एक ही मीटिंग में खत्म हो गया तो तीन तारीख की मीटिंग रखी इसलिए क्योंकि इस सदन में दो बजट में कई चीजों पे टैक्स कम किया और मैं पुरजोर तरीके से वहां रखता रहा कि नहीं, दिल्ली में होटल्स में 250 रूपये का कमरा कुछ मायने नहीं रखता है। हमारी विधान सभा ने 15 सौ तक के कमरे पर हम लोगों

ने लग्जरी टैक्स माफ किया हुआ है और कई राज्य अपने अपने हिसाब से रख रहे थे लगभग लगभग डिसिजन हो चुका था। मैंने कहा, ''नहीं दिल्ली की तरफ से ये मैं स्वीकार नहीं करता और मैं इसका पुरजोर विरोध करूंगा, अन्दर भी करूंगा और बाहर भी करूंगा।'' उसकी वजह से इसी तरह से कपड़े पर, फेब्रिक पर हमने ये डिसिजन लिया था, हम कुछ टैक्स रखेंगे, फिर हमने वापस लिया उसको। उसके फायदे हुए। इसी तरह से चप्पल जूता, प्लस सस्ता चप्पल जूता पर ये सारी डिसिजन क्योंकि यहां का एक्सपीरियंस था। इस एक्सपीरेएन्स को मैंने वहां रखा। इसकी वजह से एक और मीटिंग जीएसटी काउंसिल को तीन तारीख की बुलानी पड़ी। नहीं तो ये तो उसी मीटिंग में सब कुछ तय हो गया हाता। वहां बड़े-बड़े टैक्स लगाने की योजना है। बहुत सारी चीजों पर रोका, यथाशक्ति जहां तक रोक सकते हैं।

माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, जीएसटी काउंसिल में हमारी हैसियत है, जैसे आपकी यहां पर। संख्या तो उतनी ही है। देखिए, डेमोक्रसी संख्या बल से ही चलती है। मैं रखता हूं चीजों को। इन प्रिंसिपल बार-बार मैंने इस बात को रखा है जीएसटी काउसिल में कि साहब, केंद्र और राज्य में कौन सी पार्टियां है, चलिए, बहस नहीं करते हैं आपस, पर आपको पता है। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में बार-बार मैंने इस चीज को रखा है कि जीएसटी काउंसिल का, जीएसटी का फोकस पब्लिक सेंट्रिक होना चाहिए, आफिसर्स सेंट्रिक नहीं होना चाहिए। बहुत बार मैंने इस डिसकसन को डायल्यूट कराया कि हम आफिसर्स क्या करेंगे, कौन आफिसर्स होंगे। कौन सी के हाथ में कितना अधिकार होगा, इस सब पर इतना समय लगा रहे हैं। अरे! जनता टैक्स देगी। व्यापारी टैक्स लेगा, वो कैसे यहां तक पहुंचायेगा, उसके बार में ज्यादा चिन्ता करो। इसके

बारे में चिन्ता मत करो कि किस तरफ के बैठे हैं, अफसर, किस तरफ के अफसर क्या फैसला लेंगे, कैसे उसको। आफिसर्स सेंट्रिक, पेपर सेंट्रिक, क्लास सेंट्रिक नहीं, पीपल्स सेंट्रिक टैक्ससेसन सिस्टम करो, अगर इतना बड़ा टैक्स रिफार्म कर रह हो, तो इसको मैंने बहुत पुरजोर तरीके रखा है। इस बात को रखा है। दिल्ली के अनुभव के साथ मैंने इस बात को रखा है कि टैक्स जितना कम होगा, उतना ही उसका कम्पलाएन्स, टैक्स रेट जितना कम होगा, उतना ही उसका कम्पलाएन्स ज्यादा होगा। आप बीस परसेन्ट, पच्चीस परसेन्ट, अट्ठाईस परसेंट, चालीस परसेंट टैक्स कर दीजिए। जिस-जिस आईटम पर आप ज्यादा टैक्स लगायेंगे, उस-उस आइटम को खरीदने वाली जनता रोयेगी और उस-उस आइटम पर व्यापार करने वाला व्यापारी चोरों की श्रेणी में शामिल होता रहेगा क्योंकि वो टैक्स चोरी करवायेगा और अगर वो टैक्स चोरी होगा, वहां पे इवेजन होगा। जितना आप लोअर टैक्स रखेंगे, उतना फायदा है। जैसे मैं छोटे-छोटे से उदाहरण और कैसी-कैसी चीजों को, मैं क्योंकि सहमत हूं और तीन तारीख की मीटिंग में इस बात को रखूंगा और मैंने 17-18 में भी रखा था इन चीजों को। कल व्यापारी आये आप्टिकल्स लन्सेज, ग्लासेज वाले, बोले, ''साहब, ये चश्मा नजर की बीमारी तो आज आम बच्चे-बच्चे को हाती है। अब उस चश्में पर भी हमने 28 परसेंट टैक्स लगा दिया। ये तो ठीक नहीं है।'' बात ठीक है जी। भई, लग्जरी आइटम थोड़ी है। कोई शौक के लिए थोड़ी लगा रहा है। ये तो नीड है। बच्चे-बच्चे की नीड हो गयी है आज की तारीख में। चश्मा, पांचवीं-छठी उम्र से लग जाता ह बहुत सारे लोगों को। तो इस पर हमें पीपल्स एन्ट्रिक सोच लगानी पड़ेगी। इस चीज को मैंने रखा है और आग भी मैं रखूंगा। मैंने, आटा पर टैक्स लगा रहे हैं, विरोध किया। इसीलिए तीन तारीख तक

पोस्टपोन्ड हुआ। आगे भी विरोध करूंगा इस चीज का। हर चीज का विरोध करता हूं जो चीज हॉयर टैक्स रेट की तरफ जाती है, इन-प्रिंसिपल हॉयल टैक्स के विरोध करूंगा इस चीज का। हर चीज का विरोध करता हूं जो चीज हॉयर टैक्स रेट की तरफ जाती है, इन-प्रिंसिपल हॉयर टैक्स के विरोध में हूं वहां पर। ये मार्बल के लिए कहा, ''मार्बल बड़ा लग्जरियस आईटम है जी।'' सर जी, मार्बल जब लोग करोड़ों-करोड़ों रूपये के घर बनाते हैं तो लग्जरियस आईटम होता है लेकिन एक दिल्ली में किसी अनॉथराईज कालोनी में, अथराइज कालोनी में छोटा सा फ्लैट, डीडीए के फ्लैट में, 80 गज के, 50 गज के, 100 गज के फ्लैट में रहने वाला आदमी जब अपना बॉथरूम रिपेयर रता है और उसको दस हजार रूपये का मार्बल मार्केट से खरीद के लाना पड़ता है, दो हजार रूपये का वॉशरूम और फिटिंग्स लानी पड़ती है उस पर अगर वो 28 परसेंट टैक्स देगा तो वो बहुत भारी पड़ेगा सर, उसको। हम एक-एक, दो-दो करोड़ के मकानों के बारे में, कोठियों के बारे में सोच सकते हैं। हम चमचमाते मार्बल के बारे में सोच सकते हैं लेकिन आम आदमी की आज की तारीख में ये सोचता है कि बाकी घर में मार्बल कहीं हो या न हा। कम से कम मेरे बॉथरूम में और मेरी किचन में थोड़ा सा टाइल्स हो जाये। वहां टाइल्स हो जाये, साफ-सफाई रहेगी वहां पर। वह महंगा हो जायेगा तो कैसे काम चलेगा! इस चीज को मैंने रखा है। कल और भी लोगों ने अपनी बात रखी। आटो पार्ट्स वालों ने, इलैक्ट्रिक आइटम्स वाले ने रखा। साहब, पंखा है। हम इलेक्ट्रिकल आइटम कहते हैं। इलैक्ट्रिकल आइटम कोई छोटी चीज नहीं है, बड़ी चीज है। अरे! एक घर में बल्ब, ट्यूबलाईट बदलना किसी को अगर दो हजार रूपये का पंखा लेना हो, उस पर अगर आप 28 परसेंट का टैक्स लगा दोगे तो

वो तो 1300 रूपये का, साढ़े बारह सौ रूपये का हो गया। इन चीजों का तो वहां भी विरोध किया, बाहर भी विरोध करेंगे और अन्दर नहीं सुनेंगे तो बाहर भी विरोध करेंगे। अन्दर सुनेंगे तो खुश होके कहेंगे, बहुत बढ़िया डिसीजन लिया।

अध्यक्ष महोदय, अभी कुछ और चीजों की तरफ जिक्र हुआ। टिम्बर, प्लाईवुड, इन सब पर मैं पहले भी बोल चुका हूं। बड़ी इन्टरेस्टिंग चीज थी। कल कुछ व्यापारियों ने रखी। क्योंकि जब व्यापारियों से बात करते हैं, मैं कम से कम नहीं तो, जिस तरह की मीटिंग मैंने कल की है, कम से कम डेढ़ दर्जन मीटिंग्स मैंने अलग-अलग समय पर व्यापारियों के साथ की है। एक्सपर्टस के साथ की हैं। सारी जनता में, मार्केट में जाके लोगों से बात की है। जनता के, एसोसियेशन के अलावा ऑर्डिनरी दुकान वालों से, क्या समझते हो, क्या करना है, कैसे करना है? कल एक बडी इन्टरेस्टिंग चीज लेके आये। बोले साहब, उसका उदाहरण दिया कढ़ाई का और कड़छी का। बोले, ''साहब चम्मच 18 परसेंट पर और कटोरी 12 परसेंट पर।'' अब खाना, खाना हो तो बारह परसंट की कटोरी और 18 परसेंट की चम्मच और अगर गलती से डिनर सेट खरीदने चले जाओ, तो कितने परसेंट लगेगा? पता नहीं, क्योंकि उसमें कटोरी भी होती है और चम्मच भी होता है, तो कुछ प्राब्लम्स भी हैं और मैं यहां ऑन रिकार्ड कह सकता हूं कि जब-जब मैंने काउंसिल की मीटिंग में इन चीजों को रखा है क्योंकि अलग-अलग राज्य हैं। बीजेपी बाहुल्य हैं अभी वित्त मंत्रियों का भी, लेकिन माननीय वित्त मंत्री अरूण जेटली जी को जब-जब मैंने बहुत फैक्ट के साथ में चीजें रखी हैं। उन्होंने कन्सीडर भी किया है कुछ चीजों को, हर चीज को नहीं किया। बहुत सारी चीजों को अपने राज्यों के दबाव

में नहीं किया। जैसे की रियल एस्टेट का मसला था। रियल एस्टेट के मसले पर मेरा स्पष्ट मानना है कि और मैंने वहा कहा, बहुत विरोध करके कहा कि साहब, ये हम देश के ब्लैक मनी को व्हाइट करने की बात करते हैं। हमेशा कहते हैं कि ब्लैक मनी खत्म होना चाहिए, ब्लैक मनी निकल के आना चाहिए। ब्लक मनी पाइप लाइन में आना चाहिए। देश की सप्लाई चेन में आना चाहिए और रियल एस्टेट में सबसे ज्यादा ब्लैक मनी है। रियल एस्टेट वो सेक्टर है, जहां देश का सबसे ज्यादा ब्लैक मनी लगता है। कौन आदमी कितने फ्लैट खरीद के डालता है, कौन आदमी कितने रियल एस्टेट की कम्पनियां चला रहा है, किसके घर के नाम पर, कितने बीबी-बच्चों के नाम पर, रिश्तेदारों के नाम पर, देश भर में रियल एस्टेट की कम्पनियां चल रही हैं, इसको लेके आइये जीएसटी के दायरे में। पता चलना चाहिए। कहां है कितना सीमेंट आ रहा है, कहां से कितना रेता आ रहा है, कहां से ये सारी चीजें क्लब होके फिर मकान बन रहे हैं, मकान बिक रहे हैं, सारी चीजें टैक्स नेट में एक ही नेट, एक ही चेन में होनी चाहिए। चेन में आयेंगी तो पकड़ में आयेंगी और इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। अब आईटीसी तो मिलेगा नहीं। आप सीमेंट पर टैक्स देंगे, आप लोहे पर टैक्स देंगे, आप बाकी चीजों पर टैक्स देंगे। अचानक घर पर जीएसटी नहीं है। इन पुट क्रेडिट किस पर मिलेगा। तो इनपुट क्रेडिट की चेन भी तोड़ दी। ऊपर से ब्लैक मनी का रास्ता खुला छोड़ दिया और इसीलिए छोड़ दिया जानबूझके। मुझे आश्चर्य है और मैं कह सकता हूं कि लगभग-लगभग, मैंने उस दिन भी वहां बोला था ट्रेनिंग में। सारे वित्त मंत्रियों ने, कई राज्यों के वित्त मंत्रियों न इस चीज का विरोध किया कि नहीं साहब, जीएसटी के दायरे में रियल एस्टेट को जीएसटी, क्यों नहीं, लाओ भाई जीएसटी के दायरे में कोई

जवाब नहीं है, बस, लाइये मत। कोई लॉजिक नहीं है, लाइये मत। क्यों? आप सारे बीजेपी वाले मंत्रियों ने कहा, सारे। सारे बीजेपी के फाईनेंस मिनिस्टर्स ने कहा, नहीं साहब, रियल एस्टेट इसके दायरे में नहीं आना चाहिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अच्छा, आप ये बताओ कि सेन्टर ने सपोर्ट किया कि नहीं किया?

उप मुख्य मंत्री : अच्छा, आपकी बाकी वित्त मंत्रियों से दोस्ती है कि नहीं है?

श्री विजेन्द्र गुप्ता : देखिए, जीएसटी काउन्सिल तो मैटर परसेन्टेज है। आप ये बताइये, केन्द्र का जो एक-तिहाई हिस्सा है।

उप मुख्य मंत्री : अरे! हम भी तो राज्य थे। चलो, हम भी राज्य थे। हम भी तो विरोध कर रहे थे। नहीं, मैंने कहा कि जब मैं फैक्ट के साथ में चीजें रखता हूं, मैंने चिट्ठी लिखी। अरूण जेटली जी ने कहा, इसको दोबारा ओपेन. ..एक बार चेप्टर क्लोज हो गया। मेरी चिट्ठी के बाद अरूण जेटली जी ने कहा कि इसको दोबारा ओपन किया जाये। फिर से बीजेपी के मंत्रियों ने कहा, नहीं जी, ये तो हमने क्लोज कर दिया है, इसको क्यों ओपन करना है?

श्री विजेन्द्र गुप्ता : वो मंत्री प्रदेश हैं।

उप मुख्य मंत्री : अच्छा, वो प्रदेश हो गये, वो भाजपा नहीं हैं?

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, अगर केंद्र चाहे तो अपने शासित प्रदेशों को तो ठीक कर ही सकता है न जी, अगर केन्द्र चाहे।

उप मुख्य मंत्री : अरे! आप क्यों जस्टिफाई कर रहे हो राज्यों को? स्टेट में, बीजेपी के राज्यों ने।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : मैं भी कहता हूं, ''गलत किया।''

उप मुख्य मंत्री : बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जिसने भी किया, गलत किया। जिसने भी किया, ब्लैक मनी को सपोर्ट करने के लिए किया। ये नहीं चलेगा। केन्द्र में बीजेपी तो केन्द्र की बीजेपी टूर्नामेन्ट और राज्यों की बीजेपी गुल्ली-डंडा। ये नहीं चल पायेगा। तो अध्यक्ष महोदय, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको, जरीगोटा की छोटी-छोटी चीजें, हैण्डीक्राफ्ट, इन सब पर भी 28 परसेंट टैक्स कर रखा है, करने की कोशिश कर रहे हैं। इन सबको रूकवायेंगे। जायेंगे तीन तारीख को और इन सबका विरोध करेंगे कि नहीं करने देंगे, ये इनको। हैंडबैग्स की बात करते हैं तो बात वही होती। बड़ा-बड़ा लग्जूरियस आईटम होगा जी। बड़ा सूटबूट वाला। अरे! सर जी, हरेक के जेब में पर्स रखा हुआ है। ये पर्स, इस पर 28 परसेंट का टैक्स लगा दिया। बताइये, ये कैसे करेंगे? महिलाओं के पर्स पर छोटे-छोटे पर्स और छोटे-छोटे एक्जीक्यूटिव पर्स लेके चलते हैं लोग। छोटे-छोटै बैग आजकल लेके चलते हैं लड़के-लड़कियां। उन पर भी 28 परसेंट का टैक्स कर दिया जी। बजट वाला भी है। हमारे बजट वाले पर नहीं किया। उस पर भी करने के चक्कर में हैं 5 परसेंट

अध्यक्ष महोदय, होटल इंडस्ट्री वालों ने बड़ा अच्छा कहा। जब हमने यहां होटल इंडस्ट्री वालों को सपोर्ट किया था तो बड़ा अच्छा पोजिटिव माहौल था लेकिन अब होटल इंडस्ट्री वाले बहुत दु:खी हैं, चिंतित हैं इस बात को लेकर। कल वो अपना लॉजिक लेकर आये थे। बोले जी, थाइलैंड में 6 परसेंट टैक्स

है होटल पर। आप यहां पर 28 परसेंट करोगे तो कैसे टूरिस्ट आकर रूकेगा यहां पर? भले ही हम सोच सकें कि जो आदमी पांच हजार का कमरा अफोर्ड करता है, आठ हजार का कमरा अफोर्ड करता है, उसको देने दो बढ़ा टैक्स, लकिन हकीकत यह है कि उसी से टूरिस्ट इंसेंटिव भी होता है न। आप सिर्फ टैक्स इकट्ठा करके सरकारी खजाने को लबालब भरने का क्यों सोचते हो। देश के लोगों की जेब भरी रहे, सरकारी खजाना तो अपने आप भरेगा। देश के लोगों की जेब नहीं भरी रहेगी, देश के लोगों की जेब काटोगे तो सरकारी खजाना भी नहीं भर सकता, यह प्रिंसिपल देख लीजिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं कन्क्लूड करते हुए दो-तीन चीजें और कहूंगा जिन पर अभी बाकी चर्चा मुझे आगे भी करनी है कि एक तो पूरे देश की मार्किट का इस वक्त विलिंग्ली और अनविलिंग्ली चाइना कि मार्किट से कम्पीटिशन है और भी कई देशों के मार्केट हमारे मार्किट को एकदम ड्रेगन की तरह से झपटने के लिए बैठे हैं। इन सब चीजों को देखते हुए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि जो मैं बात रख रहा हूं या कई और सदस्यों ने रखी क्योंकि रखी तो उसका चर्चा मैं जवाब देना है। इसका एक्ट से लेना-देना नहीं है। एक्ट एक प्रेक्टिसेज है। एक्ट एक फाउंडेशन है। बाकी जो प्रेक्टिसेज हम एडॉप्ट करें, वो आगे के लिए इम्पोर्टेंट है। उनसे नफा-नुकसान इन सब की बात होगी।

संजीव भाई ने बड़ी अच्छी बात उठाई कि साहब, यह जा जीएसटी एंड कम्पनी है, यह अगर चार हजार करोड़ रूपये राजकीय और केंद्र सरकारों के लगेंगे और वो सीएजी क दायरे में नहीं आयेगी, ऐसा कैसे हो सकता है?

उसको सीएजी के दायरे में आना पड़ेगा। बग्गा जी ने रिटर्न की कॉम्पलैक्सिटी की बात उठाई। ये सारी चीजें हैं जो अगली जीएसटी मीटिंग में भी और उससे अगली जीएसटी मीटिंग में भी, मैं अपने अंदर कमिटेड हूं कि हम इसको ठीक करवायेंगे। इसका ऐसे छोड़ेंगे नहीं।

मैं, आखिर में, सदन के समक्ष यही प्रस्ताव रखता हूं कि ये जो स्टेट जीएसटी बिल है, इसको पारित किया जाये क्योंकि यह एक्ट इन प्रिन्सिपल ओके है, प्रोसीजर पर हम हमेशा और भी डिसकस करेंगे, इनपुट्स लेते रहेंगे, जीएसटी काउंसिल में बात करते रहेंगे, इनको चेंज करायेंगे। जो-जो ट्रेडर्स फ्रैंडली नहीं है, जो-जो व्यापार विरोधी, जो-जो जन विरोधी फैसले वहां से होंगे, उनका विरोध करेंगे, उनके खिलाफ डिसिजन लिवायेंगे, वहां पर और मैं, जा विशेष भाई ने प्रस्ताव रखा, मुझे लगता है कि वो कहीं न कहीं मेरी, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के प्रिंसिपल्स है कि Lower the tax rate more the compliance अगर हम इतना बड़ा रिफॉर्म कर रहे हैं तो एक बार यह रिफॉर्म भी करके देखें कि अगर हम देश में यह 28 परसेंट, 18 परसेंट इन सब का लालच छोड़ें, सारे टेक्सज का 10 परसेंट कर लें। पांच परसेंट राज्य चलें और पांच परसेंट पर केंद्र सरकार काम करें। देखें, देश के लोग खुले दिल के लोग हैं, बहुत टैक्स देते हैं। दिल्ली सरकार इसका उदाहण है। अगर सेंट में भी इसको करके देखें, इसक वाइड डिसिजन लें, बाकी राज्यों के वित्त मंत्री भी इस पर साथ दें तो मुझे लग रहा है कि यह बड़ा टैक्स रिफॉर्म तभी हो पाएगा कि यह दस परसैंट तक आ जाये। अगर पांच-पांच प रसेंट दोनों राज्य और केंद्र बांट लें तो यह दस परसेंट का प्रस्ताव बहुत अच्छा है।

मैं सदन से अनुरोध करूंगा कि इसको भी पारित किया जाये। बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : अब विधेयक पर खंडवार विचार हागा। प्रश्न है कि खंड-2 से खंड-174 विधेयक का अंग बनें। यह प्रस्ताव सदन के सामने हैं–

जो इसके पक्ष में है, वे हां कहें;

जो इसके विरोध में है, वे ना कहें;

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता,

प्रस्ताव पारित हुआ।

खंड-2 से खंड-174 विधेयक का अंग बन गये।

अब प्रश्न है कि अनुसूची-1, 2 तथा 3 विधेयक का अंग बनें। यह प्रस्ताव सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में है, वे हां कहें;

जो इसके विरोध में है, वे ना कहें;

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता,

प्रस्ताव पारित हुआ।

अनुसूची-1, 2 तथा 3 विधेयक का अंग बन गये।

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न है कि खंड-1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक का अंग बनें। यह प्रस्ताव सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में है, वे हां कहें;

जो इसके विरोध में है, वे ना कहें;

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता,

प्रस्ताव पारित हुआ।

खंड-1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक का अंग बन गये।

विधेयक को पारित करना

अध्यक्ष महोदय : अब श्री मनीष सिसोदिया, माननीय उप मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि 'दिल्ली माल आर सेवा कर विधेयक, 2017 (वर्ष 2017 का विधेयक संख्या 03)' को पारित किया जाय।

उप मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन में पुर:स्थापित 'दिल्ली माल और सेवा कर विधेयक, 2017 (वर्ष 2017 का विधेयक संख्या 03)' को पारित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : अब यह प्रस्ताव सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में है, वे हां कहें;

जो इसके विरोध में है, वे ना कहें;

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता,

प्रस्ताव पारित हुआ।

विधेयक पास हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब श्री विशेष रवि, माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत संकल्प सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में है, वे हां कहें;

जो इसके विरोध में है, वे ना कहें;

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता,

प्रस्ताव पारित हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सुश्री राखी बिड़ला, चौ. फतेह सिंह जी प्रस्ताव करेंगे कि 'यह सदन दिनांक 31 मई, 2017 को प्रस्तुत नियम समिति के द्वितीय प्रतिवदन से सहमत हैं।'

सुश्री राखी बिड़ला : अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करती हूं कि यह सदन दिनांक 31 मई, 2017 को प्रस्तुत नियम समिति के द्वितीय प्रतिवदन से सहमत है, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रस्ताव सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में है, वे हां कहें;

जो इसके विरोध में है, वे ना कहें;

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता,

प्रस्ताव पारित हुआ।

अध्यक्ष महोदय : इसके पहले कि मैं सदन को अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित करूं, स्वस्थ संसदीय परम्पराओं का निर्वाह करत हुए सदन के नेता एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, माननीय उप मुख्य मंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी, माननीय सभी मंत्रीगण, श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय नेता प्रतिपक्ष तथा सदन के सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं।

इसके अलावा विधान सभा सचिव तथा सचिवालय के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ-साथ दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव उनके समस्त अधिकारियों, दिल्ली पुलिस, खुफिया एजेंसियों, सीआरपीएफ बटालियन-55 तथा लोक निर्माण विभाग के सिवल, इलैक्ट्रिकल व हार्टिकल्चर डिविजन, अग्निशमन विभाग आदि द्वारा किये गये सराहनीय कार्य के लिये भी उनका धन्यवाद करता हूं।

विधान सभा की कार्यवाही को मीडिया के माध्यम से जन-जन तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाने वाले सभी पत्रकार साथियों का भी मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं।

अब मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे राष्ट्रगान के लिए खड़े हों।

(राष्ट्रगान)

अध्यक्ष महोदय : अब सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित की जाती है। सभी माननीय सदस्यों को बहुत-बहुत धन्यवाद।

(सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित की गई)